चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

07 जुलाई–13 जुलाई 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

विदेशी फंड से संचालित ग़ैर सरकारी संगठन

देश के लिए ख़तरा हैं

सरकार की रिपोर्ट आई है कि विदेशी धन से चलने वाले देशी एनजीओ भारत के आर्थिक विकास के लिए ख़तरा हैं. विकास की परिभाषा क्या है, विकास का सही रास्ता क्या है, विकास के लिए सही नीतियां क्या हैं, यह सब बहस का मुद्दा है. वैसे भी, विदेशी फंड से संचालित एनजीओ को महज आर्थिक ख़तरा बताना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है. विदेशी धन और संगठनों द्वारा संचालित इन एनजीओ का राजनीतिक हस्तक्षेप भारत के प्रजातंत्र और संप्रभुता पर सबसे बड़ा ख़तरा है. ये देश की अखंडता के लिए भी ख़तरा बन सकते हैं. सवाल यह है कि क्या विदेशी धन से चलाए जाने वाले आंदोलनों और संगठनों को देश की राजनीति में हस्तक्षेप करने की छूट दी जा सकती है? क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए द्वारा प्रायोजित संगठनों को देश में राजनीति करने की छूट दी जा सकती है? क्या विदेशी एजेंसियों के पैसों से देश में चुनाव लड़ने की छूट दी सकती है? अगर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित अलगाववादी आंदोलन ग़लत है, अगर नक्सली आंदोलन में चीन के खुफिया विभाग द्वारा भेजे गए पैसों का इस्तेमाल ग़लत है, तो यह कहां तक जायज़ है कि देश में अमेरिका की खुफिया एजेंसी द्वारा भेजे गए पैसों का इस्तेमाल जनांदोलनों में हो, राजनीति में हो और चुनाव में हो? सवाल तो यह है कि विदेशी फंड लेने वाले लोग सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल तक कैसे पहुंच गए? क्या यह मान लिया जाए कि भारत के सर्वोच्च सत्ता संस्थानों में विदेशी एजेंसियों का मिशन पूरा हो चुका है? ऐसे में, सवाल यह है कि केंद्र सरकार सब कुछ जानते हुए भी इस मामले में चुप क्यों रही?

डॉ. मनीष कुमार

ख़ुफिया एजेंसियां और विदेशी ताक़तें दूसरे देशों में हमेशा गुप्त तरीक़े से काम करती हैं. ख़ुफिया एजेंसियां लोगों से अपना काम भी करा लेती हैं और उनके लिए काम करने वालों को यह पता भी नहीं चलता कि वे किसी विदेशी साज़िश का हिस्सा बन चुके हैं. यह तरीक़ा दुनिया की ख़राब से ख़राब खुफिया एजेंसियां अपनाती हैं. फिर अमेरिका, इज़रायल, चीन और दूसरे बड़े देशों की एजेंसियां क्या करती होंगी, यह तो सोचा तक नहीं जा सकता है. दुनिया भर में सामाजिक संगठनों, एनजीओ एवं रिसर्च फाउंडेशन के नाम पर किस तरह साज़िश होती है और लोगों को गुमराह किया जाता है, मैं उसका एक उदाहरण देता हूं. साठ के दशक में अमेरिका में ड्रग्स का फैलाव हुआ. उसने तेज़ी से नौजवानों को अपने जाल में जकड़ना शुरू किया. ड्रग्स यानी नशीली दवाओं के कई प्रकार सामने आए, लेकिन नौजवान उसमें उतनी तेज़ी से नहीं फंसे, जितनी तेज़ी से वहां सक्रिय ताक़तवर ड्रग्स माफिया चाहता था. सरकार भी चेती और उसने सख्ती कर दी. परिणाम स्वरूप ड्रग्स का फैलाव थोड़ा धीमा हो गया. ड्रग्स के कारोबार का विरोध करने के लिए वहां कई सामाजिक संगठन खड़े हो गए. विश्वविद्यालयों और बाज़ारों में होर्डिंग लगाए गए कि ड्रग्स ख़तरनाक है. इसे लेकर वहां सेमिनार होने लगे, जिनके ज़रिये यह बताया गया कि नशीली दवाएं ख़तरनाक हैं और उन्हें लेने वाला सपनों की दुनिया में चला जाता है. थोड़ी देर के लिए वह अपने वर्तमान से कट जाता है और संपूर्ण मुक्ति की अवस्था में पहुंच जाता है. वहां ऐसी भाषा इस्तेमाल की जाने लगी कि सामाजिक व्यवस्था से विद्रोह करने के नाम पर नशीली दवाएं लेना सही नहीं है. ड्रग्स विरोधी आंदोलनकारी यह भी बताते थे कि नशे की गोली या इंजेक्शन लेने पर कैसा महसूस होता है, नशे की गोलियां और इंजेक्शनों का इस्तेमाल किस मात्रा में ज़्यादा ख़तरनाक है. संपूर्ण अमेरिका और यूरोप इन सेमिनारों, सभाओं एवं सम्मेलनों के ज़रिये ड्रग्स के दुष्परिणामों से परिचित हो गया.

वर्ष 1985 में एक नया ख़ुलासा हुआ और पता चला कि तमाम सामाजिक संगठन और रिसर्च फाउंडेशन ड्रग्स माफिया द्वारा संचालित थे. चूंकि ड्रग्स माफिया ने एनजीओ खड़े कर दिए और उन्हें सभाओं एवं सेमिनारों के नाम पर फंड करना शुरू कर दिया, लिहाज़ा उन्होंने ड्रग्स विरोध के नाम पर ड्रग्स का प्रचार शुरू कर दिया. जिन लोगों को ड्रग्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वे भी उससे परिचित हो गए. इस तरह अमेरिका और यूरोप में ड्रग्स का यह कारोबार तीन सौ गुना बढ़ गया. सरकार समझ ही नहीं पाई कि उसकी नाक के नीचे यह ग़ैर क़ानूनी धंधा कैसे बढ़ गया. पुलिस-प्रशासन और राजनीति से जुड़े लोग इन माफियाओं से डरने लगे. यही वजह है कि आज अमेरिका और यूरोप में सरकार के बाद दूसरी बड़ी ताक़त इन ड्रग्स माफियाओं की है. शायद यही कारण है कि इन माफियाओं पर हाथ डालना वहां की सरकारों के वश में भी नहीं है.

कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों, जल-जंगल-ज़मीन के आंदोलनों, लोकपाल आंदोलन और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई किसी विदेशी एजेंसी की साज़िश का हिस्सा हैं? कहीं यह नव-उदारवादी पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए पुराने समाजवादी-प्रजातांत्रिक संस्थानों पर कुठाराघात करने की साजिश तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने-अनजाने में देश के समाजसेवी एवं आंदोलनकारी अमेरिकी पूंजीवाद की साज़िश का हिस्सा बन गए हों और उन्हें पता तक नहीं है? क्या भारत भी इस तरह की साज़िश का शिकार हो गया है? भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर चल रहे आंदोलन स्वत: स्फूर्त हैं या फिर किसी विदेशी खुफिया एजेंसी की साज़िश का हिस्सा हैं? क्या ये सब विदेशी पैसों से चलाए जा रहे हैं? अगर इनका संचालन विदेशी पैसों से हो रहा है, तो यह पैसा कौन दे रहा है? क्या देश में चल रहे एनजीओ और जनांदोलन विदेशी एजेंटों के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या इस देश में आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाना विदेशी साज़िश का हिस्सा है? ये सारे सवाल इसलिए भी उठते हैं, क्योंकि पिछले बीस सालों के दौरान देश में जिन-जिन आंदोलनों का नेतृत्व विदेशी फंड से संचालित एनजीओ ने किया, वे सफल नहीं हुए और बीच रास्ते में ही टूटकर बिखर गए (पूरा विवरण पढ़िए पेज 4 पर). ऐसे कई सवाल हैं, जिन्हें

(शेष पृष्ठ 2 पर)

एनजीओ को राजनीति से दूर रहने की जरूरत है पृष्ठ 3 पर

एनजीओ ने पश्चिम एशिया में अराजकता फैलाई पृष्ठ 3 पर

ऐसे एनजीओ जनांदोलनों के लिए ख़तरा हैं पृष्ठ 4 पर

कई देशों में सत्ता परिवर्तन कर चुका है सीआईए पृष्ठ 5 पर

FORD FOUNDATION

GREENPEACE ग्रीनपीस

actionaid CHANGING LIVES TOGETHER

PUBLIC RESEARCH FOUNDATION Public Cause Research Foundation

घर का डॉक्टर

प्रकृति के अनमोल तत्वों द्वारा तैयार किया गया आयुर्वेदिक तेल
राहत रूह औषधियुक्त जड़ी-बूटियों का सशक्त मिश्रण है।

- सर दर्द
- बदन दर्द
- जोड़ों के दर्द
- सर्दी जुकाम
- जले कटे एवं चर्म रोग
- चक्कर आना (समलवाई)
- दिमाग की कमजोरी
- अनिद्रा में लाभकारी

वर्ष 1881 से निरन्तर सेवा में

हरबंशराम का आयुर्वेदिक तेल

तेल राहत रूह

तिल के तेल से निर्मित

अब पाउच Packing में भी

अन्य उत्कृष्ट उत्पाद

आयुर्वेद रत्न सुपर ठंडा तेल

सकून शुद्धता और गुणवत्ता कलौंजी की

Herbal Shampoo Anti Hair Fall

Rahat Rooh 100% PURE COCONUT OIL

हरबंशराम भगवानदास आयुर्वेदिक संस्थान प्रा.लि.

website:www.harbanshram.com Customer Care No.- 08447 427 621

जनरल मर्चेन्ट एवं केमिस्ट शॉप में भी उपलब्ध

अमित शाह भाजपा के नए खेवनहार ! 05

जदयू के दर्जनों विधायकों पर हार का ख़तरा 07

बाज़ार तय कर रहा है दवाओं के दाम 10

साई की महिमा 12

देश के लिए ख़तरा हैं

पृष्ठ एक का शेष

जानना बेहद ज़रूरी है. ग़ौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कई ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतरे, जो विदेशी फंड की मदद से अपने एनजीओ चलाते हैं. बदलाव के नाम पर उनका एकमात्र मक़सद देश में अस्थिर सरकार बनाने और अराजकता फैलाने का है. फंडिंग के ज़रिये पूरी दुनिया में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की अमेरिका एवं उसकी खुफिया एजेंसी सीआईए की नीति को कल्चरल कोल्ड वार का नाम दिया गया है. राजनीति और सरकारों का एनजीओकरण क्या देश को किसी कल्चरल कोल्ड वार की ओर ले जा रहा है? वास्तव में यहां पर उद्देश्य ग़ैर सरकारी संगठनों की महत्ता, उनके काम या उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा करना नहीं है, बल्कि हमारा मक़सद सिर्फ़ और सिर्फ़ उस ख़तरे से आगाह करना है, जिसे दान के नाम पर देश के भीतर पैदा किया जा सकता है.

वर्ष 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने एक क़ानून बनाया, जिसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. 9 मार्च, 1976 को जब राज्यसभा में यह क़ानून पारित किया जा रहा था, तब बहस के दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का नाम 30 बार लिया गया. इसके अलावा, इस क़ानून के कई ख़तरों से भी अवगत कराया गया. इसी क़ानून के तहत आज देश के सामाजिक संगठनों को विदेशी धन मिल रहा है. पिछले कुछ वर्षों से समाजसेवा के नाम पर धड़ल्ले से विदेशी धन भारत भेजा जा रहा है. इस धन का इस्तेमाल लोगों में असंतोष पैदा करने, आंदोलन करने, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर राजनीतिक वर्ग के ख़िलाफ़ माहौल तैयार करने और राजनीतिक प्रचार-प्रसार में किया जा रहा है. ये गतिविधियां देश की आंतरिक सुरक्षा और एकता के लिए ख़तरनाक हैं. समाजसेवी संस्थाओं के नाम पर इस देश में कौन सा गोरखधंधा चल रहा है, यह सरकार को अच्छी तरह पता है. चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्रालय की तरफ़ से एक बयान आया. यह बयान से ज़्यादा देश के लिए चेतावनी है. गृह मंत्रालय ने ख़ुलासा किया कि भारत में कई ग़ैर सरकारी संगठन हवाला, काले धन के कारोबार और आतंकवादियों को धन मुहैय्या कराने के काम में संलिप्त हैं. गृह मंत्रालय के मुताबिक़, देश में विदेशी धन लेने के लिए अधिकृत एनजीओ की संख्या 43,527 है, जिनमें से 19,000 से ज़्यादा एनजीओ ने अपनी आय और व्यय का ब्यौरा नहीं दिया है. हैरत की बात यह है कि सरकार सब कुछ जानते हुए भी ख़ामोश बैठी रही.

एक रिपोर्ट के मुताबिक़, पिछले तीन वर्षों में ग़ैर सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी फंड की राशि सालाना 11,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है. आश्चर्य की बात यह है कि विदेशी फंड पाने वाले 19,000 एनजीओ अपने फंड का इस्तेमाल देश में कहां, क्यों और किस उद्देश्य से कर रहे हैं, यह सरकार को पता नहीं है. नई सरकार को सबसे पहले इन संगठनों की गतिविधियों पर एक श्वेत पत्र लाना चाहिए. विदेशी धन के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए क़दम उठाने चाहिए. अगर ये संगठन विदेशी पैसों से देश में आंदोलन और परिवर्तन के नाम पर विदेशी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए, देश में अनर्थ हो जाएगा. वैसे शक करने की वजह यह है कि जब अन्ना हज़ारे ने देश में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के लिए जनलोकपाल आंदोलन शुरू किया था, तब इन लोगों ने अपने जन लोकपाल विधेयक के ड्राफ्ट में विदेशी फंड से चलने वाले एनजीओ यानी ग़ैर सरकारी संगठनों एवं सामाजिक संगठनों को जन लोकपाल के दायरे से बाहर क्यों रखा था?

नब्बे के दशक में पहले राजीव गांधी ने और बाद में पीवी नरसिम्हा राव ने अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के साथ ही ग़ैर सरकारी संगठनों को भी देश की नीतियों में पूरी तरह से जगह दे दी. इसी के साथ सिविल सोसायटी एवं ग़ैर सरकारी संगठन देश की व्यवस्था और सरकारी तंत्र में स्थापित होने लगे. पहले ये सामाजिक क्षेत्रों में काम करते थे और फिर धीरे-धीरे इन्होंने देश की आर्थिक नीतियों में अपनी दख़लंदाज़ी शुरू कर दी. नतीजतन, ये सरकार की नीतियों को भी प्रभावित करने लगे. आज ये प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में उतर आए हैं और सत्ता पर क़ाबिज़ होने का ख्वाब देखने लगे हैं. यूपीए सरकार ने इन सामाजिक संगठनों को न सिर्फ़ खाद-पानी दिया, बल्कि इन्हें अपने सिर-माथे पर भी बैठाया. यूपीए की चेयरपर्सन और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार को नीतिगत सुझाव देने के लिए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया. क्या नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सीआईए की साज़िश का हिस्सा बन गई? अब यह पता नहीं कि जानबूझ कर या अनजाने में इस काउंसिल में ऐसे लोगों को शामिल किया गया, जिनका रिश्ता विदेशी फंड से चल रहे सामाजिक संगठनों से था.

अगर यह अमेरिकी खुफिया एजेंसी की साज़िश है, तो इसका मतलब यह है कि भारत सरकार की सबसे शक्तिशाली कमेटी में सीआईए अपने एजेंट बैठाने में क़ामयाब हो गई. इस बात की तहक़ीक़ात होनी चाहिए कि जो लोग नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में शामिल हुए हैं, उनका विदेशी फंड से चलने वाले संगठनों से क्या रिश्ता है? इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि अमेरिका या जर्मनी से इन्होंने अब तक कितने पैसे लिए हैं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिन सामाजिक संगठनों की उत्पत्ति और लालन-पालन विदेशी धन से हो रहा है और जो विदेशी एजेंडे को देश में लागू करने का काम करते रहे हैं, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?

दरअसल, नव-उदारवादी व्यवस्था में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के चरित्र में बदलाव आया है. अब उन्हें सेना भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वे दूसरे देशों में अराजकता फैलाकर, लोगों को आंदोलित करके, नियमों में बदलाव करके और राजनीतिक दबाव बनाकर स्थिति को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम करते हैं. अफ्रीका, लैटिन अमेरिका समेत दुनिया के कई इलाक़ों में ऐसा हो चुका है. कई देश इस तरह की साज़िश से निपटने में नाक़ाम रहे और तबाह हो गए. साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशी ताक़तों ने दुनिया भर में एनजीओ और सामाजिक संगठनों को अपना हथियार बना लिया है. इस मामले में उनकी रणनीति साफ़ है, क्योंकि वे आम लोगों को ही सरकार के ख़िलाफ़ खड़ा कर देते हैं. क्या भारत भी ऐसी किसी साज़िश का शिकार हो गया है? हक़ीक़त यह है कि विदेशी एजेंसियों ने पहले एनजीओ को एक दबाव समूह के रूप में खड़ा किया. इन संगठनों ने भारत में हर जगह निराशा और असंतोष का माहौल तैयार किया. सरकारी तंत्र और देश की व्यवस्था के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काने का काम किया. दरअसल, विदेशी धन से संचालित संगठनों ने ऐसा माहौल पैदा किया, जिससे लोग देश के राजनीतिक नेतृत्व और राजनीतिक सत्ता से घृणा करने लगें. इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीतिक दलों और नेताओं ने भी अपने व्यवहार से इन संगठनों को राजनीतिक वर्ग के ख़िलाफ़ प्रचार करने का एक अच्छा मौक़ा दिया है.

पिछले तीन-चार वर्षों के दौरान दो समानांतर घटनाएं हुईं. एक तो सामाजिक संगठनों को विदेशों से ज़्यादा पैसा मिलने लगा और दूसरे यह कि देश में हर जगह भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गए. रोज़मर्रा की समस्याओं से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए. आंदोलन की सफलता से खुश होकर सामाजिक संगठनों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए दूसरा क़दम उठाया. इन ग़ैर सरकारी संगठनों ने ख़ुद की महत्वाकांक्षा छिपाए रखने के लिए आंदोलनों को ज़रिया बनाया. जब अन्ना आंदोलन हुआ, तो चुनावी राजनीति के नाम पर अन्ना ने ख़ुद को इससे अलग कर लिया और वह आंदोलन की नई राह बनाने में जुट गए. लेकिन, जिनका लक्ष्य आंदोलन के नाम पर अपनी सियासी ज़मीन तैयार करना था, उन्होंने अलग पार्टी बना ली. इस पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़े उम्मीदवारों की सूची देखें, तो पता चलता है कि जिनके संगठन विदेशी धन से संचालित होते हैं, वे सभी लोग इसमें शामिल हैं. एनजीओ की दुनिया का हर बड़ा नाम इस पार्टी में है. हैरानी की बात तो यह है कि जो लोग समाजसेवा के नाम पर सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार समिति में थे, वे भी आज आम आदमी पार्टी के साथ हैं. यही लोग मौजूदा व्यवस्था और राजनीतिक वर्ग के ख़िलाफ़ देश में अराजकता फैलाने की पैरवी करते हैं. मज़ेदार बात यह है कि परिवर्तन के नाम पर देश में जो कुछ हो रहा है, वह फोर्ड फाउंडेशन की वेबसाइट में साफ़-साफ़ लिखा है. कहने का मतलब यह कि ये तमाम सामाजिक संगठन फोर्ड फाउंडेशन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं. हमारे देश में फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों को काफी इज्जत मिलती है, उन्हें अवॉर्ड दिए जाते हैं. जबकि यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि फोर्ड फाउंडेशन अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए की एक शाखा के रूप में काम करती है और वह अमेरिकी विदेश नीति का अहम हिस्सा है. सवाल यह है कि जो लोग और संगठन फोर्ड का एजेंडा देश पर थोपना चाहते हैं, वे दरअसल अमेरिकी विदेश नीति को भारत में लागू करने वाले एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं.

वर्ष 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने एक क़ानून बनाया, जिसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. 9 मार्च, 1976 को जब राज्यसभा में यह क़ानून पारित किया जा रहा था, तब बहस के दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का नाम 30 बार लिया गया. इसके अलावा, इस क़ानून के कई ख़तरों से भी अवगत कराया गया. इसी क़ानून के तहत आज देश के सामाजिक संगठनों को विदेशी धन मिल रहा है. पिछले कुछ वर्षों से समाजसेवा के नाम पर धड़ल्ले से विदेशी धन भारत भेजा जा रहा है. इस धन का इस्तेमाल लोगों में असंतोष पैदा करने, आंदोलन करने, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर राजनीतिक वर्ग के ख़िलाफ़ माहौल तैयार करने और राजनीतिक प्रचार-प्रसार में किया जा रहा है.

वैसे तो देश में हर किसी को राजनीतिक दल बनाने और राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन चिंता तब होती है, जब ये चुनाव तो लड़ते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि उनके पास कोई आर्थिक नीति नहीं है, विदेश नीति नहीं है और रक्षा नीति नहीं है. यह एक ख़तरनाक स्थिति है. ये संगठन वर्तमान व्यवस्था से नाराज़ लोगों का गुस्सा भड़का कर व्यवस्था के ख़िलाफ़ राजनीति को हवा देते हैं. लोग इन्हें समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ये उन्हीं नीतियों और विचारधाराओं को देश में लागू करने लगे, जिनके लिए इन्हें फंड दिया जा रहा है, तो अनर्थ हो जाएगा. कुछ समय पहले एक अंग्रेजी दैनिक ने ख़ुलासा किया था कि ह्यूमैनिस्टिक इंस्टीट्यूट फॉर को-ऑपरेशन विद द डेवलपिंग कंट्रीज (हिवोस) ने गुजरात में अप्रैल 2008 से अगस्त 2012 तक कुछ एनजीओ को 13 लाख यूरो (तक़रीबन 10 करोड़ रुपये) दिए, जिनमें से कुछ चर्चित ग़ैर सरकारी संगठन मसलन, दिशा को दो लाख चौबीस हज़ार यूरो, गुजरात खेत विकास परिषद को दो लाख सात हज़ार यूरो, सफर को एक लाख चौरासी हज़ार यूरो, महिती को एक लाख चार हज़ार यूरो, स्वाति को पचासी हज़ार यूरो और उठान को तिरसठ हज़ार यूरो दिए गए. हिवोस दिल्ली और मुंबई स्थित कई एनजीओ को भी आर्थिक मदद करता है. मुंबई बेस्ड तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा संचालित एनजीओ और शबनम हाशमी के नेतृत्व में संचालित दिल्ली स्थित एनजीओ अनहद को भी हिवोस ने चार हज़ार यूरो दिए. ऐसे में सवाल यह है कि आख़िर यह धनराशि क्यों दी गई?

चुनाव सुधार की दिशा में काम करने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) आईआईएम बंगलुरु के डीन रहे त्रिलोचन शास्त्री के नेतृत्व में चलाई जा रही है. संस्था की वेबसाइट पर कहा गया है कि हमारी कोशिश है कि हम देश में एक पारदर्शी, प्रभावशाली और उत्तरदायी सरकार लाने के लिए लोगों को जागरूक करें. एडीआर को बड़े पैमाने पर फंड फोर्ड फाउंडेशन की ओर से मिलता है. 2009 और 2011 में एडीआर को फोर्ड की ओर से दो-दो लाख डॉलर का फंड मिला था. इसका नतीजा यह है कि हमने इसके जरिये लोकसभा और विधानसभाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया. यह बात सही है कि लोकसभा और विधानसभाओं में अपराधी या जिन पर अपराध का मुक़दमा चल रहा है, वे घुस जाते हैं, लेकिन इसमें सुधार की ज़रूरत है. लेकिन, मीडिया और सामाजिक संगठनों ने एडीआर के रिसर्च के जरिये संसद और विधानसभाओं की विश्वसनीयता को कठघरे में खड़ा कर दिया और राजनीति को ही बदनाम कर दिया. अब जब संसद, विधानसभाओं और जनप्रतिनिधियों पर ही लोगों का भरोसा नहीं होगा, तो क्या देश में प्रजातंत्र बच पाएगा? भारत के प्रजातंत्र पर कुठाराघात सिर्फ़ एडीआर ही नहीं, बल्कि विदेशी फंड से संचालित कई संगठन अपने-अपने तरीके से कर रहे हैं.

क़ानूनी तरीक़े से विदेशी योगदान नियमन क़ानून (एफसीआरए) के तहत देश में आने वाली राशि 1993-94 में 1865 करोड़ रुपये थी, जो 2007-08 में बढ़कर 9,663 करोड़ रुपये यानी पांच गुनी से भी ज़्यादा हो गई. इस क़ानून के तहत पंजीकृत संस्थाओं की संख्या भी इस अवधि में 15,039 से बढ़कर 34,803 यानी दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई. हालांकि इनमें से 46 प्रतिशत संस्थाओं ने 2007-08 में अपना लेखा-जोखा गृह मंत्रालय को नहीं दिया. 2011 में सरकार ने एक महीने में ही 4,139 एनजीओ पर विदेश से किसी प्रकार की सहायता राशि लेने संबंधी रोक लगाई है. इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि 2009-10 में विदेश से आने वाले कुल 10,000 करोड़ रुपये में से अधिकांश रकम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोप से आई थी. गृह मंत्रालय का 42 पृष्ठों का यह विश्लेषण कहता है कि देश में 14,233 एनजीओ ने विदेशी मदद स्वीकार की है और विदेश से इनके लिए आने वाली कुल रक़म 10,337.59 करोड़ रुपये है. मदद के लिए आए इन पैसों का बड़ा हिस्सा (1815.91 करोड़ रुपये) दिल्ली पहुंचा.

इन एनजीओ के पास जो रक़म विदेश से आ रही है, उसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है. उसके बाद जर्मनी और यूके का नंबर आता है. ये तीन देश पिछले कई सालों से एनजीओ की दानदाताओं की सूची में टॉप पर हैं. भारत की ग़रीबी, अशिक्षा एवं स्वास्थ्य को लेकर इन देशों की धार्मिक संस्थाओं के मन में उपजे प्रेम ने गृह मंत्रालय को सतर्क कर दिया है. मंत्रालय यह समझने की कोशिश में जुटा है कि इस मदद का उद्देश्य वास्तव में समाज सेवा ही है या कुछ और? इन तीन देशों के अलावा, भारतीय एनजीओ को कुछ अन्य देशों से भी मदद मिल रही है. मदद करने वाले अन्य देशों में इटली, नीदरलैंड, स्पेन एवं स्विटजरलैंड आदि शामिल हैं. इसके साथ ही कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एवं यूएई भी भारतीय ग़ैर सरकारी संगठनों के बड़े मददगारों में शामिल हैं. सूचना का अधिकार क़ानून के तहत मांगी गई एक जानकारी के मुताबिक़, कबीर को 2007 से लेकर 2010 तक फोर्ड फाउंडेशन से 86,61,742 रुपये मिले हैं. इतना ही नहीं, कबीर को डच दूतावास से भी पैसे मिले हैं. आख़िर किसी दूसरे देश का दूतावास हमारे देश के किसी ग़ैर सरकारी संगठन को पैसा क्यों दे रहा है? डच दूतावास की गतिविधियों को भारत में हमेशा शक की निगाह से देखा गया है.

दरअसल, आज भारत कई तरह के ख़तरों के मुहाने पर खड़ा है. लोगों में सरकारी तंत्र के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त गुस्सा है. यह एक नाज़ुक स्थिति है. सरकारी तंत्र में लोगों का विश्वास बढ़े, यह राजनीतिक वर्ग का पहला काम होना चाहिए, अन्यथा भारत विरोधी ताक़तों को मौक़ा मिल जाएगा. रही बात ग़ैर सरकारी संगठनों की, तो उनका कार्यक्षेत्र निर्धारित करना ज़रूरी है. ये संगठन सामाजिक क्षेत्र में काम करें. इन्हें शिक्षा, रोज़गार, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास आदि क्षेत्रों में काम करने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था से जुड़े सवालों पर विदेशी फंड से चलने वाले एनजीओ पर प्रतिबंध लगना चाहिए. प्रशासनिक, न्यायिक, विदेश नीति, सुरक्षा नीति एवं चुनाव सुधार जैसे गंभीर मुद्दों पर विदेशी एजेंसियों और उनके एजेंटों को शामिल करना देश के लिए ख़तरनाक है. इसमें कोई शक नहीं कि विदेशी फंड से संचालित एनजीओ विदेशी एजेंट हैं. ये एनजीओ उन्हीं देशों के एजेंडों को लागू करने पर आमादा रहते हैं, जिनसे ये पैसा लेते हैं. केंद्र में बनी नई सरकार की यह प्राथमिकता होनी चाहिए कि वह ऐसा क़ानून बनाए, जिससे भारत में विदेशी फंड के इस्तेमाल पर रोक लगे या उसमें पारदर्शिता आ सके और जवाबदेही तय हो सके. नई सरकार को उन ग़ैर सरकारी संगठनों के नाम भी सार्वजनिक करने चाहिए, जो विदेशी एजेंसियों से पैसा लेकर आंदोलन और राजनीति करते हैं. यह देश के लोगों का अधिकार है कि वे जान सकें कि किन-किन लोगों ने विदेशी एजेंट बनकर देश का सौदा किया है.■

manishbph244@gmail.com

फोटो- *प्रभात पाण्डेय*

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 18
दिल्ली, 07 जुलाई-13 जुलाई 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय
संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

> एनजीओ का मूल काम स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में सहयोग करने और जनजागरूकता फैलाने का है, वो उससे हटकर क्या राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं या होना चाहिए? क्या ऐसे एनजीओ को क्या काम करने देना चाहिए जो पैसा तो विदेशों से लेते है लेकिन देश के भीतर अराजकता का माहौल पैदा करते है.

एनजीओ को राजनीति से दूर रहने की ज़रूरत है

शशि शेखर

एक वक्त था, जब अपराधियों के सहारे कई नेता चुनाव जीतते थे. बाद में इन अपराधियों को लगा कि जब वे किसी को चुनाव जीता सकते हैं, तो ख़ुद क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते हैं. इस तरह पहले अपराध का राजनीतिकरण हुआ और अब राजनीति का ही अपराधीकरण हो चुका है. कुछ इसी तरह का किस्सा देश में संचालित लाखों ग़ैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भी है. नब्बे के दशक से लागू आर्थिक उदारीकरण के बाद देश में अचानक एनजीओ की संख्या बढ़ने लगी. सरकार की तरफ से और विदेशों से पैसे आने का ज़बरदस्त सिलसिला भी शुरू हुआ. एनजीओ की अवधारणा इस उद्देश्य के साथ लाई गई थी कि, इससे सरकार के कार्यों को ज़मीन तक ले जाने में इसकी भूमिका होगी और साथ ही कई ऐसे सेक्टर में काम करेगी जहां सरकार सीधे-सीधे नहीं पहुंच पाती. वैसे एनजीओ के पीछे एक और सरकारी अवधारणा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके राजनीतिक कारण भी हैं. सरकारों ने हमेशा से इन एनजीओ को सेफ्टी वॉल्व (सुरक्षा कवच) के तौर पर इस्तेमाल किया है. उदारीकरण से उपजे सामाजिक-आर्थिक असंतुलन को कम करने के लिए सरकारों ने इन एनजीओ का इस्तेमाल किया. स्थानीय स्तर पर शुरू हुए कई ऐसे जनांदोलन देखे गए हैं, जिनका नेतृत्व एनजीओ ने किया. हालांकि अंत में उन आंदोलनों का काफ़ी बुरा हश्र हुआ. यह सही है कि देश में कई अच्छे क़ानून इन्हीं एनजीओ के प्रयासों से बने. मसलन, सूचना का अधिकार कानून. अगर जल, जंगल और ज़मीन से जुड़े आंदोलनों जैसे, कुडनकुलम, महान संघर्ष और एकता परिषद की अधिकार यात्रा पर नज़र डालें, तो ये सभी आंदोलन अंत में असफल रहे. ग़ौरतलब है कि ये तमाम आंदोलन किसी न किसी एनजीओ की मदद से ही चलाए जाते रहे हैं. ऐसे में यह शक और गहरा होता है कि कहीं न कहीं ये एनजीओ सरकार के हित में ही एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करते हैं. हालांकि, अब इन एनजीओ की भूमिका बदल रही है. कल तक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होते रहे ये एनजीओ अब ख़ुद राजनीति में कूद चुके हैं. लोकसभा चुनाव 2014 इसका जीता-जागता उदाहरण है, क्योंकि इस चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में एनजीओ से जुड़े लोगों ने शिरकत की. ये अलग बात है कि इन्हें हार का सामना करना पड़ा. एसपी उदय कुमार (कुडनकुलम आंदोलन) और मेधा पाटेकर (एनएपीएम) जैसे एनजीओ जगत के बड़े नाम आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पडा. इसके अलावा, और भी कई ऐसे उम्मीदवार थे, जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एनजीओ से रिश्ता रहा है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी ख़ुद बनारस से नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ चुनाव मैदान में थे. जैसा कि सभी जानते हैं कि उनका रिश्ता भी एनजीओ से है. बहरहाल, एनजीओ से जुड़े लोगों का चुनाव लड़ने पर कोई क़ानूनी रोक तो नहीं है, लेकिन जिस तरीक़े से इन पर विदेशी धन लेने और एनजीओ को मिले पैसे का चुनाव में इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है, उससे एक नैतिक सवाल के साथ-साथ कई क़ानूनी सवाल भी उठते है. अगर किसी मामले में यह सावित होता है कि एनजीओ या किसी अन्य पेशे से जुड़ा कोई शख्स विदेश से अनुदान के रूप में मिले पैसे से चुनाव लड़ता है या विदेशी अनुदान से संचालित कोई एनजीओ चुनाव लड़ रहे व्यक्ति की मदद करता है, तो यह निश्चित रूप से एक गंभीर मामला बन जाता है. इस चुनाव के दौरान यह ख़बर भी आई कि बस्तर से चुनाव लड़ रही सोनी सोरी की मदद के लिए सैकड़ों एनजीओ आगे आए थे.

ऐसे में सवाल यह है कि एनजीओ का मूल काम, यानी स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में सहयोग करने और जन जागरूकता फैलाना है, वे उससे हटकर क्या राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं या होने चाहिए? क्या ऐसे एनजीओ को काम करने की इज़ाज़त देनी चाहिए, जो पैसा तो विदेशों से लेते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल देश के भीतर अराजकता पैदा करने के लिए करते हैं? आईबी की हालिया रिपोर्ट यह बताती है कि ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, जहां जंगलों और उनसे जुड़े संसाधनों के व्यावसायिक दोहन के ख़िलाफ़ हिंसक संघर्ष हो रहे हैं, नर्मदा और अनेक नदियों के मुद्दे पर आदिवासी और राज्य सरकारें आमने-सामने हैं. इस आंदोलन को हवा देने का आरोप वहां सक्रिय एनजीओ पर लगते रहे हैं. इनमें बहुत सारे संगठनों को विदेशी धन मिलता है. ज़ाहिर है ऐसे एनजीओ की कार्यप्रणाली पर सवाल ज़रूर खड़े होंगे. इसके अलावा, इस देश में प्रत्येक 600 आदमी पर एक एनजीओ है, लेकिन ज़मीन पर काम करने वाले एनजीओ की संख्या इसके मुक़ाबले कहीं कम है.

निश्चित रूप से मौजूदा समय में एनजीओ एक धंधा के रूप में तब्दील हो चुका है. ग्रीन पीस पर आईबी की हालिया रिपोर्ट इसकी सबसे अच्छी मिसाल है. पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाने का दावा करने वाले एनजीओ ग्रीनपीस पर इंटेलीजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में यह ख़ुलासा हुआ है कि हालिया लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को भी एनजीओ ने धन मुहैया कराया था. आईबी ने मध्यप्रदेश के सीधी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे आप प्रत्याशी पंकज सिंह की

जानकारी निकालनी शुरू कर दी है. आप प्रत्याशी पंकज सिंह सितंबर 2012 से फरवरी 2013 तक ग्रीनपीस संस्था के साथ जुड़े रहे थे. पंकज इस संस्था में बतौर कंसलटेंट काम करते थे और मध्यप्रदेश में ग्रीनपीस के आंदोलन के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करते थे. हालांकि, आम आदमी पार्टी ने इस मामले में सफाई दी है कि पंकज सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले ही एनजीओ से इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन आईबी ने स्थानीय ज़िला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और स्टेट इंटेलीजेंस ब्यूरो से भी आप उम्मीदवार का ब्योरा मांगा है. बहरहाल, एनजीओ की बदलती भूमिका को देखते हुए यह ज़रूरी हो जाता है कि इसकी नई भूमिका की जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम विदेशी फंड या देशी फंड भी लेने वाले एनजीओ को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा जा सके. ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

विदेशी फंड द्वारा संचालित एनजीओ ने

पश्चिम एशिया में अराजकता फैलाई

शफीक आलम

अरब स्प्रिंग या अरब बहार क्रांति की शुरुआत दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया से हुई और देखते ही देखते यह उत्तरी अफ्रीका और अन्य अरब देशों फैल गई थी. कमोबेश इसे लेकर सभी अरब देशों में विरोध प्रदर्शन भी हुए. उन दिनों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए. इस आंदोलन ने कई दशकों से सत्ता पर काबिज़ कई हुक्मरानों को सत्ता से बेदख़ल कर दिया. कई देशों में यह प्रदर्शन अहिंसात्मक और साधारणत: शांतिपूर्ण रहे, लेकिन कई देशों में यह उग्र रूप धारण कर लिया और वहां गृहयुद्ध की स्थिति बन गई. नतीजतन लीबिया और सीरिया जैसे ख़ुशहाल देश भी गृहयुद्ध की चपेट में आ गए. सीरिया में तो हिंसा का जो दौर तीन साल पहले शरू हुआ था, वह आज भी जारी है, लेकिन मिस्र जहां फ़ौज के साए में परवान चढ़ रहे तानाशाही का ख़ात्मा तो हुआ और लोकतंत्र की स्थापना भी हुई, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से चुनकर आई सरकार का तख्ता पलट कर फ़ौज एक बार फिर सत्ता पर काबिज़ हो गई. हालांकि, ज़्यादातर राजनीतिक समीक्षकों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस आंदोलन को निरंकुश तानाशाहों के विरुद्ध जनता का स्वत:स्फूर्त आक्रोश का नतीजा क़रार दिया था, लेकिन बाद की मीडिया रिपोर्टों से ज़ाहिर हुआ कि इस आदोलन का संचालन विदेशी फंड से चलने वाले ग़ैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने किया था, जिन्हें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की पूरी सहायता प्राप्त थी.

पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में सिविल सोसाइटी के विकास के लिए विदेशी फंडिंग (ख़ास तौर पर अमेरिकी और यूरोपीय फंडिंग) वर्ष 1995 से शरू हुई थी, जिसका मकसद था यूरोप और भू-मध्यसागर के आस-पास के देशों के बीच संबंध मज़बूत करना. वैसे अरब-इज़राइल वार्ता में गतिरोध के कारण इस अभियान में कोई ख़ास तरक्की नहीं हो सकी, लेकिन वर्ष 2001 के बाद डायलॉग ऑफ पीपुल प्रोग्राम के तहत यूरोपीय यूनियन ने उत्तरी अफ्रीकी और मध्य एशियाई देशों के महिला संगठनों, ट्रेड यूनियनों, अधिवक्ता एसोसिएशनों, छात्रों, मानवाधिकार संगठनों, पत्रकारों, लेखकों, कलाकारों, युवाओं के बीच आपसी नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए करोड़ों यूरो की सहायता दी. उसी तरह अमेरिका के नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, एएफएल-सीआईओ और फ्रीडम हाउस जैसी संस्थाओं ने सिविल सोसाइटी के निर्माण के नाम पर इस क्षेत्र के देशों के एनजीओ को करोड़ों डॉलर की फंडिंग मुहैया कराई थी. नतीजतन ये संस्थाएं इस पूरे क्षेत्र में फलने-फूलने लगीं और क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक और राष्ट्रीय दूरी के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़ने लगीं. मज़े की बात यह है कि यहां के तानाशाहों और सरकारों ने इन संगठनों से उस समय कोई ख़ास ख़तरा महसूस नहीं किया और जब ख़तरा महसूस हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी.

जहां तक अरब क्रांति में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाने वाले एनजीओ के विदेशी कनेक्शन का सवाल है, तो इस संबंध में वर्ष 2011 से ही मीडिया में रिपोर्टें आने लगीं थीं. इन रिपोर्टों से यह ज़ाहिर होता है कि अमेरिका का लोकतंत्र बहाली अभियान और यूरोपीय यूनियन ने इन एनजीओ की मदद कर अरब स्प्रिंग आंदोलनों को हवा देने में अहम भूमिका निभाई थी. इस आंदोलन में शामिल प्रमुख नेताओं जैसे इंतेसार अल-क़ाज़ी को अमेरिका में ट्रेनिंग दी गई और जीओ 6 अप्रैल यूथ मूवमेंट (मिस्र), बहरीन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स जैसे एनजीओ की फंडिंग इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट और फ्रीडम हाउस जैसी संस्थानों की तरफ़ से की गई थी. इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट और नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट क्रमश: रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों से जुड़ी संस्थाएं हैं, जिनकी फंडिंग वर्ष 1983 में वजूद में आए नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के द्वारा होती है. नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी (एनइडी) का सालाना बजट लगभग 10 करोड़ डॉलर है, जिसे अमेरिकी कांग्रेस मुहैया कराती है. फ्रीडम हाउस के बजट का बड़ा हिस्सा भी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट (गृह मंत्रालय) से आता है. इन संस्थानों से फंडिंग प्राप्त करने वाले संगठनों में ट्यूनीशिया की लेबर यूनियन मूवमेंट, यूरो-मेडिट्रेनियन ह्यूमन राइट्स नेटवर्क, ट्यूनीशियन लॉयर एंड मजिस्ट्रेट एसोसिएशन, बहरीन की बहरीन यूथ सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स, यमन की वीमेन जर्नलिस्ट विदआउट चेन और अरब सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स इत्यादि एनजीओ शामिल हैं.

इसमें कोई शक नहीं कि अरब स्प्रिंग आंदोलन में स्थानीय लोग ही शामिल थे. अगर लीबिया को छोड़ दिया जाए, तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन यह सच्चाई का एक पहलू है. अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इस आंदोलन में शामिल एनजीओ की आर्थिक और लॉजिस्टिक सहायता कर परोक्ष रूप से अपना सहयोग दे रहे थे. हालांकि प्रोजेक्ट ऑन मिडिल ईस्ट डेमोक्रेसी जैसी संस्थाएं यह कहती हैं कि उसने इन आंदोलनों को शुरू कराने के लिए फंडिंग नहीं की, अलबत्ता आंदोलनकारियों के कौशल विकास और नेटवर्किंग में सहायता कर इस क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका ज़रूर निभाई. वैसे कई एनजीओ के नुमाईंदों और प्रभावित देशों के नेताओं ने वर्ष 2008 में न्यूयॉर्क में होने वाले टेक्नॉलजी मीटिंग में सोशल नेटवर्किंग और मोबाइल टेक्नॉलजी के ज़रिए लोकतंत्र लाने की ट्रेनिंग हासिल की थी, जो उनके इस दावे की कलई खोल देते हैं. इस मीटिंग को फेसबुक, गूगल और एमटीवी ने भी प्रायाजित किया था.

अगर किसी देश में कोई आंदोलन (चाहे वह लोकतंत्र की बहाली के लिए ही क्यों न हो) जब विदेशी फंडिंग द्वारा चलाए जा रहे एनजीओ के तत्वाधान में चल रहा हो, तो उस एनजीओ से फंडिंग हासिल करने वाले देशों के हितों की अनदेखी की आशा कैसे की जा सकती है? भले ही वे संगठन लाख दावे करें कि उनका अमेरिका और यूरोपीय ताक़तों से फंड लेना और सहायता हासिल करना एक रणनीति का हिस्सा है. जिस तरह ये ताक़तें हमें धन उपलब्ध करा रहीं हैं, उसी तरह ये उन शासकों को भी संरक्षण दे रही हैं, जिनके ख़िलाफ़ हम आंदोलन कर रहे हैं. लोकतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कोई नई बात नहीं है. दरअसल, यह अमेरिकी विदेश नीति का एक हिस्सा है. इस काम के लिए अमेरिका प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई के साथ- साथ दूसरे माध्यमों का भी प्रयोग करता है, ताकि उसके लिए सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश या क्षेत्र में अस्थिरता पैदा की जा सके. इराक और अफ़ग़ानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप की विफलता और अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने अपना हित साधने के लिए अब दूसरे माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं. इसके तहत एनजीओ की सहायता से किसी देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर वहां अस्थिरता की स्थिति पैदा करना है.

ऐसे में सवाल यह है कि अरब स्प्रिंग के बाद अरब दुनिया में फैली अराजकता के लिए दोषी कौन है? मिस्र में हुई हज़ारों लोगों की मौत की ज़िम्मेदारी किसके सर है? सीरिया और लीबिया की बर्बादी का ज़िम्मा कौन लेगा? ज़ाहिर है इसके लिए यूरोपीय और अमेरिकी मदद से चलाए जा रहे एनजीओ सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं. अगर पश्चिम एशिया में इन एनजीओ की क्रियाकलापों पर नज़र डालें, तो यह पूरी तरह अमेरिकी विदेश नीति के विस्तार का हिस्सा ही नज़र आते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अनिल पाठक का 01 फरवरी,2014 के बाद से चौथी दुनिया से कोई संबंध नहीं है, न ही वह यहां कार्यरत हैं. कुछ सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि अनिल पाठक चौथी दुनिया के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को तरह-तरह के प्रलोभन देकर गुमराह कर रहे हैं. अनिल पाठक चौथी दुनिया के नाम से किसी तरह का प्रलोभन देकर किसी तरह का लेन-देन करते हैं तो इसके लिए चौथी दुनिया प्रबंधन किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा.

चौथी दुनिया
अंकुश पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, उत्तरप्रदेश

> भारत में जब भी आंदोलनों की बात हुई है, तो हमारे जेहन में छात्र, नौजवान, किसान, मज़दूर और छोटे–मोटे सरकारी कर्मचारियों के धरने–प्रदर्शन और हड़ताल से जुड़ीं धुंधली तस्वीर उभरने लगती हैं. सत्तर और अस्सी के दशक में महंगाई, बेरोज़गारी और ग़ैर बराबरी की पृष्ठभूमि में कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जो अपने दौर की सफल फिल्मों में रही हैं.

ऐसे एनजीओ जनांदोलनों के लिए ख़तरा हैं

इस देश में ग़ैर सरकारी संगठनों के बारे में जितनी चर्चाएं होनी चाहिए, अफ़सोस! उतनी नहीं हो रही हैं. क्या एनजीओ को शामिल किए बग़ैर आंदोलन सफल नहीं हो सकता? क्या आंदोलनों को नुक़सान पहुंचाने में एनजीओ की कोई भूमिका है? क्या एनजीओ किसी स्वतंत्र नागरिक आंदोलन में घुसपैठ कर पूरे अभियान को हाईजैक कर लेते हैं? ऐसे कई सवाल हैं, जिनके बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं है. इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है, उसके बाद विदेशी चंदे से संचालित एनजीओ की भूमिका पर प्रश्नचिन्ह लग गया है.

अभिषेक रंजन सिंह

ग्रीन पीस इंडिया जैसे ग़ैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के संबंध में इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की हालिया रिपोर्ट ने देश में विदेशी अनुदान से संचालित स्वयंसेवी संस्थाओं की कार्य प्रणाली को लेकर एक बहस की शुरुआत कर दी है. इस बहस में दो खेमे स्पष्ट रूप से नज़र आ रहे हैं. एक जो ग़ैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर किसी तरह के सवाल उठाए जाने के सख्त ख़िलाफ़ है. दूसरा, जो यह चाहता है कि मौजूदा परिपेक्ष्य में विदेशी अनुदान के ज़रिये देश में चल रहे अनगिनत ग़ैर सरकारी संगठनों के कार्यों और उनके मक़सद के बारे में विस्तृत चर्चा हो. मैं स्वयं इस दलील से सहमत हूं कि भारत में सक्रिय एनजीओ के बारे में चर्चा और बहस होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में आज भी एनजीओ को लेकर ज़्यादातर लोगों में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है. अधिकांश लोग यह समझते हैं कि देश में सक्रिय एनजीओ का एकमात्र और अंतिम अर्थ समाजसेवा है. यही कारण है कि लोगों को एनजीओ से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है. लाखों की संख्या में मौजूद एनजीओ देश और समाज के विकास में सहायक हैं या अवरोध पैदा कर रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है. विदेशों से मिलने वाले अनुदान का उपयोग समाज की भलाई के लिए हो रहा है या उसका फ़ायदा एनजीओ से जुड़े चंद लोग ही उठा रहे हैं?

भारत में जब भी आंदोलनों की बात हुई है, तो हमारे जेहन में छात्र, नौजवान, किसान, मज़दूर और छोटे–मोटे सरकारी कर्मचारियों के धरने–प्रदर्शन और हड़ताल से जुड़ीं धुंधली तस्वीर उभरने लगती हैं. सत्तर और अस्सी के दशक में महंगाई, बेरोज़गारी और ग़ैर बराबरी की पृष्ठभूमि में कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जो अपने दौर की सफल फिल्मों में रही हैं. बंबई, कलकत्ता और मद्रास (पूर्व नाम) की सड़कें आंदोलनकारियों से अटी पड़ी रहती थीं. दीवारों पर अपने हक़ के लिए दो–दो पंक्तियों के नारे लिखे जाते थे. यह वह दौर था, जब किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को, किसी कारख़ाने में काम करने वाले मज़दूरों को और ज़मींदारों की भूमि पर काम करने वाले खेतिहर मज़दूरों को उनके आंदोलनों के लिए किसी एनजीओ से आर्थिक मदद नहीं मिलती थी और न विदेशी संस्थानों से उन्हें कोई धन मिलता था. अपनी ज़ायज मांग की ख़ातिर संघर्ष करने वाले वे लोग एक स्वतंत्र संगठन बनाते थे और आपस में एक–एक पैसा बतौर चंदा इकट्ठा करके पर्चा, पोस्टर और बैनर बनाते थे. हड़ताल होने की स्थिति में कारख़ानों में काम करने वाले मज़दूर गलियों और मोहल्ले में घूम–घूम कर भिक्षाटन करते थे. देश में कई ऐसे आंदोलन हुए हैं, जो इसी तरह के सामाजिक सहयोग की वजह से सफल हुए. वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद देशी और विदेशी पैसों की मदद से आंदोलन चलाने के पक्ष और विपक्ष में बातें होने लगीं. समाजवादी नेता किशन पटनायक ने वर्ष 1980 में समता संगठन की स्थापना की. जदयू के पूर्व नेता शिवानंद तिवारी इसके प्रथम संयोजक थे. किशन पटनायक जैसे नेताओं का मानना था कि देश में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन जनता के पैसों से ही चलने चाहिए. अगर जनांदोलनों में विदेशी पैसों का इस्तेमाल होगा, तो आंदोलन अपनी दिशा और उद्देश्य से भटक जाएगा.

दरअसल, नब्बे के दशक में लागू हुईं नई आर्थिक नीतियों के बाद देश में आंदोलनों को ख़त्म करने की साज़िश हुई. निश्चित रूप से इस साज़िश का शिकार हमारे देश की न्यायपालिका भी हुई. कुछ वर्ष पहले उच्चतम न्यायालय ने हड़ताल को जिस तरह ग़ैर संवैधानिक क़रार दिया, उसे इस संदर्भ में जोड़कर देखा जा सकता है. इस फ़ैसले के बाद सरकारी और निजी क्षेत्रों के कल–कारख़ानों में मज़दूरों की उठने वाली आवाज़ों को ख़ामोश कर दिया गया. निजी क्षेत्रों की कंपनियों में श्रमिकों को न्यूनतम मज़दूरी भी नहीं दी जाती है, बावजूद इसके उन्हें आंदोलन करने और यूनियन बनाने की इज़ाज़त नहीं है. गांवों में रहने वाले खेतिहर मज़दूरों और छोटे किसानों की हालत भी कमोबेश ऐसी ही है. कृषि उपज की सही क़ीमत न मिलने से किसान क़र्ज़ के बोझ तले दबे जा रहे हैं. ग़रीबी और तंगहाली से परेशान किसान कोई आंदोलन करते हैं, तो प्रशासन उन पर लाठियां और गोलियां चलाता है. देश में कई बार किसानों पर हुई फायरिंग की घटनाएं इस बात की गवाह हैं.

सत्तर और अस्सी के दशक में विश्वविद्यालयों में छात्रसंघों की एक बड़ी भूमिका होती थी. उस वक्त देश में निजी शैक्षणिक संस्थानों की कोई ख़ास सुगबुगाहट नहीं थी. महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ के चुनाव नियमित कराए जाते थे. चुनाव में जीतने वाले छात्र नेताओं को विश्वविद्यालयों के सीनेट और सिंडीकेट में शामिल किया जाता था. कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नियमित कक्षाएं संचालित हों, शैक्षणिक शुल्क में अनावश्यक वृद्धि न हो, इसे लेकर छात्र नेता काफ़ी सजग रहते थे. जिन विश्वविद्यालयों में इसकी अनदेखी होती थी, वहां के छात्र नेता सड़कों पर उतर कर विरोध–प्रदर्शन करते थे. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों की मांगों की अनदेखी करने पर छात्र बेमियादी अनशन पर भी बैठ जाते थे. ज़ाहिर है, इन सबके लिए छात्र नेताओं को पैसे की दरकार होती थी, लेकिन पैसों का इंतज़ाम वे लोग आपस में चंदे के जरिये करते थे. उनके आंदोलनों में किसी पूंजीवादी संगठन की कोई भूमिका नहीं होती थी.

छात्रों, नौजवानों, किसानों और मज़दूरों के संघर्ष की यह आदर्श स्थिति तीन–चार दशक पहले की बात थी. वर्ष 1990 यानी नव–उदारवादी नीतियों के बाद हालात काफ़ी बदल चुके हैं. इस दौरान बड़े पैमाने पर सरकारी कल–कारख़ानों को निजी कंपनियों के हाथों बेच दिया गया, तो कई फैक्ट्रियों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया. नतीजतन, वहां काम करने वाले मज़दूरों को निजी क्षेत्र की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए विवश होना पड़ा, जहां उन्हें अपनी ज़ायज मांगों की ख़ातिर संघर्ष करने का कोई अधिकार नहीं है. नब्बे के दशक के बाद देश में निजी उच्च शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना होने लगी. शिक्षा माफियाओं ने सबसे पहले सरकार के साथ मिलकर विश्वविद्यालयों में होने वाले छात्रसंघ चुनावों पर पाबंदियां लगवाईं, ताकि उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ न उठा सके. कुछ राज्यों को छोड़ दें, तो देश में अधिकांश विश्वविद्यालयों में कई वर्षों से छात्रसंघ के चुनाव लंबित हैं. निजी उच्च शैक्षणिक संस्थान अपनी मर्ज़ी से फीस बढ़ाते हैं, लेकिन उसके विरोध में कोई आवाज़ नहीं उठती. सरकारी विश्वविद्यालयों ने भी पिछले दस वर्षों में फीस में कई गुना अधिक बढ़ोत्तरी की है, लेकिन वहां इक्के–दुक्के छात्र संगठनों को छोड़कर किसी में विरोध करने का साहस नहीं रह गया है. दरअसल, ये तमाम विसंगतियां नब्बे के दशक में लागू हुईं नई आर्थिक नीतियों के बाद पैदा हुई हैं.

नब्बे के दशक से पहले देश के किसान अपनी कृषि उपज की सही क़ीमत पाने के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन पिछले चौबीस वर्षों से लाखों किसान अपनी ज़मीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. देश में आर्थिक विकास के नाम पर हर साल सैकड़ों परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है. दुर्भाग्य की बात यह है कि इनमें सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की संख्या न के बराबर है. बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए ज़मीन चाहिए और यह ज़मीन उन्हें बग़ैर सरकारी मदद के नहीं मिलती. केंद्र और राज्य सरकारें सार्वजनिक मक़सद के नाम पर किसानों की ज़मीन अधिग्रहीत करती हैं. कहीं आसानी से, तो कहीं काफ़ी विरोध के बाद सरकार निजी कंपनियों के लिए ज़मीन हासिल करने में सफल हो रही हैं. आज भी कई राज्यों में किसानों और प्रशासन के बीच खूनी संघर्ष जारी है और हर साल दर्जनों किसान पुलिस की गोलियों के शिकार हो रहे हैं. जल, जंगल और ज़मीन बचाने की इस मुहिम में किसानों और आदिवासियों का संघर्ष पिछले कई वर्षों से चल रहा है. हालांकि, किसानों और वंचितों की इस लड़ाई में आज वैसे ग़ैर सरकारी संगठन (एनजीओ) भी शामिल हैं, जिन्हें विदेशी संस्थानों से हर साल करोड़ों रुपये का अनुदान मिलता है. यहां सवाल यह है कि आख़िर जल, जंगल और ज़मीन बचाने के लिए जारी किसानों और आदिवासियों के स्वतंत्र आंदोलन में ग़ैर सरकारी संगठन (एनजीओ) इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं?

यह एक ऐसा सवाल है, जिसका उत्तर ख़ुद एनजीओ कर्मियों के पास नहीं है. मैं पिछले एक साल के दौरान देश के उन सभी स्थानों पर गया, जहां जल, जंगल और ज़मीन बचाने के लिए किसानों और आदिवासियों का संघर्ष चल रहा है. एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते मैंने महसूस किया कि वे सभी बड़े आंदोलन, जिनमें विदेशी धन से संचालित एनजीओ की घुसपैठ हुई है, धीरे–धीरे अपने मूल मक़सद से भटक गए और उस आंदोलन में शामिल ज़मीनी कार्यकर्ताओं को एनजीओ ने हाशिये पर ढकेल दिया. तमिलनाडु के तिरुनेवेल्ली ज़िले का कुडनकुलम आंदोलन इसका एक बेहतर उदाहरण है. पीपुल्स मूवमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी के तत्वावधान में पिछले कुछ वर्षों से यहां आंदोलन चल रहा है. इस आंदोलन की अगुवाई डॉ. एस पी उदय कुमार कर रहे हैं. कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस की मदद से निर्मित हुआ है. ज़ाहिर है, यहां लगने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर रूस से ही ख़रीदे गए हैं. डॉ. एस पी उदय कुमार पर शुरू से आरोप लगते रहे हैं कि उनके एनजीओ को पश्चिमी देशों से वित्तीय मदद मिलती है, क्योंकि वहां की न्यूक्लियर एनर्जी लॉबी चाहती है कि भारत में लगने वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उनके रिएक्टर लगाए जाएं, ताकि उनके देशों की कंपनियों को इससे आर्थिक लाभ हो. हालांकि, डॉ. एस पी उदय कुमार इन आरोपों को सिरे से ख़ारिज़ करते हैं. इंटेलिजेंस ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट आने के बाद इस तरह के आंदोलनों पर सवाल उठना लाज़िमी है. पीपुल्स मूवमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी संगठन को तूतीकोरीन मल्टीपरपस सोशल सर्विस सोसायटी (टीएमएसएसएस) और तूतीकोरीन डायओशन एसोसिएशन (टीडीए) द्वारा आर्थिक मदद की जा रही है. इस बात का ख़ुलासा इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में भी किया है. उक्त रिपोर्ट के मुताबिक़, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेग्युलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत टीएमएसएसएस को वर्ष 2008–09 में 10.97 और वर्ष 2012–13 में 5.26 करोड़ रुपये का विदेशी अनुदान मिला. उसी तरह टीडीए को पिछले पांच वर्षों में 19.18 करोड़ रुपये का विदेशी अनुदान प्राप्त हुआ. इस एनजीओ को यह रक़म जर्मनी, इटली और फ्रांस से मिली है. ग़ौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली उत्पादन की मंजूरी पिछले साल दी थी. उसके बाद यहां बिजली उत्पादन भी शुरू हो गया है, लेकिन आंदोलन के गढ़ कहे जाने वाले इदिंथकरई के निवासियों का आंदोलन अभी भी चल रहा है. वहीं इस आंदोलन के शीर्ष नेता डॉ. एस पी उदय कुमार ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर कन्याकुमारी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें क़रारी हार का सामना करना पड़ा.

एक दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन है नियमगिरि का. पिछले साल उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि ओडिशा के रायगढ़ा और कालाहांडी ज़िले में नियमगिरि की पहाड़ियों पर ब्रितानी कंपनी वेदांता को बॉक्साइट खनन की अनुमति मिले अथवा नहीं, यह फ़ैसला नियमगिरि की पहाड़ियों पर बसे डोंगरिया कोंध आदिवासी करेंगे. उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद ओडिशा सरकार ने उन बारह गांवों में पल्ली सभा (ग्राम सभा) का आयोजन कराया, जहां डोंगरिया कोंध आदिवासी रहते हैं. रायगढ़ा के ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश के पर्यवेक्षण में ये पल्ली सभाएं आयोजित की गईं. सभी बारह पल्ली सभाओं में डोंगरिया कोंध आदिवासियों ने नियमगिरि की पहाड़ियों पर बॉक्साइट खनन के विरोध में मतदान किया. ग़ौरतलब है कि डोंगरिया कोंध आदिवासी नियमगिरि की पहाड़ियों को नियम राजा कहते हैं. वे लोग स्वयं को नियम राजा की संतान मानते हैं और उनकी रक्षा के लिए अपनी जान देने को भी सदैव तत्पर रहते हैं. नियमगिरि का यह आंदोलन नियमगिरि सुरक्षा समिति के महामंत्री एवं समाजवादी जन परिषद् के राष्ट्रीय महासचिव लिंगराज आज़ाद की अगुवाई में चल रहा है. नियमगिरि का यह आंदोलन इस लिहाज़ से सफल कहा जाएगा कि इसमें विदेशी धन से संचालित एनजीओ की कोई भूमिका नहीं थी. हालांकि, नियमगिरि इलाक़े में एक्शन एड नामक एनजीओ भी पिछले कई वर्षों से सक्रिय है. इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक़, एक्शन एड को वर्ष 2008–09 में 364.47 करोड़ रुपये का विदेशी अनुदान प्राप्त हुआ था, वहीं 2012–13 में उसे 331.91 करोड़ रुपये का चंदा विदेशों से मिला. किसी एनजीओ को विदेशों से मिल रहे इतने बड़े अनुदान का आख़िर क्या मतलब है?

> **एक दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन है नियमगिरि का. पिछले साल उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि ओडिशा के रायगढ़ा और कालाहांडी ज़िले में नियमगिरि की पहाड़ियों पर ब्रितानी कंपनी वेदांता को बॉक्साइट खनन की अनुमति मिले अथवा नहीं, यह फ़ैसला नियमगिरि की पहाड़ियों पर बसे डोंगरिया कोंध आदिवासी करेंगे. उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद ओडिशा सरकार ने उन बारह गांवों में पल्ली सभा (ग्राम सभा) का आयोजन कराया, जहां डोंगरिया कोंध आदिवासी रहते हैं.**

इसी तरह देश में जीएम फ़सलों के ख़िलाफ़ भी आंदोलन चल रहे हैं. इस आंदोलन से जुड़े गेन कैंपेन नामक एनजीओ को वर्ष 2008 से 2013 के बीच कुल 5.45 करोड़ रुपये का विदेशी अनुदान मिला. गेन कैंपेन एनजीओ को यह धन इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और कनाडा से प्राप्त हुआ. देश में जीएम फ़सलों के विरोध में अभियान चला रही वंदना शिवा के एनजीओ नवदान्या ट्रस्ट को वर्ष 2008–09 से वर्ष 2011–12 के बीच 12.78 करोड़ रुपये का विदेशी अनुदान हासिल हुआ. नवदान्या ट्रस्ट को यह धन कनाडा, इटली, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विटजरलैंड और स्वीडन से मिला. इसके अलावा, नई दिल्ली स्थित इंडियन सोशल एक्शन फोरम नामक एनजीओ को पिछले पांच वर्षों के दौरान 5.06 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा मिला. आख़िर किसानों के नाम पर विरोध करने वाले इन एनजीओ में कौन लोग हैं और उन्हें क्या–क्या सुविधाएं मिलती हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है.

बहरहाल, विदेशी अनुदान से संचालित ग़ैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट शांत सरोवर में पत्थर मारने जैसी है. निश्चित रूप से इस रिपोर्ट पर विरोध और समर्थन के स्वर पैदा होंगे. बावजूद इसके पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे विदेशी चंदे से संचालित एनजीओ की भूमिका पर बहस करें, क्योंकि मौजूदा समय में एनजीओ का किरदार पूरी तरह बदल चुका है. ■

arsingh@chauthiduniya.com

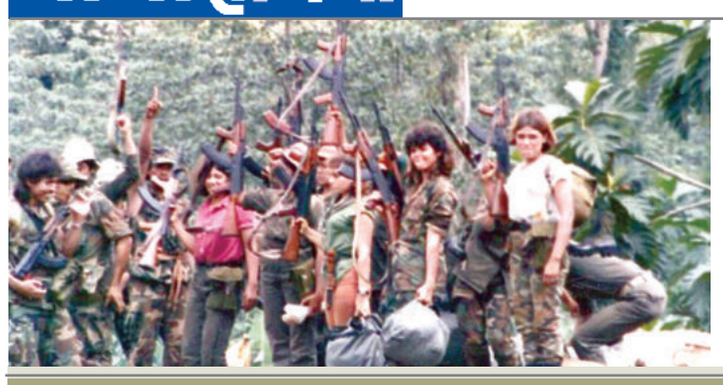

कई देशों में सत्ता परिवर्तन कर चुका है सीआईए

भारत में फोर्ड फाउंडेशन द्वारा पोषित और संचालित संगठनों और उससे जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं को बड़ी इज्जत दी जाती है. यह बात जगजाहिर है कि फोर्ड फाउंडेशन अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की एक शाखा की तरह काम करती है. सीआईए का काम दुनिया भर में अमेरिकी विदेश नीति और अमेरिकी हितों को साधना है. इसके लिए सीआईए किसी भी हद तक जा सकता है. भारत में सीआईए गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से अमेरिकी एजेंडे को लागू कराने पर आमादा है. सीआईए ने बीते कई दशकों के दौरान कई देशों में सत्ता परिवर्तन के नाम पर त्रासदियों को जन्म देकर उन देशों के मासूम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है.

अरुण तिवारी

दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए दूसरे देशों में सत्ता परिवर्तन कराने की अमेरिका रणनीति जगजाहिर है. इराक का हाल दुनिया के सामने है. सद्दाम हुसैन पर कई आरोप गढ़कर उन्हें सत्ता से बेदखल किया. सबसे दुखद यह रहा कि अमेरिका ने अपनी दादागीरी का नमूना खुले तौर पर पेश किया लेकिन किसी भी मजबूत और ताकतवर देश ने उसका विरोध नहीं किया. सद्दाम युग के ईराक से समाप्त हो जाने के बाद वहां की स्थितियां संभली नहीं बल्कि और ज्यादा बदतर हो गईं. आज ईराक गृह युद्ध की चपेट में आ गया है.कमोबेश यही हालात सीरिया में भी हैं. फ्री सीरियन आर्मी और बशर-अल-असद की सेनाओं के बीच चल रही जंग में देश के कई हिस्से तबाह हो चुके हैं. ईरान में यदि

गृह युद्ध जैसे हालात नहीं हैं तो वह आर्थिक अवस्था के बहुत ही बुरे दौर में पहुंच गया है. विचार करने योग्य बात यह है कि ईराक या उस जैसे सभी देश अमेरिकी हस्तक्षेप के पहले तक आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ थे. इन देशों के भीतर थोड़ी-बहुत हलचल जरूर रही थी लेकिन इनकी स्थित इतनी ज्यादा खराब नहीं थी. तो क्या इन देशों में रहने वाले करोड़ो लोगों के साथ हुए अन्याय के लिए अमेरिका को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए?

सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सक्रिय रहता है. उसके इन कार्यक्रमों को अक्सर सीआईए द्वारा नियंत्रित किया जाता है. परिवर्तन में कई बार अमेरिका की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है तो कभी वह चरमपंथियों को फंडिंग और ट्रेनिंग देकर तैयार करता है. इसमें उस देश की सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए लोगों को तैयार करना और सैनिक विद्रोह जैसे काम सीआईए के जरिए कराए जाते हैं. कई बार अमेरिका ने सीधे तौर पर सैन्य हस्तक्षेप करके भी सत्ता परिवर्तन कराए हैं जिनमें 1989 में पनामा और 2001 में अफग़ानिस्तान में अमेरिकी आक्रमण शामिल है. इसके अलावा अमेरिका कई देशों की विपक्षी पार्टियों को भी बिना किसी वजह समर्थन देता रहा है जिससे कि अमुक देश की सरकार को उखाड़ फेंका जा सके. इसका उदाहरण चिली और इटली जैसे देश हैं जहां सीआइए फंडेड एंटी कम्युनिस्ट विपक्षी पार्टियों ने सरकार का विरोध किया. अमेरिका के दूसरे देशों में इस हस्तक्षेप की शुरुआत 1918 में हुई रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद से ही शुरू हो गई थी जब उसने रूस में सरकार विरोधी धड़े को समर्थन देना शुरू कर दिया था. वहीं शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ की साम्यवादी सरकारों के खिलाफ खड़े समूहों को लगातार समर्थन दिया.

अगर दूसरे देशों की बात की जाए तो 1946 में ही लोकतंत्र का स्वाद चखने वाले सीरिया को तीन साल के भीतर ही सैनिक विद्रोह का सामना करना पड़ा जिससे देश में लोकतांत्रिक सरकार का अंत हो गया. इस सैनिक विद्रोह का नेतृत्व करने वाले सीरियाई आर्मी चीफ होस्नी अल-जईम ने छह बार सीआईए के अधिकारियों से मुलाकात की थी. ऐसा कहा जाता है कि जईम ने अमेरिका से फंड और सैनिक मदद के लिए गुहार लगाई थी लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हो सका कि अमेरिका ने उसकी मदद की थी या नहीं. हालांकि सत्ता में आते ही जईम ने अमेरिका के पक्ष में कई कदम उठाए थे.

अमेरिका के शिकार देशों ईरान का नाम आज से शामिल नहीं है. साल 1953 में अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ने का काम किया था. ऐसा बताया जाता है कि उस समय के ईरानी प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेघ ने देश की पेट्रोलियम इंड्रस्ट्री को नेशनलाइज करने की बात कही थी. इसकी वजह से ईरानी-ब्रिटिश तेल कंपनियों का मुनाफा कम होने का डर पैदा हो गया था. सीआईए द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों से यह जानकारी मिलती है कि उस समय ब्रिटेन डर गया था और उसने अमेरिका से गुहार लगाई थी कि ईरान की इस सरकार का हटाकर एक कठपुतली सरकार

बैठा दी जाए. इस ऑपरेश का नेतृत्व सीआईए अधिकारी केरमिट रूजवेल्ट जूनियर ने किया था. ग्वाटेमाला में भी अमेरिका सीआईए के सहयोग से 1954 में लोकतांत्रिक सरकार को हटवाने में अहम भागीदारी निभाई थी.

इसके अलावा भी ऐसे देशों की लंबी सूची है जिनमें अमेरिका ने सीआईए के जरिए या तो सीधे सैनिक हस्तक्षेप किए या फिर परोक्ष रूप से सरकार का हटाने के लिए विरोधियों की मदद की. इनमें क्यूबा, इंडोनेशिया, कांगो, दक्षिणी वियतनाम, घाना, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, अफ्गानिस्तान, तुर्की, पोलैंड और निकारगुआ जैसे देश शामिल है. यह फेहरिस्त यहीं आकर नहीं रुकती. अभी कई ऐसे और देश हैं जिनका जिक्र यहां नहीं किया जा सका है.

अमेरिका एक विश्व शक्ति है. विश्व शक्ति होने के लिए यह जरूरी है कि दुनिया में उसकी नीतियां कायम हों. अमेरिकी खुफिया एजेंसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दुनिया भर में अमेरिकी नीतियों को लागू करवाना है और उसके लिए समर्थन हासिल करना है. इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अमेरिका ने कभी प्रजातंत्र के नाम पर, कभी मानवाधिकार, कभी परमाणु और जनसंहार के हथियार के बहाने बनाकर विरोध करने वाली सरकारों को गिराने का काम किया है. भारत जैसे देश में सत्ता परिवर्तन कराना मुश्किल है क्योंकि यहां सैनिक विद्रोह नहीं हो सकता है. यही वजह है कि अमेरिकी एजेंसियां गैर सरकारी संगठनों के जरिए अपने हित को साधने का काम करती है. देश में फैले असंतोष की भावना को भड़काकर ये एजेंसियां जल जंगल जमीन, रोजगार, पर्यावरण तो कभी लोकपाल के नाम पर भारत के प्रजातांत्रिक संस्थानों की विश्वसनीयता को ध्वस्त करने में लगी हैं. देश की जनता को ऐसे गैर सरकारी संगठनों से सावधान हो जाना चाहिए जो कि विदेशी पैसे से संचालित हो रहे हैं.■

aruntiwari@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश

अमित शाह
भाजपा के नए खेवनहार !

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पटल पर नया ककहरा लिखा जा रहा है. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस-सपा और बसपा का जातिवाद वोट बैंक का हमेशा हिट रहने वाला जिताऊ फार्मूला क्या धाराशायी हुआ, इन दलों के बड़े से लेकर छोटे नेताओं- कार्यकर्ताओं तक के सुर-ताल बदल गए हैं. खासकर अखिलेश सरकार तो एक दम नए अवतार में आ गई है. रेवड़ियां बांट कर तमाम वर्गों के वोटरों को लुभाने के चक्कर में बनी लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, साड़ी-कंबल बांटने जैसी योजनाओं के सहारे समाजवादी पार्टी अपने सिर जीत का सेहरा नहीं बांध पाई तो उसने एक झटके में इन योजनाओं को बंद कर दिया. अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपने पाले में खड़ा करने के लिए शुरू की गई, 'हमारी बेटी, इसका कल' योजना से भी सरकार ने तौबा कर ली. अब सपा सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है. वह बिजली-पानी, सड़क, सेतु, सिंचाई की सुविधा, क़ानून व्यवस्था के मोर्चे पर ठीक वैसे ही लड़ना चाहती है जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार विकास को अपना हथियार बनाये हुए है. दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अब थोथी बातें नहीं हो रही हैं, बल्कि प्रमाणिक तौर पर विकास का खाका खींचा जा रहा है.

यूपी में विकास का पहिया चल पड़ा है, तो इसका सबसे अधिक श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पीएम नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वासपात्र अमित शाह को. शिकागो में एक बड़े व्यवसायी परिवार अनिल चंद्र के यहां जन्मे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से राजनीति के मैदान में उतरने वाले अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने यूपी में ऐसा रंग दिखाया कि करीब दो दशकों से निर्जीव पड़ी भाजपा में जान आ गई. मोदी ने भाषणों से समा बांधा तो अमित शाह ने इसे वोटों में तब्दील करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन किया. यूपी के इतिहास में कभी ऐसा नेता नहीं हुआ है जिसने अपने बल पर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है. इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी ने यह करिश्मा करा जरूर था, लेकिन उन्हें मां इंदिरा गांधी की शहादत के कारण चमत्कारी जीत हासिल हुई थी.

लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पाटी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल जैसे तमाम दलों के नेताओं ने भरसक कोशिश की कि किसी तरह से चुनाव को विकास के मुद्दे से भटकाकर मुजफ्फरनगर दंगा, अयोध्या विवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद पर केंद्रित कर दिया

जाए ताकि वोटों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो सके, इसके लिये समाजवादी पार्टी ने आजम खां, नरेश अग्रवाल जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया तो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, बेनी प्रसाद वर्मा, सलमान खुर्शीद और राहुल गांधी की टीम के अन्य सदस्य लगातार बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे थे. राहुल ने तो एक जनसभा में यहां तक कह दिया कि मोदी आए तो 22 हजार लोग दंगों में मारे जाएंगे. यह मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंचा. बसपा की तरफ से मायावती स्वयं मोर्चा संभाले हुए थीं, राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी अजित सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी को समुंदर में फेंक देना चाहिए, लेकिन भाजपा नेता और यूपी के चुनाव प्रभारी अमित शाह की पारखी नज़र ने विरोधियों के मंसूबे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिये. अमित शाह ने ऐसी गोटियां बिछाईं की छोटी-छोटी जातियों में बंटा हिन्दू समाज कांग्रेस की जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिये एकजुट हो गया. मुसलमान भी मोदी की बातों से प्रभावित तो था, लेकिन मुल्ला-मौलवियों ने शैक्षिक रूप से पिछड़ी इस कौम के मतदाताओं के दिमाग पर दहशत का पर्दा डाल दिया. भाजपा की बढ़त को रोकने के लिये मोदी के कुत्ते का पिल्ला वाले बयान, 2002 के गुजरात दंगों को खूब उछाला गया. यहां तक दुष्प्रचार किया गया कि मोदी अगर सत्ता में आ जायेंगे तो मुसलमानों को देश छोड़कर जाना पड़ेगा. उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी.

एक तरफ विरोधी मोदी पर हमला बोल रहे थे तो दूसरी तरफ अमित शाह को गुजरात का भगौड़ा बताकर उनका भी मजाक उड़ाया जा रहा था. यह और बात थी कि न तो अमित शाह विरोधियों के हमलों से टूटे और न ही उनके सामने झुके बल्कि सभी का डटकर मुक़ाबला किया. शाह ने कभी भी अपने व्यक्तिगत अंहकार को तरजीह नहीं दी, चुनाव आयोग ने उनके ऊपर जब प्रतिबंध लगाया तो माफी मांग कर शाह ने उससे पीछा छुड़ा लिया जबकि समाजवादी पार्टी के आजम खां साहब उलटा चुनाव आयोग से टकराते रहे, जिसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा. अंत तक आजम खां को जनसभा या रोड शो करने की इजाजत नहीं मिली. अमित शाह विरोधियों को भी पूरा सम्मान देते हैं. इस बात का अहसास मोदी के शपथग्रहण समारोह के दौरान देखने को मिला जब वह सपा प्रमुख का हाथ पकड़ कर उनको उनकी कुर्सी पर सम्मानपूर्वक बैठा कर आये.

बात यहीं खत्म नहीं होती है. शाह ने यूपी में सपा-बसपा और कांग्रेस को उनके मुद्दे नहीं उछालने दिए, लेकिन स्वयं(शाह) और मोदी ने जिस ट्रैक पर चाहा राजनीति की गाड़ी दौड़ाई. शाह का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा वाराणसी से मोदी को चुनाव मैदान में उतारना. उन्होंने भाजपा की इस रणनीति को अमली जामा पहनाया. इसके अलावा शाह बहुसंख्यक मतदाताओं के दिमाग मे यह बात भी बैठाने में कामयाब रहे कि प्रदेश में सभी गैर भाजपाई दल तुष्टिकरण की राजनीति में लगे हैं और बहुसंख्यकों के दुख-दर्द की इन्हें चिंता नहीं है. शाह ने सीधे तौर पर तो हिन्दुत्व को धार नहीं दी, लेकिन अपना चुनाव प्रचार अयोध्या में रामलला के दर्शन से शुरू करना. वाराणसी में मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में विश्वनाथ जी का दर्शन करके इस मुहिम को और आगे बढ़ाया. एक तरफ तो शाह ने मुलायम-माया और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चाबंदी की वहीं दूसरी ओर अपनी पार्टी के भीतर की गुटबाजी पर भी विराम लगाया. वर्षों से विभिन्न पदों पर कुंडली मारे बैठे नेताओं को आईना दिखाया गया. कई बुजुर्ग नेताओं के टिकट काट दिये गए, लेकिन किसी ने भी जरा सी चूं नहीं की.

शाह ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई. अभी भी वह दिल्ली में बैठकर यूपी पर नजर रखे हुए हैं. यूपी के बड़े-बड़े नेताओं को अपने वहां बुलाकर शाह उनकी रिपोर्ट देखते हैं, उन्हें दिशा निर्देश देते हैं. कौन सांसद अपने क्षेत्र में कितना समय दे रहा है, किससे क्षेत्रीय जनता नाराज चल रही है, सब बातों का आंकड़ा जुटाया जा रहा है. शाह ने जो कुछ किया वह मोदी ही नहीं आरएसएस एवं भाजपा के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं था. ऐसे में अगर शाह को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी दी जाती है, तो यह फैसला भाजपा के लिए 'मील का पत्थर' साबित हो सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमित शाह रूपी 'बेशकीमती रत्न' की कीमत जानते-पहचानते हैं. वह उसे राजनीति के बाजार में अपने हिसाब से तौलेंगे. यह अमित शाह ही हैं जिन्होंने गुजरात का गृह मंत्री रहते 2008 में अहमदाबाद बम ब्लास्ट कांड का खुलासा मात्र 21 दिनों में कर दिया था. बम ब्लास्ट में 58 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हुए थे. इतना ही नहीं उसके बाद ब्लास्ट के सूत्रधार रहे इंडियन मुजाहिद्दीन की उन्होंने गुजरात में कमर ही तोड़ दी थी. अमित शाह के लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन राजनीति के मैदान में कई ऊंचाइयां छूने वाले अमित शाह के राजनीतिक कैरियर में सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामला ग्रहण की तरह लगा हुआ है. ■

feedback@chauthiduniya.com

घटना के बाद बीएसपी में काम करने वालों ने प्रबंधन के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया. सबने बीएसपी प्रबंधन की सोच में आए बदलाव, तौर–तरीकों और नीतियों को लेकर सवाल खड़े किए. यह बात भी सामने आई कि कर्मचारियों की सुरक्षा का मसला अधिक उत्पादन के दबाव में हाशिये पर चला गया है. ब्लास्ट फर्नेस की पाइप लाइन जैसी हैवी प्रणालियों को अक्सर रखरखाव की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पिछले दस सालों से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.

भिलाई स्टील प्लांट हादसा

सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

सुषमा गुप्ता

बीते 12 जून को भिलाई स्टील प्लांट में गैस रिसाव के चलते छह लोगों की जान चली गई और क़रीब तीन दर्जन से ज़्यादा लोग हादसे की चपेट में आए. भिलाई गैस हादसे ने लोगों के जेहन में भोपाल गैस त्रासदी की याद ताज़ा कर दी. हादसे के क़रीब एक सप्ताह के बाद बीएसपी के उत्पादन में आई कमी पूरी कर ली गई, लेकिन प्लांट में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के जवाब नहीं खोजे जा सके हैं. इस हादसे में प्रबंधन द्वारा लापरवाही की बात बार–बार सामने आई और इसी के साथ यह सवाल भी खड़ा हो गया कि क्या यूनियन कार्बाइड की तरह यहां भी किसी बड़े हादसे की आशंका है. हालांकि घटना के एक सप्ताह बाद प्रबंधन ने सामने आकर सफाई दी और सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोताही से इंकार किया, लेकिन बीएसपी के कर्मचारी प्रबंधन की सफाई से संतुष्ट नहीं हैं. इसकी वजह भी है.

बीएसपी प्रबंधन के पास आज भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि गैस कैसे लीक हुई. घटना के दूसरे दिन केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा भिलाई में बुलाई गई प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि हादसा कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि गैस लीक होने की वजह से हादसा हुआ. लेकिन गैस लीक कैसे हुई, इस बात की जानकारी वह नहीं दे पाए. जाहिर है, जब बुनियादी सवाल अनुत्तरित है, तो बाकी सवालों पर तमाम ख़तरों के बीच काम कर रहे बीएसपी कर्मचारी कैसे संतुष्ट हो पाएंगे?

हादसा गुरुवार 12 जून की शाम पंप हाउस नंबर दो में हुआ, जहां से पानी ब्लास्ट फर्नेस में जाता है. यहां स्थित पाइपों में रखरखाव का काम चल रहा था, उसी दौरान एक पाइप फट गया और उससे गैस निकलने लगी. ये गैस मिथेन और कार्बन मोनो ऑक्साइड थी. ये दोनों गैस जहरीली, गंधहीन और स्वादहीन होती हैं. इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति को इसका एहसास देर से होता है. उस शाम रिसाव का पता लोगों को तब हुआ, जब वहां कबूतर गिरने लगे. जब वहां मौजूद लोगों को दिक्कत होने लगी, तो वहां सुरक्षाकर्मियों को बुलाया गया. मौक़े पर पहुंचे सुरक्षाकर्मी मामले को समझ पाते, इससे पहले ही वे भी गैस की चपेट में आ गए. स्वयं चीफ फायर ऑफिसर बी के महापात्रा मौके पर पहुंचे और वह भी बेहोश हो गए. घटना की जानकारी मिलने पर जो भी सुरक्षाकर्मी वहां व्यवस्था संभालने के लिए पहुंचा, गैस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. एन सी कटारिया, चार्जमैन ए सेमुएल, सीनियर ऑपरेटर वाई एस साहू, फायरमैन रमेश कुमार शर्मा और ठेका श्रमिक विकास वर्मा यानी छह लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे.

अन्य प्रभावित लोगों में वाटर मैनेजमेंट विभाग के कर्मचारियों के अलावा फायर ब्रिगेड एवं सीआईएसएफ के जवान भी शामिल हैं. इसके बाद तो हड़कंप मच गया और सभी लोगों को तुरंत सेक्टर 9 स्थित नेहरू मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया गया. प्रबंधन ने हादसे पर जमकर लीपापोती करने की कोशिश की. उसे हरकत में आने में क़रीब 3 घंटे लग गए. मीडिया से जानकारियां छिपाई जाने लगीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह से फोन पर घटना की जानकारी ली. लेकिन, हैरान करने वाली बात यह रही कि मुख्यमंत्री को रायपुर से भिलाई की 40 किलोमीटर की दूरी तय करके पीड़ितों तक पहुंचने में 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया. वह केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ आए और अस्पताल में घायलों से मिलकर वापस रायपुर चले गए. वहीं तोमर डटे रहे और उन्होंने आधी रात को घटनास्थल का मुआयना किया, अगली सुबह हर मृतक के परिवारीजनों से मुलाकात की और फिर वापस दिल्ली गए.

घटना के बाद बीएसपी में काम करने वालों ने प्रबंधन के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया. सबने बीएसपी प्रबंधन की सोच में आए बदलाव, तौर–तरीकों और नीतियों को लेकर सवाल खड़े किए. यह बात भी सामने आई कि कर्मचारियों की सुरक्षा का मसला अधिक उत्पादन के दबाव में हाशिये पर चला गया है. ब्लास्ट फर्नेस की पाइप लाइन जैसी हैवी प्रणालियों को अक्सर रखरखाव की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पिछले दस सालों से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. जिस पाइप लाइन में विस्फोट हुआ, वह पिछले 27 सालों से नहीं बदली गई थी. पहले संयंत्र में एक नियमित अंतराल पर भारी मशीनों को बंद करके उनकी जांच एवं देखभाल की जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में यह व्यवस्था बंद कर दी गई है, जिससे इस तरह की दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है.

बीएसपी में 90 के दशक में वीआरएस स्कीम लागू करके बड़ी संख्या में कामगारों की छंटनी की गई और उनकी जगह अब ठेका मज़दूर काम करते हैं. मौजूदा समय में यहां क़रीब 25 हज़ार नियमित कर्मचारी हैं, जबकि ठेका मज़दूरों की संख्या 50 हज़ार से ज़्यादा है. स्थायी मज़दूरों को न्यूनतम ट्रेनिंग देने के बाद ही कार्यस्थल पर भेजा जाता था. लगातार काम करने से उक्त मज़दूर ट्रेंड हो जाते थे और मशीनों की बुनियादी कार्यप्रणाली से वाकिफ रहते थे तथा किसी मशीन में आई थोड़ी–सी भी खराबी के प्रति वे अधिकारियों को आगाह कर देते थे. लेकिन, ठेका मज़दूर दो–चार महीने काम करते हैं और फिर चले जाते हैं. 2–4 महीने काम करने की वजह से उन्हें न तो ठीक से ट्रेनिंग मिल पाती है और न वे मशीनों के बारे में ज़्यादा कुछ जान पाते हैं. और तो और, बीएसपी के कर्मचारियों की मानें, तो उक्त ठेका मज़दूरों से ऐसी जगहों पर काम लिया जा रहा है, जहां पर केवल अति कुशल लोग ही काम कर सकते हैं. ऐसे में ठेका मज़दूरों पर हर समय ख़तरा मंडराता रहता है.

बीएसपी प्रबंधन और दुर्ग ज़िला प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि गैस का रिसाव कैसे हुआ. प्रबंधन की मानें, तो गैस पाइप लाइन से रिवर्स हो गई. प्रबंधन का दावा है कि गैस रिवर्स होने की घटना इससे पहले किसी भी स्टील संयंत्र में नहीं हुई. कच्चे लोहे (आयरन ओर) से स्टील बनने की प्रक्रिया में तीन स्तरों पर कोक-1, मिथेन, कार्बन मोनो ऑक्साइड और कनवर्टर नामक जहरीली गैसें बनती हैं, जिनका इस्तेमाल प्लांट में ईंधन के रूप में किया जाता है.

मज़दूर संगठन सीटू के मुताबिक, ठेका मज़दूरों को सुरक्षा संबंधी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, केवल ट्रेनिंग की रस्म अदायगी की जाती है. हालांकि प्रबंधन का दावा है कि ठेका मज़दूरों को पर्याप्त सुरक्षा प्रशिक्षण के बाद ही कार्यस्थल पर भेजा जाता है. ऐसे संयंत्रों में कर्मचारियों के लिए सुरक्षा समिति होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दुर्घटना के बाद यह बात सामने आई कि इस संयंत्र में ऐसी किसी सुरक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है. यही हाल गैस सेफ्टी विभाग और एनर्जी मैनेजमेंट विभाग का है, जो ऐसे हादसे रोकने में सक्षम होते हैं, लेकिन उक्त विभाग काफी दिनों से कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं. बीएसपी कर्मचारी बताते हैं कि घटना के बाद सेफ्टी सायरन भी नहीं बजा था. यही नहीं, गैस रिसाव के चलते घटनास्थल से 500 मीटर दूर काम कर रहे कुछ लोगों ने चक्कर आने की शिकायत की थी, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया. इससे साफ़ तौर पर जाहिर होता है कि प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रबंधन कितना गंभीर है. घटना के बाद एक बात और चर्चा में थी कि गैस लीक होने की शिकायत लोगों ने पहले भी की थी, लेकिन उसकी अनदेखी कर दी गई.

बीएसपी प्रबंधन और दुर्ग ज़िला प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि गैस का रिसाव कैसे हुआ. प्रबंधन की मानें, तो गैस पाइप लाइन से रिवर्स हो गई. प्रबंधन का दावा है कि गैस रिवर्स होने की घटना इससे पहले किसी भी स्टील संयंत्र में नहीं हुई. कच्चे लोहे (आयरन ओर) से स्टील बनने की प्रक्रिया में तीन स्तरों पर कोक–1, मिथेन, कार्बन मोनो ऑक्साइड और कनवर्टर नामक जहरीली गैसें बनती हैं, जिनका इस्तेमाल प्लांट में ईंधन के रूप में किया जाता है. यदि इन गैसों का समुचित प्रबंधन न हो, तो ऐसे हादसे कभी भी हो सकते हैं. बीएसपी से जुड़े कुछ लोगों के मुताबिक, यहां उक्त गैसें इतनी मात्रा में प्रोड्यूस होती हैं कि अगर कभी उनमें विस्फोट हुआ, तो भोपाल गैस कांड जैसा हादसा हो सकता है. हालांकि प्रबंधन से जुड़े लोग ऐसी आशंकाओं को खारिज करते हैं. उनका कहना है कि इन गैसों का प्रबंधन अनेक स्तरों में कई जगहों पर किया जाता है और ये कहीं एक जगह पर एकत्र नहीं होतीं.

बहरहाल, हादसे से एक बात साफ़ हो गई है कि गैस के लिहाज़ से भिलाई स्टील प्लांट और अन्य स्टील प्लांट बेहद संवेदनशील हैं. यदि ऐसी गैसों को खपाने का कार्य सुचारू रूप से नहीं किया जाएगा, तो दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहेगी. इससे पहले 1986 में भी यहां गैस रिसाव की घटना हो चुकी है, जिसमें 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. दो घटनाओं के बाद यह सवाल लाजिमी है कि क्या प्लांट के अंदर जहरीली गैसों के प्रबंधन में कोई खामी है?■

feedback@chauthiduniya.com

जदयू के विधायकों में जो बचैनी है इसकी एक वजह यह भी है कि आगामी चुनाव में इन विधायकों को जीतने की सम्भावना कम लग रही है. संसदीय चुनाव में जदयू की हुई शर्मनाक हार व भाजपा की हुई शानदार जीत का असर आगामी होने वाले विधान सभा चुनाव में चंपारण में सबसे अधिक पड़ेगा और जदयू प्रत्याशियों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए कड़ी कसरत करनी पड़ेगी.

जदयू के दर्जनों विधायकों पर हार का ख़तरा

जदयू विधायकों के माथे पर इस बात को लेकर चिंता की लकीरें हैं कि इन सवर्ण वोटरों का क्या होगा, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें बड़ी संख्या में किया था. इसके अलावा भाजपा के अन्य वोट बैंक भी अब जदयू से दूर रहेंगे. लोकसभा चुनाव में जो तस्वीर उभरी, वह बताती है कि कुल सवर्ण वोटरों में से 70 फ़ीसदी ने एनडीए प्रत्याशियों को वोट दिया. बाक़ी तीस फ़ीसदी वोट ही दूसरे दलों को मिले हैं, जिनमें राजद व जदयू भी शामिल है. लोकसभा चुनाव के इन आंकड़ों से जदयू के दर्जनों विधायक ख़ासकर अगड़ी जाति के विधायक परेशान हैं. यह मानी हुई बात है कि अगर अगड़ी जाति का वोट जदयू के विधायकों को नहीं मिला तो कम-से-कम तीन दर्जन विधायकों का जीतना असंभव है. लगभग इतने ही विधायक कड़ी लड़ाई में फंसे हुए नज़र आएंगे.

सरोज सिंह

बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अभी से ही जातीय गुणा-भाग करने का काम हर दल में शुरू हो गया है. पिछले विधानसभा चुनाव के मुक़ाबले इस बार सारे समीकरण बदल गए हैं. भाजपा से नाता तोड़ जदयू अब राजद के क़रीब आने की कवायद में जुटा है. लालू प्रसाद ने इस काम के लिए अपने दरवाजे भी खोल रखे हैं. लालू और नीतीश की दोस्ती होगी या नहीं होगी यह तो अभी तय नहीं है, लेकिन यह सच है कि भाजपा और जदयू का साथ छूट चुका है. ऐसे में जदयू विधायकों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं कि उन सवर्ण वोटरों का क्या होगा, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें बड़ी मात्रा में वोट किया था. इसके अलावा भाजपा के अन्य वोट बैंक भी अब जदयू से दूर रहेंगे. उधर, लोकसभा चुनाव में जो तस्वीर उभरी है, वह बताती है कि कुल सवर्ण वोटरों में से 70 फ़ीसदी ने एनडीए के प्रत्याशियों को वोट दिया. बाक़ी तीस फ़ीसदी वोट ही दूसरे दलों को मिले हैं, जिनमें राजद व जदयू भी शामिल हैं. लोकसभा चुनाव के इन आंकड़ों से जदयू के दर्जनों विधायक, ख़ासकर अगड़ी जाति के विधायक, परेशान हैं. यह मानी हुई बात है कि अगर अगड़ी जाति का वोट जदयू के विधायकों को नहीं मिला तो कम-से-कम तीन दर्जन विधायकों का जीतना असंभव है. लगभग इतने ही विधायक कड़ी लड़ाई में फंसे हुए नज़र आएंगे. इसके अलावा इस बार उन्हें कुशवाहा वोटों से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बन जाने के बाद इस समुदाय ने नए सिरे से सोचना शुरू कर दिया है. जदयू के विधायकों में जो बचैनी है उसकी एक वजह यह भी है कि आगामी चुनाव में इन विधायकों को जीतने की संभावना कम लग रही है. संसदीय चुनाव में जदयू की हुई शर्मनाक हार व भाजपा की हुई शानदार जीत का असर आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में चंपारण में सबसे अधिक पड़ेगा और जदयू प्रत्याशियों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए कड़ी कसरत करनी पड़ेगी.

मगध में बदल गए सारे समीकरण

मगध प्रमंडल के पांच ज़िलों के 26 विधानसभा क्षेत्रों में से सर्वाधिक 16 पर जदयू क़ाबिज़ है. आठ पर भाजपा तथा राजद और निर्दलीय का एक-एक पर क़ब्ज़ा है. यह स्थिति तब की है, जब भाजपा के साथ जदयू था. मगध की जनता ने भी एनडीए के लिए संयुक्त रूप से जदयू-भाजपा को मत देकर 26 में से 24 विधानसभा क्षेत्रों पर क़ब्ज़ा दिलाया था. लेकिन पिछले एक साल में राजनीतिक उठा-पटक ने बिहार के साथ-साथ मगध प्रमंडल के भी सारे राजनीतिक समीकरण को भी बिगाड़ दिया. लोकसभा चुनाव में नमो की लहर ने सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया. लेकिन विधानसभा चुनाव में यह स्थिति तो नहीं रहेगी. अगर अगड़ी जाति के मतों में बिखराव हुआ तो सर्वाधिक नुकसान जदयू को होगा. लोकसभा चुनाव में तो एक तरह से कहें तो अगड़ी जातियों के वोटरों का ध्रुवीकरण का प्रभाव मगध पर भी पड़ा और जदयू, राजद, कांग्रेस का सूपड़ा साफ़ हो गया. 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू-भाजपा के एनडीए गठबंधन में सबसे अधिक लाभ भी जदयू को ही मिला था. मगध प्रमंडल के 26 विधानसभा क्षेत्रों में से जदयू ने 18 सीतों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 16 पर उसकी जीत हुई थी और 2 विधानसभा क्षेत्रों, बेलागंज और ओबरा, में जदयू के प्रत्याशी हार गए थे. जबकि भाजपा ने सभी आठ सीटों पर जीत हासिल की थी. लेकिन अब बदलते राजनीतिक हालात में जदयू के वोट बैंक की राजनीति में गड़बड़झाला हो गया है. अगड़ी जाति का वोट पिछले चुनाव में एनडीए के साथ था. इसका लाभ भाजपा के साथ-साथ जदयू को भी मिला था, लेकिन आज स्थिति बदल गई है. अगले साल आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरण का असर सबसे अधिक जदयू पर पड़ेगा. मगध में जो स्थिति नज़र आ रही है, उसमें अगड़ी जाति का वोट आज की स्थिति में पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन 70 प्रतिशत भाजपा के साथ ज़रूर रहेगा. ऐसे में स्थानीय स्थिति और जातीय समीकरण का असर भी विधानसभा चुनाव में पड़ेगा. अगड़ी जाति के वोट बैंक में कुछ भी बिखराव हुआ, तो जदयू के सुरक्षित विधानसभा क्षेत्रों पर कम और सामान्य विधानसभा क्षेत्रों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा. इनमें प्रभावित होने वाले विधानसभा क्षेत्रों और विधायकों के नाम हैं- कुर्था के सत्यदेव सिंह, जहानाबाद के अभिराम शर्मा, घोषी के राहुल कुमार, गोह के रणविजय सिंह, नबीनगर के विरेन्द्र कुमार सिंह, कुटुंबा के ललन राम, रफीगंज के अशोक कुमार सिंह, बाराचट्टी की ज्योति देवी, टिकारी के अनिल कुमार, अतरी के कृष्णनन्दन यादव, वारसलीगंज के प्रदीप कुमार. ऐसे ही टिकारी के विधायक अनिल कुमार जदयू के बाग़ी खेमें में आकर आने वाले विधानसभा चुनाव में दल-बदल करने का संकेत दे रहे हैं. अन्य जदयू विधयकों की क्या रणनीति रहेगी, यह तो समय बताएगा लेकिन इतना तय है कि अगड़ी जाति के वोट बैंक को नज़रअंदाज़ करना जदयू के लिए सबसे ख़तरनाक साबित होगा.

चम्पारण में लग सकता है बड़ा झटका

चम्पारण में 21 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें आठ विधानसभा क्षेत्रों, वाल्मीकिनगर, बगहा, नौतन नरकटिया, पिपरा, मधुबन, गोविन्दगंज व कल्याणपुर पर जदयू का क़ब्ज़ा है. यहां से क्रमश: राजेश सिंह, प्रभात रंजन सिंह, मनोरमा प्रसाद, श्यामबिहारी प्रसाद, अवधेश कुशवाहा, शिवजी राय, मीना द्विवेदी व रजिया खातुन विधायक हैं.

इनमें वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्र की अलग पहचान रही है और थारू समाज के सर्वाधिक मतदाता यहां हैं. यहां थारू करीब 80 हज़ार, कोइरी 50 हज़ार, वैश्य 35 हज़ार, यादव 30 हज़ार, मुस्लिम 25 हज़ार, राजपूत 20 हज़ार के साथ-साथ अन्य जातियों के मतदाता भी हैं. कभी जदयू के लिए वोट बैंक साबित होने वाला थारू समाज अभी पूरी तरह से भाजपा के साथ है और इस बार के लोकसभा चुनाव में जदयू को पूरी तरह से नकार चुका है. वर्ष 2010 के चुनाव में भाजपा-जदयू ने साथ चुनाव लड़ा था. उस वक्त जदयू प्रत्याशी राजेश सिंह को 42,289 वोट मिले थे, जिसमें थारू समाज के लोगों ने जदयू को अधिक वोट दिया था. उस चुनाव में राजद प्रत्याशी मुकेश कुमार कुशवाहा को 27,618 व बसपा प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रताप सिंह को 20 हज़ार 866 वोट मिले थे. वहीं बगहा विधानसभा क्षेत्र पर अगर नज़र डालते हैं तो यहां सबसे अधिक ब्राह्मण मतदाता हैं. दूसरा स्थान यादव व तीसरा स्थान कोइरी व वैश्य समाज का है. वर्ष 2010 के चुनाव में जदयू विधायक प्रभात रंजन सिंह को 67510 वोट मिले थे, जबकि राजद के रामप्रसाद यादव को 18425 व बसपा प्रत्याशी मो. कमरान को 18341 वोट प्राप्त हुए थे. नौतन विधानसभा क्षेत्र में करीब 40 हज़ार कोइरी, 30 हज़ार मुस्लिम, 30 हज़ार यादव, 25 हज़ार मल्लाह, 25 हज़ार ब्राह्मण मतदाता हैं. वर्तमान जदयू विधायक मनोरमा प्रसाद को वर्ष 2010 के चुनाव में 40894 वोट मिले थे, जबकि राजद के नारायण प्रसाद को 18130 वोट मिले थे. बसपा के अमर यादव को 8521 व सीपीआई के गुल्लू चौधरी को 15 हज़ार 467 वोट प्राप्त हुए थे. इसी तरह नरकटिया विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहां करीब 60 हज़ार मुस्लिम मतदाता हैं. दूसरे स्थान पर यादव व तीसरे स्थान पर वैश्य हैं. साल 2010 के चुनाव में जदयू के श्यामबिहारी प्रसाद को 31 हज़ार 549, लोजपा के यासमिन साबिर अली को 23 हज़ार 861 व डॉ. शमीम अहमद को 14 हज़ार 217 वोट मिले थे. पिपरा विधान सभा क्षेत्र पर अगर नज़र डालते हैं, तो यहां कोइरी मतदाताओं की संख्या अधिक है. दूसरे स्थान पर यादव व तीसरे स्थान पर मुस्लिम मतदाता हैं.

यहां वैश्य मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है. साल 2010 के चुनाव में जदयू के अवधेश कुशवाहा को 40 हज़ार 99 व राजद के सुबोध यादव को 28212 वोट मिले थे. वहीं मधुबन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक 60 हज़ार, राजपूत, 40 हज़ार यादव, 35 हज़ार कोइरी, 25 हज़ार मुस्लिम व करीब 20 हज़ार वैश्य मतदाता हैं. साल 2010 के चुनाव में जदयू के शिवजी राय को 40 हज़ार 478, राजद के राणा रंधीर सिंह को 30 हज़ार 356 व कांग्रेस के राजेश कुमार रौशन उर्फ बब्लू देव को 15 हज़ार 248 वोट मिले थे. वहीं गोविन्दगंज विधानसभा क्षेत्र में करीब 60 हज़ार ब्राह्मण, 40 हज़ार भूमिहार, क़रीब 25 हज़ार राजपूत व 20 हज़ार मुस्लिम मतदाता हैं. साल 2010 के चुनाव में जदयू की मीना द्विवेदी को 33 हज़ार 859, लोजपा के राजू तिवारी को 25 हज़ार 454 व कांग्रेस के जयप्रकाश पाण्डेय को 13 हज़ार 17 वोट मिले थे. इसी तरह कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 50 हज़ार भूमिहार, 30 हजार ब्राह्मण, 25 हज़ार मुस्लिम व 20 हज़ार यादव मतदाता हैं. इस तरह अधिकांश सीटों पर काफी कम वोटों के अन्तर से जदयू की जीत हुई थी और प्रत्याशियों को कड़ा संघर्ष भी करना पड़ा था. लेकिन, इस बार के चुनाव में जब भाजपा अलग है तो फिर चुनाव का रुख कैसा होगा, सहज अनुमान लगाया जा सकता है. वैसे जानकार बताते हैं कि चम्पारण में जदयू पूरी तरह से खोखली हो गई है और लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद उसके नेताओं व कार्यकर्ताओं में जोश नहीं रह गया है. वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और वे इस विधानसभा चुनाव को अपनी पक्ष में करने में जुट गए हैं.

तिरहुत में बहाना होना जदयू को पसीना

तिरहुत प्रमंडल के सीतामढ़ी, शिवहर और मुज़फ्फरपुर ज़िले में संपन्न लोकसभा चुनाव ने इस बात का संकेत लगभग साफ दे दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू की राह आसान नहीं होगी. जदयू-भाजपा का पुरानी गठबंधन दरकने के बाद हुए पहले चुनाव के नतीजा ने यह भी साफ कर दिया है कि अकेले जदयू चुनावी समर में कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है. अब तक जाति व पार्टी के नाम पर मतदान करने वाले मतदाताओं ने अपनी मंशा में बदलाव करना शुरू कर दिया है.

राजद शासन काल में जंगल राज का हंगामा खड़ा कर सत्ता पाने वाली जदयू को अब महादलित व अल्पसंख्यक कार्ड का खेल महंगा पड़ने लगा है. आलम है कि न तो अल्पसंख्यक पूर्णत: जदयू के साथ है और न ही महादलित का ही भरपूर समर्थन मिलता नज़र आ रहा है. रही बात सवर्ण की तो राजद से नाराज़ सवर्णों ने नीतीश कुमार को भरपूर समर्थन देकर सत्ता में लाने का काम किया था, लेकिन नीतीश कुमार सवर्णों की अपेक्षा पर खरे नहीं उतर सके. नतीजा है कि अब सवर्ण जदयू को पचा पाने की स्थिति में नहीं हैं. यही कारण है कि संपन्न लोकसभा चुनाव में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव व तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तूफानी चुनावी सभाओं के बाद भी कोई भी विधायक अपने क्षेत्र में मतदाताओं को जदयू के पक्ष में एकजुट करने में सफल नहीं हो सका. सीतामढ़ी के कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 पर जदयू का क़ब्ज़ा है. उनमें सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाहिद अली खान सुरसंड, वर्तमान गन्ना विकास मंत्री डॉ. रंजू गीता बाजपट्टी, बिहार विरासत विकास समिति की सभापति गुड्डी देवी रून्नीसैदपुर एवं सुनीता सिंह चौहान बेलसंड से विधायक हैं. शिवहर से अल्पसंख्यक विधायक सरफुद्दीन जदयू का कमान संभाल रखे हैं. मुज़फ्फरपुर ज़िले में कुल 11 विधानसभा क्षेत्र है. जिनमें भाजपा 4 सीट पर है. इनमें पारू से अशोक कुमार सिंह, मुज़फ्फरपुर नगर सुरेश शर्मा, गायघाट वीणा देवी, औराई राम सूरत राय, जदयू के बोचहां से रमई राम, सकरा सुरेश चंचल, कुढनी से मनोज कुशवाहा, साहेबगंज से राजू कुमार सिंह राजू, मीनापुर से दिनेश कुशवाहा, कांटी ई. अजीत कुमार हैं. वहीं, बरूराज से राजद के ब्रज किशोर सिंह शामिल है. चर्चाओं पर यकीन करें तो लोकसभा चुनाव के बाद सूबे में आयी राजनीतिक भूचाल ने लोगों की सोच को बदल दिया है. लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार का इस्तीफ़ा और फिर राज्यसभा की सीट को लेकर जदयू के विधायकों में मचे विद्रोह ने पार्टी की छवि को आम लोगों के बीच बहुत हद तक प्रभावित किया है. अगर अगड़ी जातियों के वोट पिछली बार की तरह जदयू के उम्मीदवारों को नहीं मिलते हैं, तो फिर तिरहुत में जदयू को नाको चने चबाना पड़ सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA
چوتھی دنیا
First International Urdu Weekly

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

निम्न-मध्यम वर्ग को राहत मिलनी चाहिए

बजट में करदाताओं के लिए कुछ राहत के संकेत मिल रहे हैं. लेकिन किस तरह की राहत? आप वास्तव में राहत देना चाहते हैं, तो निम्न-मध्यम वर्ग, जो पहले से ही महंगाई के बोझ से दबा है, को कराधान से राहत दें. इसके लिए आयकर की छूट सीमा में कई गुना वृद्धि की जानी चाहिए. महंगाई कराधान का सबसे खराब प्रकार है और इसमें सुधार के संकेत नहीं मिल रहे हैं. यह सरकार सबसे कम जो काम कर सकती है, वह यह कि आयकर के लिए न्यूनतम छूट की सीमा पांच लाख रुपये कर दी जाए.

नई सरकार के सत्ता में आने के एक महीने पूरे हो गए हैं. हालांकि, पिछले एक महीने में नीतिगत घोषणा के अनुसार ज़्यादा कुछ निकल कर सामने नहीं आया है. शासन बदल चुका है, लेकिन वह अभी तक बदलता दिख नहीं रहा है. सरकार को ऐसी नीतियों की घोषणा करनी या नीति बनानी चाहिए, जिससे लोगों को जानकारी मिले कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है. राजनीतिक मोर्चे पर भी किसी प्रशासनिक सुधार के संकेत नहीं हैं, ताकि यह पता चल सके कि वे किस तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं. 1985 में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद नौकरशाही में पदों की संख्या में कई गुना वृद्धि की थी. सचिव स्तर के पद बढ़ गए, सचिवों के पास बहुत कम काम रह गया और बहुत कम महत्व भी रह गया. इस बात की जांच करना बुद्धिमानी होगा कि क्या भारत सरकार के सचिवों की संख्या घटाई जा सकती है, ताकि वे महत्वपूर्ण स्थिति में आ सकें और कुछ परिणामों के साथ काम कर सकें. इस मोर्चे पर कुछ नहीं हो सकता. इसलिए वर्तमान नौकरशाही का ही स्वरूप जारी रहेगा और इसी प्रणाली के तहत दिए गए नोट्स के आधार पर निर्णय लिए जाते रहेंगे, लेकिन इस सबसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन वास्तव में सामने नहीं दिखेगा.

बजट में करदाताओं के लिए कुछ राहत के संकेत मिल रहे हैं. लेकिन किस तरह की राहत? आप वास्तव में राहत देना चाहते हैं, तो निम्न-मध्यम वर्ग, जो पहले से ही महंगाई के बोझ से दबा है, को कराधान से राहत दें. इसके लिए आयकर की छूट सीमा में कई गुना वृद्धि की जानी चाहिए. महंगाई कराधान का सबसे खराब प्रकार है और इसमें सुधार के संकेत नहीं मिल रहे हैं. यह सरकार सबसे कम जो काम कर सकती है, वह यह कि आयकर के लिए न्यूनतम छूट की सीमा पांच लाख रुपये कर दी जाए. इससे प्रति माह 30 से 40 हज़ार रुपये वेतन पा रहे लोग आयकर की सीमा से बाहर हो जाएंगे और उन्हें राहत मिलेगी. लेकिन, नौकरशाही ऐसा कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि इससे वर्तमान करदाताओं में से साठ से सत्तर फ़ीसद करदाता आयकर की सीमा से बाहर निकल जाएंगे. पश्चिम का पारंपरिक ज्ञान यह मानता है कि कराधान का दायरा बड़ा होना चाहिए. भारत में यह लागू नहीं होता. हमारे देश में 70 फ़ीसद लोग कृषि पर निर्भर हैं और हमने संविधान के तहत कृषि पर कर न लगाने का निर्णय लिया हुआ है. बचे 30 फ़ीसद, जिनमें से 15 फ़ीसद पर कर लगाने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वे इतने ग़रीब हैं. तो, देश में कर का कुल आधार 15 फ़ीसद लोग हैं. और, इस 15 फ़ीसद में से शायद एक फ़ीसद वास्तविक करदाता हैं और बाकी लोग किसी तरह जीवनयापन कर रहे हैं और हम उन पर टैक्स चार्ज कर रहे हैं, जो सरासर अनुचित है.

हम पश्चिमी मॉडल का अनुसरण कर रहे हैं और इस वजह से पिछले 20 सालों में सरकार उदारीकरण के बावजूद यह सब नहीं बदल सकी. ज़रूरत इस बात की है कि हम स्वयं का एक मॉडल विकसित करें. मैं नहीं जानता कि वित्त मंत्री क्या सोचते हैं या सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरशाहों के साथ बैठना चाहिए. हमें उनसे पैसा एकत्र करने की ज़रूरत है, जो वास्तव में बहुत पैसा कमा रहे हैं. कॉरपोरेट सेक्टर के लिए कर की दर 35 से बढ़ाकर 40 फ़ीसद और किसी व्यक्ति के लिए इसे 30 से बढ़ाकर 35 फ़ीसद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह करारोपण सिर्फ़ अमीरों पर होना चाहिए, न कि निम्न-मध्यम वर्ग और ग़रीबों पर. किसी भी मामले में वेतनभोगियों पर हम अभी 30 फ़ीसद कर लगाते हैं और व्यापारियों पर भी 30 फ़ीसदी कर लगा रहे हैं. व्यापारी अपने सभी खर्च काटकर सिर्फ़ मुनाफे पर कर देता है, जबकि वेतनभोगी अपनी सकल आय पर 30 फ़ीसद भुगतान कर रहा है, यह अनुचित है. अन्य विधि तलाशी जा सकती है, जिससे वेतनभोगी लोगों का कराधान 10 फ़ीसद तक कम किया जा सके. लेकिन, जब तक आप इस आबादी के लिए राहत नहीं लाते, तब तक राहत का कोई मतलब नहीं रहेगा.

आने वाला भी बजट एक और सामान्य बजट होने जा रहा है, कुछ फ़ीसद ऊपर और कुछ फ़ीसद नीचे के साथ. लोग बदलाव चाहते हैं और सरकार का दावा कि वह बदलाव के लिए आई है, का कोई अर्थ नहीं रहेगा. राजनीतिक मोर्चे पर ग़ैर भाजपाई लोग यानी हम जैसे लोग कुछ बातों को लेकर भयभीत हैं. जैसे कि इस देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का क्या होगा, प्रेस की स्वतंत्रता का क्या होगा, अल्पसंख्यकों के साथ क्या होगा? पुणे में हुई हत्या के क्या संकेत हैं? क्या यह कुछ लोगों द्वारा एक योजना बनाकर की गई हत्या है? यह सब पहले से ही उदार विचारधारा वाले सामाजिक लोकतंत्र के पैरोकारों के बीच भय का माहौल पैदा कर रहा है. आप रेल किराया बढ़ाते हैं, लेकिन आप मध्यम वर्ग के लिए अलग कुछ भी नहीं करते. अगर कराधान के मोर्चे पर राहत नहीं देते हैं, तो क्या बदलाव आप लेकर आएंगे? मैंने अख़बारों में पढ़ा कि बजट 10 जुलाई को आ रहा है. और, आप किस दिशा में सरकार चलाएंगे, उसका भी पहला संकेत मिल चुका है.

केवल एक अच्छी बात कृषि मंत्री की ओर से आई है. उन्होंने कहा है कि किसानों को पहले से बेहतर बीमा दिया जाएगा. अभी इस संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं आई है. मानसून के असफल होने या बाढ़ आने से सबसे अधिक नुक़सान इस देश के किसानों को ही उठाना पड़ता है. नई बीमा योजना से अगर उन्हें कुछ राहत मिलती है, तो वास्तव में यह देश के लिए एक बड़ी बात होगी, क्योंकि खाद्य आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी प्राथमिकता है. पिछले दस वर्षों में कृषि वृद्धि दर अच्छी नहीं रही. यह अलग बात है कि हमें खाद्य संकट से गुजरना नहीं पड़ा. लेकिन, यदि अगले 20 सालों तक ऐसा ही चलता रहा, तो निश्चित तौर पर हमें खाद्य संकट का सामना करना पड़ेगा. कृषि उत्पादन जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में बढ़ाना होगा. आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक विज्ञान, फसल की उपज और उत्पादकता में आधुनिक विकास के साथ तालमेल रखना चाहिए. इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है. हमारे पास आंतरिक विशेषज्ञता है. केवल सरकार को सोचना है कि कैसे कृषि को उद्योग या विनिर्माण क्षेत्र की तरह प्राथमिकता दी जाए.

हम प्रधानमंत्री का दिमाग़ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वह ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं. प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका संवाद प्रधानमंत्री बनने के लिए किए गए चुनाव प्रचार के मुकाबले कम हो गया है. उन्हें एक ऐसी रणनीति बनानी चाहिए, जिससे लोगों को पता लग सके कि उनकी सरकार क्या सोच रही है. एक महीना बीत चुका है. वह बजट के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो अभी आने वाला है. लेकिन, वक्त आ गया है कि सरकार यह बताए कि वह कौन से बड़े बदलाव करने जा रही है और आगे किस तरह से कार्य करेगी? कांग्रेस का पैटर्न हम लोग जानते हैं, भाजपा क्या बदलाव लाएगी, यह नहीं मालूम, लेकिन जितनी जल्दी पता लग जाए, उतना ही बेहतर होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

सरकार के सामने चुनौतियां

मुद्रास्फीति अगले छह से नौ माह के बाद ही कम हो पाएगी. सरकारी खजाने पर दोष मढ़ना अब पुरानी बात हो चुकी है. असली नीति वह होगी, जिसमें अनाज को भंडार गृहों से बाहर निकाला जाए, दुर्लभ वस्तुओं को नियमित समय अंतराल पर मंगाया जाए और परेशानियों का स्थायी समाधान करते हुए आपूर्ति की बाधाएं समाप्त की जाएं. आगामी बजट ही सरकार के काम करने का तरीका बता पाएगा. यह बजट सरकार के लिए कठिन भी होगा, क्योंकि पिछली सरकार ने उसके लिए काफी परेशानियां पहले से छोड़ रखी हैं.

मेघनाद देसाई

एक बार पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरॉल्ड मैकमिलन से यह पूछा गया कि वह किस बात को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित होते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था, अवांछित घटनाएं मेरे दोस्त. भारत में नई सरकार बने अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और उसे अभी से ही यह महसूस होने लगा है कि उसके इर्द-गिर्द की दुनिया कितनी कठिन है. सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद एक सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत हो गई, मेघवाल के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला एक बार फिर खुल गया (आख़िर जब तक उनका केस समाप्त नहीं हो जाता, उन्हें निलंबित क्यों नहीं किया जा सकता), प्याज के मूल्यों में एकदम से उछाल आ गया. अब इराक की परेशानी और वहां फंसे भारतीयों की समस्या मुंह बाये खड़ी हो गई है. भाजपा सरकार को लोगों ने बहुत ही आशा के साथ चुना था. प्रधानमंत्री ने हमें उस समय आश्चर्यचकित भी कर दिया था, जब उन्होंने दक्षेस देशों के प्रमुखों को अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बुलाया था. इस आश्चर्य को और बल तब मिला, जब उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी सरकार चौबीसों घंटे काम करने वाली होगी, उनके साथियों द्वारा अनुशासन दिखाया जाएगा और कैबिनेट के पदों के लिए कलह खुलेआम नहीं दिखाई देगी. साथ ही उनकी भूटान यात्रा ने भी काफी संतोष दिया.

लोगों के लिए यह सुखद था कि अब देश के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है, जो जनता से बात करता है, न कि सिर्फ़ संसद से. इसके बावजूद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह जनता को समझा पाने में कामयाब हो जाए कि सबसे बेहतरीन प्रयास करने के बावजूद स्थितियां बेहतर होने में समय लगेगा. मुद्रास्फीति अगले छह से नौ माह के बाद ही कम हो पाएगी. सरकारी खजाने पर दोष मढ़ना अब पुरानी बात हो चुकी है. असली नीति वह होगी, जिसमें अनाज को भंडार गृहों से बाहर निकाला जाए, दुर्लभ वस्तुओं को नियमित समय अंतराल पर मंगाया जाए और परेशानियों का स्थायी समाधान करते हुए आपूर्ति की बाधाएं समाप्त की जाएं. आगामी बजट ही सरकार के काम करने का तरीका बता पाएगा. यह बजट सरकार के लिए कठिन भी होगा, क्योंकि पिछली सरकार ने उसके लिए काफी परेशानियां पहले से छोड़ रखी हैं. यहां तक कि रूटीन खर्चों के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी. सरकार को थोड़ी आलोचनाएं झेलनी ही होंगी और तेल के दामों में वृद्धि करनी होगी. हम पेट्रोल का इस्तेमाल करने वालों को ग़रीब नहीं कह सकते हैं. एक भी रुपये की सब्सिडी दिए जाने का मतलब है कि घाटे को एक रुपये और बढ़ाना, जिसकी वजह से मुद्रा स्फीति ज़्यादा समय तक टिकी रहेगी. मूल्यों में सब्सिडी दिया जाना किसी भी रूप में मुद्रा स्फीति का जवाब नहीं है.

लेकिन वर्तमान समय में जो डराने वाली बात है, उसका संबंध तेल के मूल्यों से नहीं है. वह है, इराक की समस्या. पूर्व में ऑटोमान साम्राज्य का हिस्सा रहे इस स्थान पर काफी लंबे समय से शिया और सुन्नी के बीच जंग चल रही है. 19वीं सदी के दौरान दक्षिण एशिया के मुस्लिम इस्तांबुल में बैठे खलीफा को अपना आध्यात्मिक नेता मानते रहे. पहले विश्व युद्ध के दौरान जब ऑटोमान साम्राज्य हार गया, तो उसके सहयोगियों द्वारा नई सीमा रेखाएं तय की गईं, जो वर्तमान समय में एक बार फिर से खींची जा रही हैं. सीरिया, इराक, लेवनॉन एवं जॉर्डन के अलावा भी शिया और सुन्नी के आधार पर दूसरे देश बन सकते हैं, जिनमें एक नया कुर्दिस्तान भी हो सकता है. ये नए देश पुरानी सीमा रेखाओं को बदल सकते हैं. सीरिया भी दो भागों में बंट सकता है, जिनमें एक असद की सरकार वाला सीरिया होगा और बाकी का हिस्सा अलग होगा. सुन्नियों के कब्जे वाले हिस्सों पर भी अलग देश शायद बने. यह समस्या सीरिया के गृह युद्ध की शुरुआत के बाद से ही लगभग तीन सालों से चल रही है, जो इराक तक फैल गई है.

इस्लामिक चरमपंथी ज़्यादातर उन देशों में सरकार के विरोधी बने हुए हैं, जहां पर मुसलमानों की बहुलता है. वे इन देशों में चरमपंथियों की सरकार बनाना चाहते हैं और किसी भी लोकतांत्रिक या तानाशाही सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं. हम इस्लाम के दो समुदायों के लगभग 1300 साल पुराने बंटवारे के सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं. अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तो वह दोनों तरह की समस्याओं की चपेट में है. जहां एक तरफ़ तालिबान सरकार से लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ़ वह शियाओं को भी मौत के घाट उतार रहा है.

इस्लामिक चरमपंथी ज़्यादातर उन देशों में सरकार के विरोधी बने हुए हैं, जहां पर मुसलमानों की बहुलता है. वे इन देशों में चरमपंथियों की सरकार बनाना चाहते हैं और किसी भी लोकतांत्रिक या तानाशाही सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं. हम इस्लाम के दो समुदायों के लगभग 1300 साल पुराने बंटवारे के सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं. अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तो वह दोनों तरह की समस्याओं की चपेट में है. जहां एक तरफ़ तालिबान सरकार से लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ़ वह शियाओं को भी मौत के घाट उतार रहा है. भारत सरकार को इस बात के लिए चौकन्ना रहना चाहिए कि देश में अगला दंगा शिया और सुन्नी के बीच भी हो सकता है. आलोचक चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की आलोचना इस बात को लेकर करते रहे हैं कि वह मुस्लिम विरोधी है. खैर, आलोचक कुछ भी कहें, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि अगर ऐसी कोई विषम परिस्थिति बने, तो सरकार को यह दिखाना होगा कि वह पूरे देश के लिए है, न कि सिर्फ़ किसी एक समुदाय के लिए.■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

प्रधानमंत्री जी, यह परीक्षा की घड़ी है

हम अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करते हैं. हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अनुरोध करना चाहते हैं. आपने 14.20 प्रतिशत किराया बढ़ाकर 8000 करोड़ रुपये साल में इकट्ठा करने का सुहावना लक्ष्य देश के सामने रखा यह कहकर कि रेलवे कमजोर है, खस्ताहाल है, घाटे में चल रही है, इसलिए आपको 8000 करोड़ रुपये सालाना चाहिए. आपके अधिकारी एवं रेल मंत्री यह क्यों भूल गए कि देश के हर रेलवे स्टेशन पर कुछ न कुछ स्टील जंक पड़ा हुआ है, स्क्रैप पड़ा हुआ है. चाहे वह पुराने डिब्बों की शक्ल में हो, पुराने लोहे के स्लीपर की शक्ल में हो, पुरानी रेलवे लाइनों की शक्ल में हो.

उर्दू का एक शेर है, उसे अपनी तरह से कहने की कोशिश करते हैं, किस-किस पे ख़ाक डालिए, किस-किस पे रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढंक के सोइए. सचमुच मुंह ढंक के सोने की ख्वाहिश हो रही है. कांग्रेस ने इस देश को 60-65 सालों में जो दिया, उसे हम भुगत रहे हैं. पूरा देश आपसी रंजिश की कगार पर है, विघटन की कगार पर है, निराशा की कगार पर है. जब कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि सरकार महंगाई घटाने के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो हंसी आती है, क्योंकि बुनियादी तौर पर महंगाई कांग्रेस की ही देन है.

अभी मोदी सरकार की बात करें. पूरे चुनाव के दौरान ऐसा लगा, जैसे हमारे बीच अचानक एक अवतार आ गया. धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कल्कि अवतार होगा कलयुग में. कल्कि अवतार होगा, जो देश को विनाश से बचाएगा. नरेंद्र मोदी कल्कि अवतार के रूप में दिखाई दिए और उन्होंने वैसे ही छाप सारे देश में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान छोड़ी. देश में महंगाई है, इलाज नरेंद्र मोदी के पास है. बेरोज़गारी है, इलाज नरेंद्र मोदी के पास है. भ्रष्टाचार है, इलाज नरेंद्र मोदी के पास है. लेकिन इलाज क्या है, यह नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं बताया. फिर भी देश ने भरोसा किया और एक गुजरात मॉडल को अपने मन में एक काल्पनिक संभावनाओं का मॉडल बना लिया. क्या गुजरात मॉडल, कैसा गुजरात मॉडल, किसी को नहीं पता, पर लोगों के दिमाग में गुजरात मॉडल बस गया. नरेंद्र मोदी जी एक नए अवतार के रूप में कलयुग में तारणहार के रूप में प्रधानमंत्री बन गए.

प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 100 दिनों के एजेंडे की बात की. अपने मंत्रियों से कहा कि वे उन्हें सौ दिनों का एजेंडा बनाकर दें और 100 दिनों के बाद वह उनसे उस एजेंडे पर क्या हुआ, इसकी जानकारी लेंगे. वैसे यही काम मनमोहन सिंह ने भी, जब वह 2009 में जीतकर दोबारा आए थे, तब किया था. न उनके किसी मंत्री ने 100 दिनों का एजेंडा बनाया, न उन्होंने कभी 100 दिनों की रिपोर्ट देश के सामने रखी. नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी कौन सा एजेंडा बनाया है, यह देश को नहीं पता. नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पहले 30 दिन बीत गए. आने वाले साठ दिनों में किस एजेंडे पर काम होगा, यह देश को नहीं पता. देश के लोगों को सिर्फ़ यह पता है कि उन्होंने जो आशाएं लगा रखी थीं, उनके ऊपर हल्की सी धूल की परत जम गई. धूल की परत इसलिए, क्योंकि देश के लोगों को लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी को पूरे सौ दिन मिलें और उनकी आलोचना न हो, तो शायद उनकी समस्याएं हल करने में मोदी जी कामयाब होंगे. लेकिन पहला झटका लोगों को लगा, रेल के किराये में 14.20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गई, जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई. चीनी के दाम में बढ़ोत्तरी हुई और ऐसा लगता है कि अब अनाज एवं दालों के दामों में भी बढ़ोत्तरी होगी और कालाबाज़ारी होगी, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री दोहरा चुके हैं कि अगर जमाखोर यह सब सामान अपने यहां दबाकर रखेंगे, तो वह विदेशों से मंगा लेंगे. विदेशी कंपनियों की दौड़ हमारे देश में शुरू हो गई है, जो यहां अनाज और दालें बेचना चाहती हैं.

सरकार को राय कौन दे सकता है और सरकार किससे राय मांग सकती है. सरकार सार्वभौम है, सरकार सर्वगुण संपन्न है, सरकार के पास दिमाग़ ही दिमाग़ है, लेकिन इसके बावजूद न मनमोहन सिंह ने महंगाई घटाई और न अब नरेंद्र मोदी महंगाई घटाने की बात कर रहे हैं. वह कड़वे घूंट, कड़वी दवा की बात कर रहे हैं, कड़े क़दमों की बात कर रहे हैं. इन कड़वी दवाओं और कड़े क़दमों का भुगतान सिर्फ़ देश के ग़रीबों को करना पड़ता है, अमीरों को नहीं. नरेंद्र मोदी की सरकार के भीतर क्या कोई समझदार आदमी नहीं है, जो मंत्रिमंडल में नए ढंग की सोच सामने रखे? मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सोचने में सक्षम हैं, लेकिन क्या उन्हें सोचने का वक़्त मिलता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि देश की समस्याओं के हल के लिए बिल्कुल नए तरीके अपनाए जाएं, जिनसे समस्याएं बढ़ें नहीं, समस्याओं का ग्राफ वहीं रुक जाए और फिर धीरे-धीरे उन्हें नीचे लाने की कोशिश की जाए?

देश का बजट जुलाई में आने वाला है. यह बजट नरेंद्र मोदी की असली परीक्षा है, पर पहली परीक्षा में उन्होंने देश के लोगों को एक अलग तरह की निराशा दी. उनके रेल मंत्री और वित्त मंत्री ने कहा कि यह तो कांग्रेस सरकार का फ़ैसला था, जिसे हमने लागू किया. क्या मजबूरी थी आपकी इसे लागू करने की? आप पंद्रह दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? आप बजट में व्यापक दृष्टिकोण या समग्र दृष्टिकोण देश के सामने रखते कि विभिन्न समस्याओं को हल करने का आपका आर्थिक नज़रिया क्या है. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ और जमकर रेल का किराया बढ़ाया गया. और, अपना दिवालियापन आपने बता दिया यह कहकर कि हमने तो कांग्रेस के फ़ैसले को लागू किया. अगर कांग्रेस का ही फ़ैसला लागू करना था, तो देश की जनता ने आपको क्यों जिताया? आपको लोगों ने इसलिए जिताया कि आपने कहा था कि आप सत्तर सालों से चल रही गड़बड़ियां ठीक करेंगे. आप देश को उसका सम्मान दिलाएंगे और लोगों की ज़िंदगी में कुछ खुशियां लाएंगे.

हम अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करते हैं. हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अनुरोध करना चाहते हैं. आपने 14.20 प्रतिशत किराया बढ़ाकर 8000 करोड़ रुपये साल में इकट्ठा करने का सुहावना लक्ष्य देश के सामने रखा यह कहकर कि रेलवे कमजोर है, खस्ताहाल है, घाटे में चल रही है, इसलिए आपको 8000 करोड़ रुपये सालाना चाहिए. आपके अधिकारी एवं रेल मंत्री यह क्यों भूल गए कि देश के हर रेलवे स्टेशन पर कुछ न कुछ स्टील जंक पड़ा हुआ है, स्क्रैप पड़ा हुआ है. चाहे वह पुराने डिब्बों की शक्ल में हो, पुराने लोहे के स्लीपर की शक्ल में हो, पुरानी रेलवे लाइनों की शक्ल में हो. एक मोटा अनुमान है कि 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपये का स्क्रैप रेलवे के पास सारे देश में है. क्या आपके रेल मंत्री यह जानकारी मंगाने का आदेश नहीं दे सकते थे कि सारे देश में रेलवे के पास कितना स्क्रैप है? हो सकता है, वह 30 हज़ार करोड़ रुपये का भी हो. जब यह जानकारी आती, तो उस स्क्रैप को नीलाम कर देते. रेलवे का स्क्रैप खरीदने के लिए सारी दुनिया में होड़ मच जाती. आपको एक रात में 30 हज़ार करोड़ रुपये का मुनाफा हो जाता. आपने 8000 करोड़ रुपये के लिए, जो आपको साल भर में मिलेंगे, देश के लोगों की आशाएं तोड़ीं और यह बताया कि आपके सोचने का तरीका कांग्रेस से बिल्कुल भिन्न नहीं है. आप अगर नए सिरे से सोचते, तो लोगों के ऊपर बोझ नहीं पड़ता और आपके पास जगह घेरने वाला बेकार पड़ा स्क्रैप बाज़ार में रिसाइकिल होकर नए उत्पादन में इस्तेमाल होता. लेकिन, रेल मंत्री ने यह नहीं सोचा, तो प्रधानमंत्री जी, आपका तो कर्तव्य बनता है कि आप सोचें, आप मुखिया हैं. देश के लोगों ने रेल मंत्री के नाम पर वोट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर भी वोट नहीं दिया. देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया है, आपको 282 सीटें दी हैं.

इसी तरह एक दूसरा सुझाव है कि देश के नए उद्योगों के लिए क्या सेंट्रल एक्साइज हॉली-डे की घोषणा नहीं की जा सकती, जिसकी कम से कम अवधि दस साल हो. अगर आप इस बजट में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, पंजाब के ड्रग्स (नशा) प्रभावित ज़िलों और पहाड़ी क्षेत्रों में टैक्स हॉली-डे, सेंट्रल एक्साइज हॉली-डे की घोषणा करें, तो वहां पर बहुत सारे उद्योग चले जाएंगे. ये उद्योग ज़िले या प्रदेश के आधार पर टैक्स हॉली-डे के लिए न चुने जाएं, बल्कि उन ब्लॉकों को चुना जाए, जो निहायत ग़रीब और पिछड़े हैं, जिनके आंकड़े भारत सरकार के पास हैं. उन ब्लॉकों-प्रखंडों में दस साल का टैक्स हॉली-डे अगर आप घोषित करें, तो वहां पर जो उद्योग जाएंगे, उनसे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा. और, यह रोज़गार बढ़ाने का एक प्राथमिक तरीका हो सकता है. यह आपको तब तक सांस लेने का अवसर दे सकता है, जब तक आप रोज़गार की कोई व्यापक योजना सामने लाएं, जिसके लिए आपको कम से कम चार-पांच महीने का वक़्त चाहिए. अगर आप ग्रामीण उद्योग आधुनिक तकनीक से लगाने का फ़ैसला करते हैं, तब भी आपको पांच-छह महीने चाहिए, अन्यथा उद्योग या रोज़गार के अवसर सृजित करना आपकी सरकार के वश की बात होगी, इसमें संदेह है.

तीसरी चीज, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह कि हमारे देश में अन्न बहुत नष्ट होता है. खुले रूप में अनाज गोदामों में रखा जाता है. हमारे पास भंडारण की सुविधा नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं हैं. ऐसे स्थान नहीं हैं, जो टैम्प्रेचर कंट्रोल्ड गोदाम हों और वहां पर अनाज रखा जा सके. कोल्ड स्टोरेज की कमी देश के उन फसलों को नुक़सान पहुंचा रही है, जिन्हें हम साल भर तक स्टोर करना चाहते हैं. क्या यह नहीं हो सकता कि सरकार देश के लोगों से कहे कि आप इन-इन पैमानों पर कोल्ड स्टोरेज बनाएं, इस पैमाने के ऊपर आप टैम्प्रेचर कंट्रोल्ड गोदाम बनाएं और उनका किराया इस हिसाब से सरकार से लें. सारे देश के हर ब्लॉक में आप जितने चाहें, उतने भंडारण गृह खड़े कर सकते हैं. इसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ़ एक शर्त लगाई जाए यानी जो स्पेशिफिकेशन सरकार या जिला अधिकारी दे, उसी के ऊपर ये भंडारण गृह और कोल्ड स्टोरेज बनें. आप घोषणा कीजिए कि हम उसका किराया देंगे. आपका वह पैसा बच जाएगा, जो गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनने में लगना है. लोग अपने आप खड़े हो जाएंगे और आपका सारा अनाज सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन यह फ़ैसला लेना आसान है क्या? यह फ़ैसला लेना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे कार्यों में कमीशन नहीं होते. आप अगर लोगों को रोज़गार देने की नज़र से फ़ैसले करें, तो कमीशन नहीं मिलता.

देश में ऊर्जा की कमी है, क्या आप खुले तौर पर यह नहीं कह सकते कि जो कंपनी चाहे, वह देश में सौर ऊर्जा के बिजली घरों का निर्माण करे, अपना पैसा लगाए. सरकार एक रेट तय कर दे कि इस रेट से वह सौर ऊर्जा की बिजली खरीदेगी. कंपनियां हैं, लोग हैं, जो अपना पैसा लगाकर हर गांव को बिजली घर के रूप परिवर्तित कर सकते हैं या ज़िलों में दस, बीस, तीस, चालीस, पचास, सौ मेगावाट के विद्युत उत्पादन केंद्र बनाकर उस बिजली को सरकार के ग्रिड में डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हर जगह आपको लाइसेंस देना है. हर जगह परमीशन देने के नाम पर फाइल लटकानी है. नरेंद्र मोदी जी, दुर्भाग्य यह है कि सिस्टम के सामने देश नहीं है, सिस्टम के सामने पैसा है. इसलिए आपको कड़े फ़ैसले नए नज़रिए से लेने पड़ेंगे. आपको बहुत सारी चीजों में लाल फीताशाही हटानी होगी और लोगों को उत्साहित करना होगा कि वे लाल फीताशाही के ख़िलाफ़ खड़े हों और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ भी.

प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि आप भ्रष्टाचार से टेक्नोलॉजी के जरिये लड़ेंगे. तीस दिन बीत गए, हमें टेक्नोलॉजी कहीं नज़र नहीं आई. हमारी साधारण समझ में टेक्नोलॉजी का मतलब पारदर्शिता है यानी जो फ़ैसले हों, वे रिकॉर्ड हों, ऑडियो रिकॉर्ड हों या वीडियो रिकॉर्ड हों. और, एक समय रखा जाए, जिसमें वे सारी की सारी चीजें बाहर लाई जाएं. तभी फ़ैसला लेने वालों के मन में डर होगा कि फ़ैसला लेते समय उनकी बातचीत या उनके तर्क अगर देश के सामने आ गए, तो उनका जीना मुहाल हो जाएगा. इसी तरह से ज़िम्मेदारी तय कीजिए. आदमी रिटायर हो जाए, इसके बावजूद अगर उसके समय में लिया गया फ़ैसला ग़लत है, तो उसके ऊपर ज़िम्मेदारी डालिए. यह देश आपकी तरफ़ बड़ी आशा से देख रहा है. अगर यह आशा टूटी, तो आप एक बहुत बड़े निगेटिव मूवमेंट के लिए तैयार रहिए, एक विध्वंसक आंदोलन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपका असफल होना नक्सलवादियों, उग्रवादियों को नए तर्क देगा. और, अगर आप जनाभिमुख आर्थिक नीतियां नहीं लाए और कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियां इस बजट में आईं, तो प्रधानमंत्री जी, मुझे विनम्रता से यह कहने की इजाजत दीजिए कि इसी बात की प्रतीक्षा तो वे लोग कर रहे हैं, जिनका अहिंसा में विश्वास नहीं है. आपके सामने यक्ष प्रश्न जैसे सवाल है कि आप देश के लोगों को प्रमुख मानते हैं या अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेट बिरादरी को? प्रधानमंत्री जी, यहीं पर देश की परीक्षा है और यहीं पर आपकी परीक्षा है.■

editor@chauthiduniya.com

सर्वाइकल कैंसर

लक्षणों की पहचान बहुत ज़रूरी

प्रियंका प्रियम तिवारी

कुछ खास तरह के कैंसर सिर्फ़ महिलाओं को होते हैं, जिन्हें गायनॉलोजिकल कैंसर कहते हैं और जो जनन अंगों से संबंधित होते हैं. महिलाएं इनके शुरुआती लक्षणों को पहचान नहीं पातीं. ये कैंसर महिलाओं के पेल्विक रीजन की विभिन्न जगहों पर हो सकते हैं, जैसे पेट और हिप बोन्स के बीच, कहीं भी.

गायनॉलोजिकल कैंसर
1. सर्वाइकल
2. यूटेराइन
3. ओवरीअन
4. वल्वर
5. वजायनल

लक्षण

पीरियड के अलावा अन्य दिनों में भी ब्लीडिंग एवं डिस्चार्ज होना, वल्वा की त्वचा में बदलाव, हमेशा बुखार महसूस करना, पेल्विक एरिया में दर्द और दबाव महसूस करना, वजायनल इचिंग एवं बर्निंग, बैक एवं एब्डोमेनल पेन, हमेशा थकान महसूस होना, युरिन में परेशानी, फाउल स्मेलिंग ऑफ डिस्चार्ज, मैनोपॉज के बाद रक्तस्राव. इनमें स्क्रीनिंग सिर्फ़ सर्वाइकल कैंसर की हो पाती है.

सर्वाइकल कैंसर

दुनिया में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों के आंकड़े सबसे ज़्यादा हैं. 80 प्रतिशत मामले विकासशील देशों की महिलाओं से संबंधित हैं. अकेले भारत में इस बीमारी से हर 7वें मिनट में एक महिला की मौत हो जाती है. दुनिया भर में हर साल इस गंभीर बीमारी के कारण 2.73 लाख महिलाओं की मौत हो जाती है.

क्यों होता है सर्वाइकल कैंसर

गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर गर्भाशय के प्रवेश द्वार का कैंसर है. इस बीमारी की मुख्य वजह है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी). सर्वाइकल कैंसर किसी भी सेक्सुअली एक्टिव महिला को हो सकता है, लेकिन इस बीमारी का ख़तरा 40 वर्ष से ज़्यादा की महिलाओं में बढ़ जाता है. एशियन स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस के डॉ. एन के पांडे के मुताबिक, सर्वाइकल कैंसर बदलती जीवन शैली की देन है. पिछले कुछ समय से महिलाओं के बीच सिगरेट और शराब का चलन बढ़ा है, जो कैंसर का जोखिम बढ़ाता है. बार-बार होने वाली प्रेग्नेंसी, मल्टीपल पार्टनर्स और जेनेटिक कारणों से भी यह बीमारी होती है. यदि कोई व्यक्ति एचपीवी से संक्रमित है, तो उसके साथ यौन संबंधों से भी यह बीमारी हो सकती है. कैंसर विशेषज्ञ कहते हैं कि एचपीवी इंफेक्शन से बचाव के लिए वैक्सीन और नियमित स्क्रीनिंग बेहद ज़रूरी है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक, प्रत्येक 3 साल में 18 से 69 वर्ष की सभी भारतीय महिलाओं में से मात्र 2.6 प्रतिशत की स्क्रीनिंग हो पाती है.

टीकाकरण

इस बीमारी से बचाव के लिए दो तरह के टीके उपलब्ध हैं:-

सर्वारिक्स : यह एचपीवी-16 और एचपीवी-18 के संक्रमण को काफी हद तक रोकता है. 70 प्रतिशत सर्वाइकल कैंसर के लिए यही दोनों वायरस ज़िम्मेदार होते हैं (डोज शेड्यूल-0, 1, 6 माह के अंतराल पर).

गार्डसिल : यह टीका एचपीवी-16, एचपीवी-18, एचपीवी-6 और एचपीवी-11 के संक्रमण से बचाता है (डोज शेड्यूल-0, 2, 6 माह के अंतराल पर).

इन्हें 9 से 26 साल की लड़कियों को दिया जा सकता है. 45 साल तक की महिलाएं भी इन्हें लगवा सकती हैं. ये सर्वाइकल कैंसर का जोखिम कम करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि जिन्होंने टीकाकरण करा लिया हो, वे भी साल में एक बार पैप टेस्ट कराएं.

कंडोम सुरक्षा कवच नहीं

आम तौर पर लोग मानते हैं कि कंडोम का इस्तेमाल करके वे किसी भी तरह के इंफेक्शन से बच सकते हैं, पर असल में वह उसी भाग को सुरक्षित रखता है, जिसे कवर करता है. जबकि एचपीवी शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है.

नियमित जांच जरूरी

पैप स्मियर टेस्ट : सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए महिलाओं को पैप स्मियर टेस्ट कराना चाहिए. इस टेस्ट में सर्विक्स में कैंसरस और प्री-कैंसरस सेल्स के बारे में पता लगाया जाता है. इससे विभिन्न तरह के इंफेक्शंस और ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में भी पता चल जाता है. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एच-पीवी 8 से 10 वर्ष बाद अपना प्रभाव दिखाता है. यह टेस्ट पहले रिलेशनशिप के तीन साल बाद कराना चाहिए. आईसीएमआर(इंडियन कांउसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) गाइड लाइन के मुताबिक, किसी भी सेक्सुअली एक्टिव महिला को साल में एक बार यह टेस्ट कराना चाहिए. इसके अलावा डीएनए टेस्टिंग और लिक्विड वेस्ट साइटोलॉजी भी कराई जा सकती है. पैप स्मियर टेस्ट 600-800 रुपये में हो जाता है.

पैप स्मियर कराने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें...

- पीरियड के दौरान या उससे 4-5 दिन बाद तक यह टेस्ट नहीं कराना चाहिए.
- टेस्ट कराने से 24 घंटे पहले फिजिकल रिलेशनशिप में न रहें.
- इस टेस्ट से पहले प्राइवेट पार्ट में किसी तरह का कोई लोशन या क्रीम न लगाएं.

साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट

कैंसर के मरीज असहनीय पीड़ा सहते हैं, मानसिक पीड़ा से भी गुजरते हैं. इलाज के दौरान महिलाओं के कई अंग रि-मूव करने पड़ते हैं, जो भावनात्मक रूप से एक महिला के लिए काफी कष्टप्रद स्थिति होती है. कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंसेस के निदेशक डॉ. सुनील मित्तल कहते हैं कि मानसिक तनाव को शारीरिक या भावनात्मक दबाव के रूप में महसूस किया जा सकता है. डॉक्टर मित्तल कहते हैं कि ऐसे समय में तनाव से कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. कैंसर के मरीजों को भावनात्मक सहारा मिले, तो वे इस बीमारी से बखूबी लड़ सकते हैं. इलाज के साथ-साथ उन्हें रिलैक्सेशन, ध्यान, व्यायाम और स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए. उनकी काउंसलिंग या टॉक थेरेपी भी कराई जानी चाहिए. ■

उपचार

सर्जरी : कैंसर के प्रारंभिक अवस्था में होने पर गर्भाशय निकालने के लिए सर्जरी (हिस्टेरेक्टॅमी) की जाती है. हिस्टेरेक्टॅमी गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय निकालने के लिए की जाने वाली एक सर्जरी है, जबकि रैडिकल हिस्टेरेक्टॅमी में गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय, दोनों अंडाशय, योनि का भाग और उस क्षेत्र में लिम्फ नोड्स को सर्जरी के जरिये हटाया जाता है.

कीमो थेरेपी: कीमो थेरेपी ड्रग्स वेन्स द्वारा दिए जाते हैं. इनका इस्तेमाल कैंसर के सेल्स ख़त्म करने के लिए किया जाता है. इन्हें एंटी कैंसर ड्रग्स या कीमो थेरेपी एजेंट भी कहा जाता है. किमोथेरेपी के विशेषज्ञ डॉक्टरों को ओंकोलॉजिस्ट कहा जाता है. किमो थेरेपी से कैंसर सिकुड़ जाता है और शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैल पाता. ये ड्रग्स इंजेक्शन या दवाइयों के रूप में लिए जाते हैं.

रेडिएशन: इस थेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने और ट्यूमर हटाने के लिए एक्स-रे का प्रयोग किया जाता है. रेडिएशन थेरेपी को सर्जरी एवं किमो थेरेपी के साथ सम्मिलित रूप से भी इस्तेमाल किया जाता है. किमो थेरेपी के अंतर्गत कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है. ■

बाज़ार तय कर रहा है आवश्यक दवाओं के दाम

देश में उदारीकरण के बाद स्वास्थ्य सुविधाएं आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हो गई हैं. कोई आम आदमी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में इलाज कराने का सपना भी नहीं देख सकता है. विकल्प सरकारी अस्पताल हैं. लेकिन, जब ज़रूरी दवाएं भी न मिलें, तो उसका जीवन भगवान भरोसे ही रह जाता है.

नवीन चौहान

यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में पेट्रोलियम पदार्थों से लेकर दवाइयों तक, अधिकांश आवश्यक वस्तुओं की क़ीमत का निर्धारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाज़ार के हवाले कर दिया. कुछ साल पहले तक आवश्यक दवाओं की क़ीमत का निर्धारण कॉस्ट बेस्ड प्राइजिंग (सीबीपी) मेकनिज्म के आधार पर किया जाता था, लेकिन अब यह कार्य मार्केट बेस्ड प्राइजिंग (एमबीपी) मकेनिज्म के आधार पर किया जा रहा है. सीबीपी के तहत दवा के निर्माण में आई कुल लागत में एक निश्चित सीमा तक मुनाफा जोड़कर दवा की ख़ुदरा(रीटेल) कीमत निर्धारित की जाती थी. इसके लिए मूल्य निर्धारण नियामक यानी नेशनल फॉर्मासुटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) दवा निर्माताओं की यूनिटों में सीधे जाकर दवा निर्माण में आने वाली लागत के आंकड़े एकत्र करती थी. लागत मूल्य प्राइज रेगुलेटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे. इसे मेनीपुलेट करने की कंपनियां हरसंभव कोशिश करती थीं. उदाहरण के लिए नई तकनीक के उपयोग के नाम पर कंपनियां हमेशा अपनी लागत को बढ़ाना चाहती थीं. 2011-12 की शुरुआत में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सभी कंपनियों, जिनमें औषधि निर्माता कंपनियां भी शामिल थीं, को उत्पाद बनाने में आई लागत के आंकड़े जारी करने का निर्देश दिया. इसके बाद से दवा कंपनियों द्वारा लागत के उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का उपयोग दवाओं के रीटेल प्राइज निर्धारण करने में किया जाने लगा.

वर्ष 1990 के बाद ड्रग प्राइज कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) के अंतर्गत आने वाली दवाओं की संख्या में लगातार कमी आने लगी. 1979 में डीपीसीओ के अंतर्गत 347 दवाएं आती थीं, जो कि वर्ष 1987 में घटकर 142 और 1995 में घटकर केवल 76 तक पहुंच गईं. 2002 में जो नीति प्रस्तावित थी, उसमें यह संख्या घटकर 35 हो गई होती, लेकिन भला हो सिविल सोसायटी का, जिसने सरकार के इस फैसले के विरोध में आवाज उठाई. इस मसले सुनवाई करते हुए 2003 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस नीति पर रोक लगा दी. इसके बाद से ही इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित था. इसके बाद एक नई नीति का आगमन सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का सीधा-सीधा परिणाम है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को न केवल सभी जीवन रक्षक दवाओं को प्राइज कंट्रोल के दायरे में लाने का निर्देश दिया, बल्कि 1995 की सीबीपी मेकेनिज्म को भी यथावत रखने को कहा. वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) जारी करने का निर्देश दिया. सरकार ने एनएलईएम-2011 जारी की. इसके बाद औषधि विभाग ने नई औषधि नीति पर काम करते हुए विभिन्न पक्षों के साथ बातचीत शुरू की. बड़े और मझोले औषधि उत्पादक बाज़ार आधारित क़ीमत निर्धारण के तरीके के पक्ष में थे, जबकि छोटे औद्योगिक संस्थान कॉस्ट बेस्ड प्राइजिंग (सीबीपी) मेकेनिज्म को यथावत रखने के पक्ष में थे. यहां तक कि सरकार में भी इसे लेकर दो धड़े थे, जो क़ीमत निर्धारण के अलग-अलग तरीकों की पैरवी कर रहे थे. पिछले तीन दशकों में न केवल कंट्रोल्ड दवाओं की संख्या में कमी आई, बल्कि कंट्रोल कैटेगरी की संख्या भी घटी है, जबकि इस दौरान कई दवाइयां पेटेंट के दायरे से बाहर आ गईं. बावजूद इसके, उनकी क़ीमतों में कमी नहीं हुई. दवा निर्माताओं के मुनाफे में लगातार इजाफा होता गया. 1995 के प्राइज कंट्रोल ऑर्डर ने उत्पादन के बाद के खर्च को बढ़ाकर लागत का 100 प्रतिशत कर दिया था, जबकि 1979 में यह 40 से 75 प्रतिशत के बीच सीमित था. इससे यह ज़ाहिर होता है कि सरकार संविधान की लोक कल्याणकारी राज्य की भावना को ताक पर रखकर दवा निर्माताओं के कल्याण की नीतियां बना रही थी. नई नीति में आवश्यक औषधियों की क़ीमतों का निर्धारण मार्केट बेस्ड प्राइज के जरिए करने के पीछे सरकार का तर्क था कि वर्ष 2015 के अंत तक अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों में लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की दवाएं पेटेंट से बाहर होंगी. उसके बाद उत्पन्न होने वाली निर्यात की संभावनाओं का लाभ देश नहीं उठा पाएगा. नई नीति की मदद से कंपनियों को खुद को उचित मूल्य बैंड में रखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा, जिससे वे वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा का भी सामना कर सकेंगी.

एनएलईएम-2011 में सूचीबद्ध दवाओं का नियंत्रण मूल्य दवा की खुराक और ताकत के आधार पर निर्धारित होता है. आज आवश्यक दवाओं की क़ीमत का निर्धारण निम्न फॉर्मूले के आधार पर हो रहा है:- (बाज़ार में संबंधित दवा की बिक्री में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखने वाली तीन कंपनियों का भारित औसत मूल्य(डब्लूएपी)+ बाजार में एक प्रतिशत या उससे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियों का डब्लूएपी)/दवा का उत्पादन करने वाले उत्पादकों की कुल संख्या.

वर्ष 1979 में औषधियों के दाम निर्धारित करने का सीधा और सरल तरीका ड्रग प्राइज कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) के रूप में जारी किया गया था. इसके बाद 1986 एवं 1995 में डीपीसीओ अपने लिए ताकत आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3 से हासिल करते रहे. वर्ष 1979 की नीति और इसके बाद की नीतियों के निर्माण में जयसुख लाल हाथी आयोग की रिपोर्ट की प्रमुख भूमिका रही. दवा बाज़ार का चरित्र मोनापोली के माध्यम से समझा जा सकता है. दवा बाज़ार पर कुछ कंपनियों की मोनोपोली होती है.बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाएं सामान्य तौर पर सबसे मंहगी या महंगी दवाओं में से एक होती हैं.

दवाओं की कीमत निर्धारण के नए तरीके से जनता को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है. सिप्रॉफ्लॉक्सिन नामक एंटीबायोटिक दवा बाजार में एक कंपनी 9.79 रुपये में बेचती है, वही दवा बाज़ार में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी 73.30 रुपये में बेचती है. बाज़ार में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखने वाली तीन सबसे बड़ी कंपनियों की औसत क़ीमत 67 रुपये और एक प्रतिशत या उससे ज़्यादा हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियों की औसत क़ीमत 50.40 रुपये है. लागत आधारित व्यवस्था के तहत इस दवा की क़ीमत 26.57 रुपये होती है, जबकि बाज़ार आधारित व्यवस्था के तहत यह कीमत 58.70 रुपये है. इसका सीधा मतलब है कि सरकार दवा कंपनियों को दुगने से भी ज्यादा मुनाफा बनने की क़ानूनी तौर पर छूट दे रही है. वह भी उस मुद्दे पर जिसका सीधे तौर पर आम आदमी के जीन-मरने से है. दवा कंपनियां क़ानूनी तौर पर आम आदमी को लूट रही हैं और सरकार आवश्यक दवाओं की कीमतों के नियंत्रण का खोखला दंभ भर रही है. ■

navinonline2003@gmail.com

राजनीतिक दलों को दवा कंपनियों का चंदा

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में चार प्रतिशत हिस्सेदारी दवा निर्माता कंपनियों की है. जॉयडस वेलनेस लिमिटेड, कैडिला फॉर्मासुटिकल्स लिमिटेड, यूनीकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड, हेट्रो ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्रैनुल्स इंडिया लिमिटेड, जेनिक्स फॉर्मा, बायोसर्व क्लीनिकल रिसर्च, नवयुग मेडिकल्स, डायना मेडिकल सर्विस, अरबिंदो फॉर्मा, विकास फार्मा, देहली फॉर्मा, दिशमान फॉर्मासुटिकल्स एंड केमिकल्स लिमिटेड आदि कंपनियों ने विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा दिया है. 2004-05 से 2011-12 तक रसायन और दवा कंपनियों ने 16.54 करोड़ रुपये राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दिए हैं, जिसमें भाजपा को सबसे ज़्यादा 10.12 करोड़ रुपये मिले. इसके बाद कांग्रेस 5.54 करोड़ रुपये के साथ दूसरे नंबर पर है. ■

वर्ष 1979 में औषधियों के दाम निर्धारित करने का सीधा और सरल तरीका ड्रग प्राइज कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) के रूप में जारी किया गया. इसके बाद 1986 एवं 1995 में डीपीसीओ अपने लिए ताकत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 से हासिल करते रहे, जबकि 1979 की नीति और इसके बाद की नीतियों के निर्माण में जयसुख लाल हाथी आयोग की रिपोर्ट की प्रमुख भूमिका रही.

> अफ़ग़ानिस्तान में इराक़ जैसे हालात की चिंता हामिद करजई को भी है. तभी उन्होंने कहा भी है कि अफ़ग़ानिस्तान में कभी इराक जैसी स्थिति नहीं पैदा होगी. लेकिन, उनके महज बयानों को छोड़ दें, और यदि ऐसा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी. अगर अमेरिका अपनी योजना के मुताबिक 2014 के अंत तक अफ़ग़ानिस्तान से पूरी सेना हटा लेता है, तो इराक जैसे हालात निश्चित रूप से आ सकते हैं.

इराक़ की राह पर अफ़ग़ानिस्तान

चंदन कुमार

इराक़ से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के तीन साल के बाद वहां के आज के हालात की कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी. एक मुल्क के रूप में आज इराक़ के अस्तित्व पर ख़तरा मंडरा रहा है. ऐसा नहीं है कि इराक़में हमेशा से शांति रही है. अमेरिकी हमले के बाद लगभग वर्षों तक उसके नियंत्रण के दौरान भी सांप्रदायिक हिंसा होती रही और बम धमाकों की गूंज भी लगातार सुनाई देती रही, लेकिन ऐसा पहली बार लग रहा है कि इराक़का वजूद आज संकट में है. आईएसआईएस नामक चरमपंथी संगठन राजधानी बग़दाद के करीब तक पहुंच चुका है. दावा यह भी किया जा रहा है कि उन्होंने इराक़की कई बड़ी तेल रिफाइनरियों पर क़ब्ज़ा कर लिया है. इराक की स्थिति केवल उसके लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए चिंता का विषय है. सारी दुनिया की नज़र आज इराक पर है. चीन से लेकर भारत तक सभी के निहितार्थ वहां हैं. लेकिन, सबसे चिंता की बात अगर किसी के लिए है, तो वह है अफ़ग़ानिस्तान के लिए. आज इराक़ जिन कारणों से तबाही की कगार पर खड़ा है कमोबेश वैसी स्थितियां अफगानिस्तान में भी पैदा हो रही हैं.

लगभग आठ वर्षों के नियंत्रण के बाद अमेरिका ने इराक़से अपनी सेना वापस बुला ली और शासन से लेकर सुरक्षा तक की तमाम जिम्मेदारियों इराक़ियों के हवाले कर दी. सद्दाम हुसैन के दौरान जंग में यह मुल्क इतना टूट चुका था कि विभिन्न सांप्रदायिक गुट उभार लेने लगे. आज इराक शिया, सुन्नी और कुर्द मुख्यतः इन तीन सांप्रदायिक गुटों के संघर्ष के बीच फंसा हुआ है. अतः कहा जा सकता है कि दिसंबर, 2011 में जब अमेरिका ने इराक से अपनी सेना वापस बुलाई थी, उस वक्त इराक़ी सरकार पूरे देश का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं थी. अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, तो अमेरिका प्रत्यक्ष तौर पर इराक़ में सैन्य हस्तक्षेप करने से बच रहा है. बावजूद इसके लगता है कि अमेरिका ने अपनी ग़लतियों से कोई सबक नहीं सीखा है. आज जिस वजह से इराक गृहयुद्ध की चपेट में है और अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, कमोबेश वही हालात अफगानिस्तान में भी दिख रहे हैं. हालांकि, इराक और अफगानिस्तान की आबादी, भौगोलिक परिवेश और ऐतिहासिक परिस्थितियों में काफी अंतर हैं, लेकिन अफगानिस्तान में सुरक्षा और राजनीतिक घटनाक्रमों के जो हालात बन रहे हैं उन्हें नजरअंदाज करना बहुत बड़ी भूल हो सकती है.

अब एक नज़र अफगानिस्तान की स्थिति पर डालते हैं. अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान से अपने अधिकांश सैनिकों को वापस बुला लिया है. बाक़ी बचे जवान अफ़गानी सेना और सैन्य बलों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं. इराक में जब चरमपंथी मजबूत हो रहे थे और कई इलाकों में बड़ी तेज़ी से अपनी पैठ बना रहे थे, उस वक्त वहां की सरकार उनके प्रति कठोर दमनकारी रुख अपनाए हुए थी. सरकार विरोधियों से बातचीत के पक्ष में नहीं दिख रही थी. इसी का नतीजा है कि आज इराक़ अस्थिरता के दौर में पहुंच चुका है. अफ़ग़ानिस्तान से भी जल्दी ही अमेरिकी सेना स्वदेश लौट जाएगी. इसके बाद सुरक्षा की पूरी कमान अफगानी सुरक्षा बलों के जिम्मे होगी. ऐसे में पूर्ण प्रशिक्षण के अभाव में तालिबान से लड़ना अफ़ग़ानी सेना के लिए बड़ी चुनौती होगी. एक वक्त में तालिबान से बातचीत को लेकर पहल की गई थी, लेकिन वह प्रयास भी पूरी तरह असफल रहा. यानी वहां इराक जैसे हालात अगर अभी नहीं हैं, तो अगले कुछ वर्षों में बनते दिख रहे हैं. इराक़ की ही तरह अफ़ग़ानिस्तान में चरमपंथी आतंकवादी संगठन पूरी तरह संगठित हैं और उन्हें फंड भी काफी मिलते हैं. ऐसे में जब अमेरिका सेना पूरी तरह से अफगानिस्तान छोड़ देगी, तो वे विभिन्न जगहों पर क़ब्जे की कोशिश कर सकते हैं. तालिबान एकबार काबुल पर क़ब्जा कर चुका है. कई वर्षों तक उसकी वहां सरकार भी रही. इसमें कोई शक नहीं कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेगा.

इराक में जब चुनाव हुए, तो सभी को लगा कि वहां लोकतांत्रिक सरकार सत्ता में है, लेकिन इस दौरान राजनीतिक भ्रष्टाचार काफी बढ़ा. इराक के प्रधानमंत्री नूरी–अल–मलिकी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने देश को एकजुट करने की जगह एक ख़ास समूह को नजरअंदाज किया, उसी तरह हामिद करजई ने भी अपने 12 साल के कार्यकाल में बतौर राष्ट्रपति अफगानिस्तान को एकजुट करने के लिए बहुत कम प्रयास किए हैं. पिछले दिनों अफगानिस्तान में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए. दोनों उम्मीदवारों की राजनीति का आकलन करें, तो ऐसा नहीं लगता कि उनकी प्राथमिकता में अफ़ग़ानिस्तान को सशक्त मुल्क बनाने की कोई योजना भी है, क्योंकि उनमें से एक अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह ने 14 जून को हुए रन–ऑफ चुनाव प्रक्रिया का ही बहिष्कार कर दिया. नतीजतन, अफ़ग़ानिस्तान इराक़ की तुलना में राजनीतिक तौर पर अधिक विभाजित हो सकता है.

अफ़ग़ानिस्तान के भविष्य के लिए अगर थोड़ी उम्मीद दिखती है, तो वह है अफगान नेशनल आर्मी. इराकी आर्मी की ही तरह अमेरिकी सेना के जाने के बाद अफगानिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अफगान आर्मी पर ही होगी. इराक की ही तरह अफगानी सेना को प्रशिक्षण अमेरिकी सेना द्वारा ने दिया है. इराक में अमेरिकी प्रशिक्षित इराकी सेना का हश्र हमारे सामने है. साथ ही, अफगानिस्तान के पास पहले कभी कोई राष्ट्रीय सुरक्षा बल नहीं रहा है.अफ़ग़ानिस्तान में इराक़ जैसे हालात की चिंता हामिद करजई को भी है. तभी उन्होंने कहा भी है कि अफ़ग़ानिस्तान में कभी इराक जैसी स्थिति नहीं पैदा होगी. लेकिन, उनके महज बयानों को छोड़ दें, और यदि ऐसा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी. अगर अमेरिका अपनी योजना के मुताबिक 2014 के अंत तक अफ़ग़ानिस्तान से पूरी सेना हटा लेता है, तो इराक जैसे हालात निश्चित रूप से आ सकते हैं.

हालांकि, अफगानिस्तान को दूसरा इराक बनने से रोकने के लिए अमेरिका के पास अभी वक्त है. बशर्ते उसने जो ग़लतियां इराक में की हैं, वो दोहराई न जाएं. अपनी ग़लती को सुधारने के लिए उसके पास मौक़ा है. इस दरम्यान वह किसी भी मुश्किल हालात से निपटने के लिए उसे अफगानी सेना को बेहतर तरीके से प्रशिक्षत करना होगा. साथ ही, जब नया राष्ट्रपति अपना कार्यभार संभालेगा तो उस पर सभी गुटों से संधि के लिए कूटनीतिक दबाव बनाया जाए. लेकिन जो काम पिछले 10 सालों में नहीं हो सका वह काम चंद महीनों में कैसे हो पाएगा, जबकि सेना को जल्दी वापस बुलाने का ओबामा पर घरेलू दवाब भी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

विदेश नीति में पड़ोसियों को वरीयता

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

आज़ादी के बाद भारत की विदेश नीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है. भारत की विदेश नीति एक सतत विदेश नीति रही है. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा जाने लगा था कि यूपीए सरकार के दौरान अर्थनीति से लेकर विदेश नीति तक में जो ठहराव आ गया था, उसमें मोदी आमूलचूल बदलाव करेंगे. हालांकि, नरेंद्र मोदी भी भारतीय विदेश नीति में व्यापक बदलाव को लेकर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. लेकिन, वे पड़ोसी देशों से संबंध को लेकर ज्यादा उत्साहित हैं. किसी भी देश की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और दूसरे देशों से बेहतर संबंधों की नीति पर आधारित होती है. अगर इस लिहाज से देखा जाए, तो मोदी सरकार की विदेश नीति सही राह पर चल रही है. इसकी वजह है कि यूपीए के कार्यकाल में भारत पर अपने पड़ोसी देशों की अनदेखी का आरोप अक्सर लगता रहा. कहा यह जाने लगा कि भारत सरकार अमेरिका की क़ीमत पर अपने पड़ोसियों की अनदेखी कर रहा है. नयी सरकार के आने के बाद काफी कुछ बदलता दिख रहा है. इसकी सबसे बड़ी मिसाल है हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का पहले विदेशी दौरे पर बांग्लादेश जाना. ग़ौरतलब है कि नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में ही सार्क देशों को निमंत्रण भेजकर यह संकेत दे दिया था कि भारत की विदेश नीति क्या होने वाली है. यानी भारत पहले अपने पड़ोसियों से संबंध को मजबूत करेगा. मोदी भी अपने पहले विदेशी दौरे पर भूटान गए. अब सुषमा स्वराज का बांग्लादेश जाना यह बतलाता है कि भारत की विदेश नीति में किसे कितनी प्राथमिकता मिलने वाली है.

श्रीलंका को लेकर भी मोदी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि पिछली सरकार की तरह तमिलनाडु का हस्तक्षेप श्रीलंका के साथ संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा. नरेंद्र मोदी नौकरशाही के मुरीद रहे हैं और विदेश नीति को लेकर उनका अनुभव बेहद कम है. लेकिन, हर सरकार की अपनी कार्यशैली होती है. नतीजतन, नीतियों में थोड़ा–बहुत तो बदलाव ज़रूर होता है. भारत के साथ श्रीलंका के संबंधों की बात करें, तो मोदी की अगुवाई में भारत से उसके संबंध खट्टे–मीठे अनुभव वाले हो सकते हैं. व्यावहारिकता में देखें, तो अर्थव्यवस्था और एक–दूसरे को जोड़े रखने के मुद्दे पर संबंध मधुर हो सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर कोलंबो के साथ अतीत की द्विपक्षीय वार्ता, जैसे श्रीलंकाई संविधान में तेरहवें संशोधन के मुद्दे पर संबंधों में कड़वाहट के रस देखने को मिलेंगे. ग़ौरतलब है कि दिल्ली और कोलंबो के बीच विदेश नीति का केंद्र बिंदु अभी तक तमिलनाडु रहा है. यह कहा जा सकता है कि साउथ ब्लॉक के बाबू मीठा पसंद करते हैं, तो तमिलनाडु के लोग मिर्च. लेकिन, 16वीं लोकसभा के नतीजों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने के कारण तमिलनाडु का हस्तक्षेप पहले की अपेक्षा काफी कम होगा, क्योंकि भारत किसी एक राज्य की वजह से अपनी पड़ोसियों से संबंधों को ख़राब नहीं करना चाहेगा.

मोदी राष्ट्रवादी हैं और उनकी सोच से ज़ाहिर होता है कि वे एक मज़बूत भारत देखना चाहते हैं. ख़ासतौर पर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में. नौकरशाही के प्रति उनका प्रेम और विदेश मामलों के प्रति उनकी अनभिज्ञता उन्हें साउथ ब्लॉक पर अधिक निर्भर बनाएगा. हालांकि, पिछली सरकारों में भी ऐसा ही होता था. नतीजतन, भारतीय विदेश नीति को समझने के लिए साउथ ब्लॉक के विभिन्न नए प्रभावी विभागों को समझने की जरूरत है. ऐसे में अजीत डोभाल एक बड़े नाम हैं. सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हैं और निश्चित तौर पर वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. ■

–*चंदन कुमार* feedback@chauthiduniya.com

> बाबा की अनुमति प्राप्त कर रतन जी नांदेड़ लौट आए और शिरडी में जो कुछ हुआ, उसे दासगणू को सुनाया. रतन जी ने कहा, सब कार्य ठीक ही रहा. बाबा के शुभ दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद और प्रसाद भी प्राप्त हुआ, लेकिन वहां की एक बात समझ में नहीं आई. बाबा ने कहा था कि मुझे तीन रुपये चौदह आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं.

साई बाबा के सत्य वचन

चौथी दुनिया ब्यूरो

कोई भी भक्त चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत से घिरा हो, साई बाबा उसे संकट से ज़रूर उबारते हैं और उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं. रतन जी वाडिया साई बाबा के भक्त थे. उन्होंने अपने व्यापार के माध्यम से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया. वह अत्यंत भाग्यशाली थे, हमेशा प्रसन्न दिखते थे, लेकिन अंदर से थे नहीं. विधाता की रचना ऐसी विचित्र है कि इस संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं है. वह परोपकारी व दयावान थे. वह ग़रीबों को भोजन एवं वस्त्र वितरण करते और सभी की अनेक प्रकार से सहायता करते थे. उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे. लेकिन, लंबे समय तक संतान न होने के कारण वह दु:खी रहते थे.

जिस प्रकार प्रेम एवं भक्ति रहित कीर्तन और वाद्य रहित संगीत उत्तम प्रतीत नहीं होते, उसी प्रकार संतान रहित गृहस्थ का आंगन भी सूना रहता है. रतन जी सदैव इसी चिंता में रहते थे. वह मन ही मन कहते, क्या ईश्वर की मुझ पर कभी दया न होगी, क्या मुझे कभी संतान की प्राप्ति न होगी. उनकी दासगणू महाराज पर पूर्ण निष्ठा थी. उन्होंने अपना हृदय उनके सम्मुख खोल दिया, तब उन्होंने साई बाबा की शरण में जाने के लिए कहा. रतन जी ने उनका आदेश मानते हुए शिरडी जाने का निश्चय किया. कुछ दिनों के उपरांत वह शिरडी गए और बाबा के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना की. साई बाबा ने उनसे पांच रुपये दक्षिणा मांगी, जो वह देना ही चाहते थे. लेकिन, बाबा ने पुन: कहा, मुझे तुमसे तीन रुपये चौदह आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए केवल शेष रुपये ही दो. यह सुनकर रतन जी असमंजस में पड़ गए. बाबा का अभिप्राय उनकी समझ में न आया. वह सोचने लगे कि यह शिरडी आने का मेरा प्रथम ही अवसर है और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इन्हें तीन रुपये चौदह आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं. वह बाबा के चरणों के पास ही बैठे रहे और उन्हें शेष दक्षिणा अर्पित कर दी. बाबा ने कहा, चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए हैं. इसके बाद बाबा ने उदी देकर अपना वरदहस्त उनके मस्तक पर रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा.

बाबा की अनुमति प्राप्त कर रतन जी नांदेड़ लौट आए और शिरडी में जो कुछ हुआ, उसे दासगणू को सुनाया. रतन जी ने कहा, सब कार्य ठीक ही रहा. बाबा के शुभ दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद और प्रसाद भी प्राप्त हुआ, लेकिन वहां की एक बात समझ में नहीं आई. बाबा ने कहा था कि मुझे तीन रुपये चौदह आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं. कृपया समझाएं कि इसका क्या अर्थ है? इससे पूर्व मैं शिरडी कभी नहीं गया. फिर बाबा को वे रुपये कैसे प्राप्त हो गए? दासगणू के लिए भी यह एक पहेली ही थी. कई दिनों के पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि कुछ दिन पहले रतन जी ने एक यवन संत मौला साहेब को अपने घर आमंत्रित किया था और उसके निमित्त उन्होंने कुछ धन व्यय किया था. मौला साहेब नांदेड़ के एक प्रसिद्ध संत थे, जो कुली का काम करते थे. रतन जी उनसे अच्छी तरह परिचित थे और उनसे प्रेम भी अधिक करते थे. दासगणू ने रतन जी से आतिथ्य के खर्च की सूची मांगी और यह जानकर सबको आश्चर्य हुआ कि खर्च ठीक तीन रुपये चौदह आने ही हुआ था. न इससे कम था और न अधिक. सबको बाबा की त्रिकालज्ञता विदित हो गई. यद्यपि वह शिरडी में विराजमान थे, लेकिन शिरडी के बाहर क्या हो रहा है, इसका उन्हें पूरा-पूरा ज्ञान था. रतन जी इस उत्तर से संतुष्ट हो गए. कुछ समय बाद उनके यहां एक पुत्र का जन्म हुआ, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा. इस तरह बाबा के वचन सत्य निकले. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1-जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2-चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दु:ख की पीढ़ी पर.
3-त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4-मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5-मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6-मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7-जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8-भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9-आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10-मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11-धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

केदारनाथ धाम

जहां गोत्र वध के पाप से मुक्त हुए थे पांडव

राजकुमार शर्मा

पावन केदारनाथ धाम को मोक्ष धाम के नाम से भी जाना जाता है. इस धाम का पौराणिक महत्व है. इसकी प्राचीनता के संदर्भ में स्वयं भगवान भोलेनाथ ने स्कंद पुराण में जगत माता पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा है, हे प्राणेश्वरी! यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है, जितना मैं हूं. मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्मत्व प्राप्त किया. तभी से यह स्थान मेरा आवास है. यह केदारनाथ मेरा चिरप्रिय आवास है. यह स्थान मुझे भू-लोक में स्वर्ग के समान लगता है.

भारत में भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें सर्वोच्च पावन केदारनाथ धाम है, जो हिमालय की मनोरम गोद में स्थित है. द्वापर युग में महाभारत युद्ध के बाद गोत्र वध के पाप से भयाक्रांत पांडवों को दु:खों एवं पापों से मुक्ति के लिए वेदव्यास जी ने केदार क्षेत्र में भगवान शिव जी के दर्शन के लिए भेजा. भगवान शिव गोत्र वध करने वाले पांडवों को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते थे. इसी कारण वह मायामय महिष का रूप धारण करके केदार अंचल में भ्रमण करने लगे. युधिष्ठिर की मदद से पांडवों ने महिष रूपी शिव को पहचान लिया. वे भगवान शिव का पीछा करने लगे, तो महिष रूपी शिव भूमिगत होने लगे. इस पर पांडवों ने महिष रूपी शिव के पृष्ठ भाग स्थित पूंछ पकड़ ली और उनकी स्तुति करने लगे. भगवान भोलेनाथ कृपालु हो गए. उसी महिष के पृष्ठ भाग के रूप में शिव जी वहीं स्थित हो गए.

> केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं. राज्य सरकार ने हवाई यात्रा सेवा भी शुरू की है. यहां स्थित गौरी कुंड का प्राचीन माहात्म्य है. मान्यता है कि गणेश जी की उत्पत्ति यहीं हुई थी. आज भी यहां गणेश जी की सिरकटी मूर्ति की पूजा होती है. इसी स्थान पर माता पार्वती ने ऋतु स्नान किया था. कुंड का उष्ण जल का रंग सिंदूरी है. इस कुंड में स्नान का विशेष माहात्म्य है. हिमालय में पिछले साल आई दैवीय आपदा ने सर्वाधिक तबाही केदारनाथ धाम में मचाई.

पांडवों ने शिव जी का कृपालु स्वरूप पहचान कर उसी रूप में उन्हें स्वीकार करके उनकी विधिवत पूजा-अर्चना की और शिव जी की कृपा से वे गोत्र वध जैसे पाप से मुक्त हुए. पांडवों ने द्वापर युग में ही केदारनाथ जी के भव्य एवं विशाल मंदिर का निर्माण किया, तभी से देवाधिदेव महादेव केदारनाथ में दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं. कलियुग में भी केदारनाथ धाम के रूप में पूजित हैं. यहां शिव रूप महिष के पृष्ठ भाग में घी का लेपन किया जाता है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं. यह धाम द्वापर युग से पहले ही केदारनाथ धाम के रूप में पूजित एवं शिव की साधनास्थली रहा है. आज भी केदारनाथ धाम के प्रकृति रूप के कण-कण में शिव का वास होने का अनुभव भक्त गण करते हैं. इसी धाम में जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने भी शिव की आराधना करके सिद्धि प्राप्त की. भगवान केदारनाथ की विशेष पूजा होती है. सुबह की पूजा को निर्वाण दर्शन पूजा के नाम से जाना जाता है. कृपा पाने के लिए शिव भक्त दुर्गम मार्ग से आकर बाबा के दर्शन करते हैं. मंदाकिनी, गंगा, क्षीर गंगा, मधु गंगा एवं सरस्वती गंगा आदि पांच नदियां नित्य महादेव का अभिषेक करती हैं. नारद जी ने इसे कल्पेश्वर तीर्थ की संज्ञा देते हुए कहा, इस धाम के दर्शन मात्र से जीव की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं. समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर गौरी कुंड से 14 किलोमीटर दूर है. शीतकाल में बर्फ पड़ने के कारण मंदिर प्राचीन परंपरा के अनुसार छह माह के लिए बंद कर दिया जाता है. इसके बाद मंदिर के कपाट मई में पुन: छह माह के लिए खुलते हैं. व्यवस्था संचालन के लिए बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति है. केदारनाथ धाम तीर्थस्थल होने के साथ-साथ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है. केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं. राज्य सरकार ने हवाई यात्रा सेवा भी शुरू की है. यहां स्थित गौरी कुंड का प्राचीन माहात्म्य है. मान्यता है कि गणेश जी की उत्पत्ति यहीं हुई थी. आज भी यहां गणेश जी की सिरकटी मूर्ति की पूजा होती है. इसी स्थान पर माता पार्वती ने ऋतु स्नान किया था. कुंड का उष्ण जल का रंग सिंदूरी है. इस कुंड में स्नान का विशेष माहात्म्य है. हिमालय में पिछले साल आई दैवीय आपदा ने सर्वाधिक तबाही केदारनाथ धाम में मचाई. हज़ारों लोगों की जान चली गई और पूरा केदारनाथ धाम तहस-नहस हो गया. रामबाड़ा एवं गौरी कुंड का तो नामोनिशान मिट गया. इस हिमालयी सुनामी में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर पूरी तरह सुरक्षित बचा. जो मंदिर में शरणागत थे, उनकी भी रक्षा हुई. पहली बार केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की लगातार चलने वाली पूजा महीनों तक बाधित रही. सावन में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक न होने की घटना को श्री जयराम संस्था के दिव्य पीठाधीश्वर ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज घोर अमंगलकारी मानते हुए कहते हैं कि इससे शिव को कष्ट पहुंचा है. भगवान शिव फिर भी औघड़दानी हैं. उनकी सामूहिक स्तुति की जाए, तो वह खुश होते हैं. यही उनकी क्षमायाचना का विधान है. दिव्य पीठाधीश्वर स्वामी कमलेशानंद सरस्वती कहते हैं कि आज भी यह धाम शिव लोक होने के कारण परम पावन है. शिव दिगंबर और शमशान प्रिय देवता हैं, इसलिए उन्हें संहार का देव माना गया है. मानव के लिए वह सदैव सत्यम, शिवम, सुंदरम हैं. वह कहते हैं कि सभी आत्माओं का शिव द्वारा कल्याण किया जा चुका है और ऐसा उनकी दया भावना के कारण हुआ. गतम् न सोचयामि, नारायण! नारायण!! ■

feedback@chauthiduniya.com

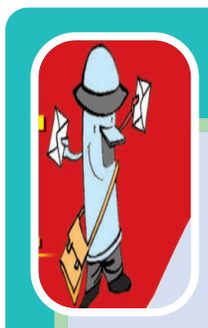

पाठकों की दुनिया

सरकार की नीतियां

मैं चौथी दुनिया का नया पाठक हूं. मैंने यह अख़बार एक न्यूज स्टैंड पर देखा. मुख्य आलेख-सरकार की नीतियां क्या होंगी पढ़ा, अच्छा लगा. आलेख में पूर्व सरकार की नीतियों, कमजोरियों, असफलताओं एवं वर्तमान में भारत की दशा और नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए वादों को देखते हुए जो बातें कमल मोरारका ने लिखी हैं, वे शत-प्रतिशत सही साबित होंगी. मोदी द्वारा पूर्व सरकार के संदर्भ में की गईं बड़ी-बड़ी बातों, चुनाव से पहले पाकिस्तान के प्रति मोदी के रवैये और वर्तमान में उनके बदलते राग से उनकी कथनी-करनी में अंतर स्पष्ट है, लेकिन यह तो अभी शुरुआत है. सरकार की नीतियों से संबंधित ऐसे लेख सिविल सेवा के प्रतिभागियों के लिए उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि इन्हें पढ़ने के बाद हमारी सोच-समझ कहीं अधिक विकसित होती है.

-नरसी राम भील, बीकानेर, राजस्थान.

नक्सलियों से बातचीत ज़रूरी

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-नक्सलियों से वार्ता की पहल करे केंद्र सरकार (23 जून-29 जून) पढ़ा, काफी विचारोत्तेजक है. वास्तव में सरकार को नक्सलियों से बातचीत की पहल करनी चाहिए. देश के कई राज्यों में नक्सली बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों के जवानों और स्थानीय लोगों पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं. सभी नेता और सरकारें विकास के जरिये नक्सलवाद मिटाने की बात करते हैं, लेकिन केवल विकास ही इसका एकमात्र हल नहीं है. सरकार को चाहिए कि वह नक्सलियों से बातचीत करे और उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास हो.

-राजेश सिंह, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश.

मेड इन चाइना का मुकाबला

आलेख-मेड इन चाइना से कैसे निपटेगा मेड इन इंडिया (23 जून-29 जून) में सही कहा गया है कि भारत मेड इन चाइना से कैसे निपटेगा, क्योंकि आज दीवाली एवं होली पर इस्तेमाल की जाने वाली अधिकतर वस्तुएं चीन निर्मित होती हैं. दीपावली पर घर की सजावट का सामान हो या होली के मौक़े खरीदी जाने वाली पिचकारी, सब कुछ चीन निर्मित है. पहले हम स्वदेशी बिजली की झालरें एवं दीपक इस्तेमाल करते थे, अब चीनी झालरों से बाज़ार पटा रहता है. मोबाइल बाज़ार पर चीन का जबरदस्त प्रभाव है. सरकार इस स्थिति से कैसे निपटेगी? मोदी सरकार लाखों युवाओं को नौकरी देने की बात करती है, लेकिन आख़िर कैसे मिलेगा युवाओं को रोज़गार?

-श्रवण कुमार, रांची, झारखंड.

सपने, विश्वास और सब्र

भारत के लोगो, समझो मोदी जी के पास नहीं है मैजिक बैंड.
यूपीए ने पहले से ही देश का बजा रखा है बैंड.
जो काम यूपीए ने पिछले दस साल में नहीं किया.
कभी यह भी न सोचा कि आम आदमी कैसे जीया.
तब मोदी जी ने सब कुछ ओके करने का ज़िम्मा लिया.
और लोगों ने मन में ठान कर उन पर विश्वास किया.
इतने घोटाले, इतने भ्रष्टाचार, क्या कभी किसी ने देखा है.
इन सबसे निपटना और बाहर निकलना क्या इतना आसान है.
हर जगह बेईमानी, हर जगह है अराजकता का ही राज.
इन्हें भी टक्कर देकर ईमानदारी लाएगा एनडीए राज.
विश्व के सभी देश मोदी जी की विजय से प्रभावित हैं.
अमेरिका भी अब उन्हें वीजा देने को तैयार है.
मोदी जी की सरकार प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर रही है.
धीरज रखो भाइयो, यही संदेश मोदी जी की सरकार दे रही है.
हे देशवासियो, एक बात तुम करो स्वीकार.
मोदी जी के किए हुए वादे नहीं जाएंगे बेकार.
थोड़ा समय लगना है, किसी काम को आकार देने में.
आपके सपने भविष्य में अवश्य होंगे साकार.
यूपीए पहले ही दिन से मोदी जी की आलोचना किए है.
यूपीए के लोगों, जरा सब्र करो, कुछ अच्छा होने जा रहा है.

-मीना भट्टाचार्य, मुंबई, महाराष्ट्र.

बिजली संकट

आलेख-बिजली संकट के लिए ज़िम्मेदार कौन? (23 जून-29 जून) पढ़ा. सही सवाल है कि बिजली संकट के लिए ज़िम्मेदार कौन है. पारा जैसे-जैसे चढ़ता गया, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बिजली संकट गहरा गया. दरअसल, बिजली संकट का कारण केंद्र और राज्य सरकारों की लापरवाही है. उत्तर प्रदेश में कई पावर प्लांट बंद पड़े हैं. देश में कई पावर प्लांटों का काम अधूरा है. यूपीए सरकार की लापरवाही के कारण ही देश में बिजली संकट पैदा हुआ. कई बिजली कंपनियों ने कोयले की कमी का हवाला दिया है. इन सबके लिए राज्य और केंद्र दोनों ही ज़िम्मेदार हैं.

-अफरोज आलम, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश.

वादे नहीं, काम चाहिए

संपादकीय-जनता को भीख नहीं, अवसर चाहिए (23 जून-29 जून) काफी विचारोत्तेजक है. संतोष भारतीय सही कहते हैं कि जनता को भीख नहीं, अवसर चाहिए. वास्तव में जनता ने कई बार व्यवस्था के ख़िलाफ़ आवाज उठाई और सरकार पर दबाव बनाया. लोगों की बातें सुनी गईं. भ्रष्टाचार, महंगाई एवं बेरोज़गारी के चलते उपजे क्रोध ने एनडीए और भाजपा को इतना बड़ा बहुमत दिलाया. मोदी सरकार को चाहिए कि वह महंगाई कम करे, बेरोज़गारों के लिए रोज़गार के साधन उपलब्ध कराए. यदि मोदी अपने वादों पर खरे नहीं उतरते हैं, तो जनता समझेगी कि वह एक बार फिर ठगी गई और उसका सरकार से विश्वास उठ जाएगा.

-अखिलेश यादव, रीवा, मध्य प्रदेश.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

करुणानिधि ने कहा कि हिंदी को प्राथमिकता दिए जाने को ग़ैर हिंदी भाषी लोगों के साथ भेदभाव करने और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक मानने के प्रयास की दिशा में पहला क़दम समझा जाएगा. डीएमके नेता करुणानिधि का यह बयान न केवल हास्यास्पद है, बल्कि पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है. दोनों बेटों के बीच जारी कलह, टेलीकॉम घोटाले में बेटी एवं पत्नी के आरोपी होने और सबसे बड़ी बात यह कि लोकसभा चुनाव में पूरे राज्य से सूपड़ा साफ़ होने के बाद करुणानिधि के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और वह हाशिये पर चले गए हैं.

सियासत की आग पर भाषा की हांडी

अनंत विजय

केंद्रीय गृह मंत्रालय के हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने का विरोध शुरू हो गया है. गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने की पहल और कोशिश शुरू की है. गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के ट्वीटर, फेसबुक और अन्य जगहों पर बनाए गए आधिकारिक खातों में राजभाषा हिंदी को नज़रअंदाज करके केवल अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जा रहा है. गृह मंत्रालय के मुताबिक, सभी विभागों द्वारा इन आधिकारिक खातों में हिंदी अथवा अंग्रेजी एवं हिंदी, दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसमें हिंदी को पहले रखे जाने का आदेश है. इस आदेश के ख़बर बनते ही लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद तमिलनाडु में सियासी जमीन की तलाश में जुटे डीएमके नेता करुणानिधि को इसमें संभावना नज़र आई. उन्होंने फौरन गृह मंत्रालय के हिंदी को बढ़ावा देने के निर्देश के फ़ैसले का विरोध करते हुए बयान जारी कर दिया.

करुणानिधि ने कहा कि हिंदी को प्राथमिकता दिए जाने को ग़ैर हिंदी भाषी लोगों के साथ भेदभाव करने और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक मानने के प्रयास की दिशा में पहला क़दम समझा जाएगा. डीएमके नेता करुणानिधि का यह बयान न केवल हास्यास्पद है, बल्कि पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है. दोनों बेटों के बीच जारी कलह, टेलीकॉम घोटाले में बेटी एवं पत्नी के आरोपी होने और सबसे बड़ी बात यह कि लोकसभा चुनाव में पूरे राज्य से सूपड़ा साफ़ होने के बाद करुणानिधि के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और वह हाशिये पर चले गए हैं. इस स्थिति में वह एक बार फिर से हिंदी विरोध का राग अलाप कर तमिलनाडु की जनता की भावनाएं भड़का कर अपनी राजनीति चमकाने की फिराक में हैं. हिंदी की एक कहावत है, शायद करुणानिधि को पता न हो, काठ की हांडी बार–बार नहीं चढ़ती. साठ के दशक में हिंदी की हांडी को राजनीति के चूल्हे पर चढ़ाकर करुणानिधि और उनकी पार्टी ने लंबे समय तक तमिलनाडु पर राज किया.

साठ के दशक का वह वक्त कुछ और था और पांच दशक बाद का वक्त अब कुछ और है. देश की, देशवासियों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं. अब लोग भाषा के नाम पर मरने– मारने के लिए उतारू होने वाले नहीं हैं. इसके अलावा, भाषा के नाम पर राजनीति चमकाने की नेताओं की चाल भी जनता समझ चुकी है, लिहाजा हिंदी विरोध की हांडी से इस बार सत्ता निकलने वाली नहीं है. करुणानिधि का सवाल है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में

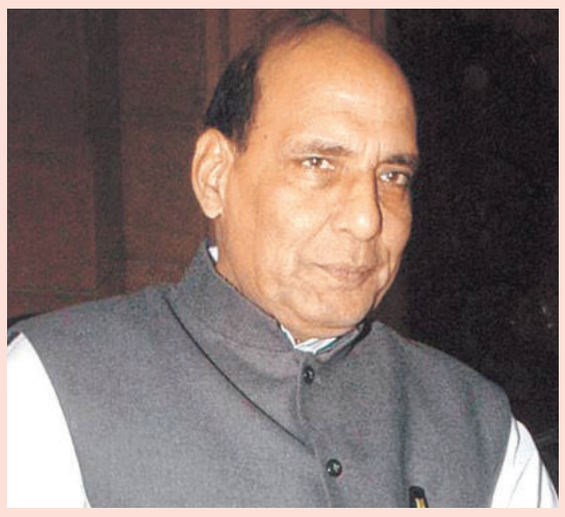

शामिल सभी भाषाओं में से हिंदी को ही प्राथमिकता देने का ऐलान क्यों किया गया है. उन्होंने संचार के लिए हिंदी में रुचि दिखाने के केंद्र के फ़ैसले को भटकाव पूर्ण क़दम करार दिया है. करुणानिधि स्वयं अच्छे लेखक रहे हैं, लेकिन उनका यह तर्क कि संचार के माध्यम के लिए भाषा विशेष को तवज्जो देना भटकाव है, गले नहीं उतरता. हिंदी को तमाम विरोध और संघर्ष के बाद राजभाषा का दर्जा हासिल हुआ था. अब अगर राजभाषा में सरकारी कामकाज के प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देने पर अमल शुरू करने की पहल हो रही है, तो यह भटकाव कैसे है. करुणानिधि का बयान आने के बाद जयललिता ने भी विरोध जताने की रस्म अदायगी कर दी है.

दरअसल, अगर हम इतिहास पर एक नज़र डालें, तो डीएमके की बुनियाद ही भारत विरोध पर आधारित रही है. मद्रास प्रेसिडेंसी में तमाम दलों ने साथ आकर डीएमके की स्थापना की थी. उसके अगुवा रहे सी एम अन्नादुरैई ने जोर–शोर से अलग तमिल देश की मांग उठाई थी और कहा था कि तमिल राज्य के बनने के बाद ही तमिल अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. डीएमके के अलगाववादी रुख की वजह से इस पार्टी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी. इसकी वजह संविधान का अनुच्छेद उन्नीस था, जो किसी भी तरह के अलगाववादी दल को चुनाव लड़ने से रोकता था. 1962 में चीन के आक्रमण के दौरान डीएमके नेताओं ने जेल से ही चीनी हमले का विरोध किया था. उसके बाद नेहरू के रुख में बदलाव आया और उन्होंने अनुच्छेद उन्नीस में संशोधन करा दिया, ताकि डीएमके चुनाव लड़ सके. यह ठीक है कि बाद के वर्षों में डीएमके का अलगाववादी रुख उस तरह से मुखर नहीं हुआ. लेकिन,

जनवरी 1965 में एक बार फिर से हिंदी के विरोध में तमिलनाडु में जबरदस्त हिंसा शुरू हो गई थी.

तमिलनाडु के लोगों को लगता था कि हिंदी को बढ़ावा देने से तमिलों का हक़ छिन जाएगा, जबकि ऐसा था नहीं. तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी ने बगैर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को बताए तमिलनाडु जाकर भाषाई हिंसक आंदोलन को बातचीत के जरिये सुलझाया था. इंदिरा गांधी की पहल को दाद दी गई थी. हालांकि लाल बहादुर शास्त्री को इंदिरा गांधी का यह क़दम अच्छा नहीं लगा था. खैर, यह एक अवांतर प्रसंग है, जिस पर कभी बाद में चर्चा होगी. इस पूरे प्रसंग को बताने का मतलब यह है कि हिंदी को बढ़ावा देने से अन्य भाषाओं को कोई ख़तरा नहीं है, यह बात अन्य भाषा के लोगों को समझानी होगी. अन्य भारतीय भाषाओं के लोगों से संवाद कायम करना होगा, अन्यथा करुणानिधि जैसे लोग भाषा की भावना भड़का कर राजनीति की रोटी सेंकने में कामयाब होते रहेंगे.

महात्मा गांधी ने यह बात आज़ादी के पहले ही साफ़ कर दी थी कि हिंदी के प्रचार–प्रसार से किसी भी अन्य प्रांतीय भाषा को कोई ख़तरा उत्पन्न होगा. 20 अप्रैल, 1935 को हिंदी साहित्य सम्मेलन के चौबीसवें अधिवेशन में इंदौर में गांधी जी ने कहा था, मैं हमेशा यह मानता रहा हूं कि किसी भी हालत में प्रांतीय भाषाओं को मिटाना नहीं चाहिए. हमारा मतलब तो सिर्फ़ यह है कि विभिन्न प्रांतों के पारस्परिक संबंध के लिए हम हिंदी सीखें. ऐसा कहने से हिंदी के प्रति हमारा कोई पक्षपात प्रकट नहीं होता. हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं. वह राष्ट्रीय होने के लायक है. वही भाषा राष्ट्रीय बन सकती है, जिसे बहुसंख्यक लोग जानते–बोलते हों और जो सीखने में सुगम हो. ऐसी भाषा हिंदी ही है. हिंदी के प्रति गांधी जी का प्रेम सर्वविदित है, लेकिन वह हिंदी के साथ–साथ सभी भारतीय भाषाओं की प्रगति के सबसे बड़े पैरोकार थे.

9 जुलाई, 1938 के हरिजन सेवक में गांधी जी ने लिखा, शिक्षा का माध्यम तो एकदम और हर हालत में बदलना चाहिए और अन्य प्रांतीय भाषाओं को उनका वाजिब स्थान मिलना चाहिए. इसके अलावा संविधान सभा में पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा था, मैं नहीं चाहता कि हिंदी को अनिच्छुक लोगों पर लादा जाए. यदि आप यह समझते हैं कि जिन लोगों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे इस विधान के पक्ष में मत न दें. हिंदी के लोगों की अन्य भारतीय भाषाओं को लेकर हमेशा से एक सकारात्मक सोच रही है. निहित स्वार्थ की खातिर कुछ लोगों ने हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं की दुश्मन के तौर पर प्रचारित कर दिया. यहां एक और उदाहरण देना सही होगा. सरकारी भाषा आयोग की एक बैठक में भाषा के सवाल पर सदस्यों के बीच तीखी बहस हो रही थी. उस बहस में हस्तक्षेप करते हुए बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कहा था, यदि हिंदी देश की एकता में रोड़ा बनती है, तो मैं इसे गहरे सागर में डुबो दूंगा. हिंदी के नुमाइंदों की उक्त प्रतिक्रियाएं यह साफ़ करती हैं कि वे हिंदी को सर्वग्राह्य बनाना चाहते थे, हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं पर थोपना नहीं चाहते थे और अब भी ऐसा नहीं चाहते हैं.

यह बात गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ़ कर दी. उन्होंने कहा कि सभी भारतीय भाषाएं अहम हैं और उनका मंत्रालय सभी भारतीय भाषाओं के विकास एवं प्रचार के लिए प्रतिबद्ध है. यह प्रतिबद्धता ज़रूरी भी है, क्योंकि अन्य भाषाओं का सहयोग लेकर ही हिंदी को आगे बढ़ाया जा सकता है. अन्य भारतीय भाषाओं के लोगों को भी समझना होगा कि उनकी भाषा के फैलाव के लिए भी हिंदी का होना आवश्यक है. एक छोटे–से उदाहरण के जरिये इसे समझा जा सकता है. अगर किसी अन्य भारतीय भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद कराना हो, तो पहले उसके हिंदी अनुवाद की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हिंदी को छोड़कर ऐसे अनुवादक कम हैं, जो भारतीय भाषाओं में ही अनुवाद कर सकें. हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को सहोदर भाषा के तौर पर काम करना होगा, ताकि वे एक–दूसरे के साथ चलकर अपनी– अपनी मंजिल पा सकें. करुणानिधि जैसे लोगों की राजनीति पहचान कर तमिलभाषियों को ही उनके मंसूबे असफल करने होंगे.■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

व्यंग्य

...रमंते तत्र शांति

महेंद्र अवधेश

संडे का दिन था और ऊपर से मौसम भी खुशगवार. बावजूद इसके, भइया लाल बहुत उखड़े–उखड़े से नज़र आ रहे थे. मैंने सोचा कि शायद दफ्तर में किसी बात पर किसी से ठन गई होगी, इसीलिए मिजाज में तल्खी झलक रही है. वजह जानने की गरज से बोला, क्या बात है बॉस?

कुछ नहीं, बस यूं ही, कहकर भइया लाल ने बनावटी मुस्कान के साथ एक ठंडी सांस छोड़ी. मैंने कहा, लेकिन फिर भी?

थोड़ी देर बाद वह बोले, कहा न, तुम नहीं समझ पाओगे. जब तक ईश्वर की इच्छा है, मौज कर लो. दो–चार साल बाद मैं खुद तुमसे पूछूंगा कि क्या बात है बॉस?

मैं फिर पूछ बैठा, जरा बताइए तो सही भाई साहब, आख़िर मामला क्या है?

भइया लाल पहले बुदबुदाए, फिर बोले, और कुछ भी नहीं, सारे रण की जड़ तुम्हारी भौजाई हैं, जो हमेशा राशन–पानी लिए मेरे सिर पर चढ़ी रहती हैं. जब देखो, तब किच–किच और खोपड़ी नुचौव्वल!

मैंने छेड़ा, ज़रूर आप में कोई खोट नज़र आती होगी भाभी जी को, अन्यथा एक हाथ से तो ताली भी नहीं बजती. आप अपनी उलझने वाली आदत छोड़ दीजिए. शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमंते तत्र देवता....

मेरे इतना कहते ही भइया लाल उबल से गए, मति मारी गई है तुम्हारी. सुबह से शाम तक दफ्तर, फिर हाट–बाज़ार और उसके बाद तुम्हारी भतीजी–भतीजे का होमवर्क, सारे के सारे काम मैं ही निपटाता हूं, पड़ोसी नहीं निपटाते.

दो मिनट तक वाणी विराम के बाद वह फिर शुरू हुए, और सुनो बेटा, इतवार की सुबह सब्जी काटने का ओवरटाइम अलग से करता हूं. कभी–कभी कपड़े भी प्रेस करने पड़ते हैं. इसलिए तो कह रहा हूं कि दो–चार साल बाद पूछूंगा कि तुम्हारे घर में देवता वास कर रहे हैं या नहीं?

इस बार मैंने समझाने के उद्देश्य से कहा, आप नाहक नाराज होते हैं. घर के काम घर वाले ही करते हैं. पड़ोसियों का काम दूसरा है! यह एक ऐसी विशेष किस्म की प्रजाति है, जो अपना काम इतने शातिराना अंदाज में कर गुजरती है कि किसी को भनक तक नहीं लगती. और, जब लगती है, तो अपना सिर धुनने के अलावा कोई हल शेष नहीं दीखता.

तुम जरा ज़्यादा ज्ञान मत बघारो, मैं जानता हूं कि तुम्हारी भौजाई के भाव आख़िर बढ़े क्यों हैं? भइया लाल ने झल्लाहट भरे स्वर में कहा.

क्यों, जरा मैं भी तो जानूं? मैंने तुरंत सवाल दागा.

भइया लाल बोले, जब–जब देश में महिला अधिकारों और तैंतीस फ़ीसद आरक्षण का झुनझुना बजता है, मेरा तो जीना हराम हो जाता है. ख़बरें पढ़–पढ़कर उसका दिमाग अपनी धुरी से हट जाता है. बात–बात में बहस पर उतर आती है, भाषा बिल्कुल नेताओं वाली हो जाती है. उसके तेवरों से लगता है कि और कहीं हो या न हो, मेरे घर में क्रांति का सायरन किसी दिन ज़रूर बज उठेगा.

मेरी ओर से फिर एक कोशिश हुई. मैं बोला, इसका इलाज है भाई साहब! आप जरा भाभी जी के सामने एक शिगूफा छोड़िए कि अबकी बार दीवाली पर जब बोनस मिलेगा, तो सारी खरीदारी उन्हीं पर केंद्रित होगी. बस, नए–नए जेवरों और साड़ियों की चाह उनके सारे तेवर ढीले कर देगी. क्रांति की सारी आशंकाएं धूल–धूसरित और शांति की अपार संभावनाएं बलवती हो जाएंगी. जरा सबक तो लीजिए उन्हीं महिला अधिकार और तैंतीस फ़ीसद आरक्षण जैसे आश्वासनों से, जिन्हें आप अपनी परेशानी की वजह मानते हैं. अरे, जब व्यवस्था 33 फ़ीसद आरक्षण और समान अधिकार का लालीपॉप दिखाकर समूचे देश में क्रांति को थामे हुए है, तो आप भी चार महीने बाद मिलने वाले अपने बोनस का झुनझुना बजाकर अनहोनी को होनी में बदल सकते हैं.

यानी मैं साल में सिर्फ़ एक बार मिलने वाले बोनस का खून कर दूं? पूरी की पूरी रकम उस पर यूं लुटा दूं? भइया लाल का प्रतिवाद जारी था.

मैंने समझाया, शांति के लिए तो इस देश ने न जाने कितनी कुर्बानियां दे डालीं और आपको अपना बोनस ज़्यादा प्यारा लगता है? अनुज होने के नाते और घर की कलह ख़त्म करने की खातिर मेरी यह नेक सलाह मानिए और इस संशोधित सूत्रवाक्य को गांठ बांध लीजिए कि यत्र पत्नी पूज्यंते, रमंते तत्र शांति... आप समझे कि नहीं!■

feedback@chauthiduniya.com

ग़ज़ल

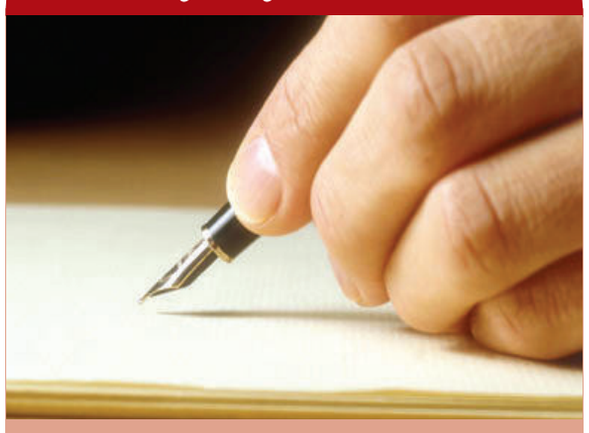

जमील अहमद

बात खुशबू की, बात फूलों की.
बात सावन की, बात झूलों की.
उम्र के इस पड़ाव पर आकर,
बात माज़ी की, बात भूलों की.
इस नए दौर में मेरे दोस्त,
बात करते हो तुम उसूलों की.
छुअन की आंच भी सह न पाया,
बात करता था, जों बगुलों की.
खुद को कांटों में कर लिया महफूज़,
हाय मजबूरियां बबूलों की.
वैसे मैंने जवाब तो दिया,
चाह कुछ और थी सवालों की.

गार्डिंग को रुचिकर बनाने के लिए यह गैजेट खास तौर पर डिजाइन किया गया है. इससे पौधों के पास की मिट्टी और एयर क्वालिटी मॉनिटर करना आसान है. इसे स्मार्ट फोन से कनेक्ट करने से लगातार मैसेज मिल सकते हैं.

दुनिया का पहला 4-के लैपटॉप

तोशिबा ने भारत में अपनी नई लैपटॉप रेंज लॉन्च की है, जिसमें दुनिया का पहला अल्ट्रा एचडी सैटेलाइट टच स्क्रीन लैपटॉप एचडी 4 के पी-50 शामिल भी है. सैटेलाइट पी सीरीज का यह लैपटॉप 4 के क्वालिटी वाला वीडियो कंटेंट प्ले कर सकता है. इसकी क़ीमत 86,000 रुपये है. इसमें आईपीएस डिस्प्ले स्क्रीन है, जो 3840 गुणा 2160 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है. यह स्टैंडर्ड फुल एचडी स्क्रीन से चार गुणा बेहतर है. यह लैपटॉप टच इनेबिल्ड है, इसी के साथ की-बोर्ड का इस्तेमाल भी इनपुट के लिए किया जा सकता है. 4 के डिस्प्ले रेजोल्यूशन को कहा जाता है. इस लैपटॉप की पी, एस और एल सीरीज के अलावा तोशिबा ने हाईब्रिड लैपटॉप भी लॉन्च किया है.

बेहतरीन स्क्रीन के साथ इस लैपटॉप में हरमन कारडॉन के स्पीकर हैं, जो ऑडियो, वीडियो, मूवीज और गेम्स में बेहतरीन साउंड देते हैं. पी-50 में स्लिम डिजाइन है, जो 27.9 एमएम पतला है. पी-50 में इंटेल का फोर्थ जेनरेशन कोर एच सीरीज का प्रोसेसर है. इसी के साथ एमडी रैडियन आर9एम265एक्स ग्राफिक्स कार्ड मौजूद है. इसमें रैम को 16 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है.

सैटेलाइट पी सीरीज : इस सीरीज के अंतर्गत सैटेलाइट पी-50 पेश किया गया है. इसकी स्क्रीन 15.6 इंच की है. यह टच स्क्रीन क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले (3840 गुणा 2160 पिक्सल का रेजोल्यूशन) देती है. व्यूइंग एंगल यूजर्स के लिए यह काफी अच्छा है. बेहतरीन स्क्रीन के साथ इस लैपटॉप में हरमन कारडॉन के स्पीकर हैं, जो ऑडियो, वीडियो, मूवीज और गेम्स में बेहतरीन साउंड देते हैं. पी-50 में स्लिम डिजाइन है, जो 27.9 एमएम पतला है. पी-50 में इंटेल का फोर्थ जेनरेशन कोर एच सीरीज का प्रोसेसर है. इसी के साथ एमडी रैडियन आर9एम265एक्स ग्राफिक्स कार्ड मौजूद है. इसमें रैम को 16 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है.

सैटेलाइट एस सीरीज : सैटेलाइट एस-40 लैपटॉप स्लिम डिजाइन के कारण लोकप्रिय हो सकता है. यह 19.3 एमएम पतला है. इसका वजन 1.87 किलो है. इसमें भी हरमन कारडॉन के स्पीकर हैं. इंटेल के फोर्थ जेनरेशन कोर आई-5 1.6 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर के साथ टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें 4 जीबी डीडीआर3एल रैम है, जिसे 16 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. एस-40 की क़ीमत 50,790 रुपये है.

सैटेलाइट एल सीरीज : इस लैपटॉप में ऑनक्यो स्पीकर हैं. एल सीरीज में 14 मॉडल्स हैं, जिनमें ग्लॉसी ब्लैक, व्हाइट, गोल्ड कलर वेरिएंट्स उपलब्ध हैं. इनकी क़ीमत 25,785 रुपये से लेकर 51,340 रुपये के बीच है. इस सीरीज के लैपटॉप में 15.6 इंच की स्क्रीन है. इसमें तीन यूएसबी पोर्ट्स हैं, जिसमें से एक डुअल यूएसबी 3.0 पोर्ट है. एक यूएसबी पोर्ट स्लीप एंड चार्ज तकनीक के साथ है. लैपटॉप ऑफ रहने के बाद भी फोन चार्ज किया जा सकता है. ङ्कएमडी क्वाड कोर ङ्कपीयू के साथ एमडी टीएम एचडी 8330 ग्राफिक्स कार्ड है.

हाईब्रिड लैपटॉप : इसे लैपटॉप और टैबलेट, दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. यह पोर्टेज जेड10टी विंडोज 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इसकी स्क्रीन 11.6 इंच की है. स्क्रीन में टच के साथ-साथ डिजिटाइजर (लाइट पेन) का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. यह लैपटॉप चार अलग-अलग प्रोसेसर ऑप्शन के साथ आता है. इसमें 4 जीबी रैम है. ■

आइडिया का बजट 3-जी स्मार्ट फोन

आइडिया ने एक सस्ता 3-जी स्मार्ट फोन लॉन्च किया है. यह फोन जितना आकर्षक दिखता है, इसके फीचर्स भी उतने शानदार हैं. यह 3-जी स्मार्ट फोन 11 सर्किलों में उपलब्ध होगा, जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हैं. इस नए आईडी-4000 स्मार्ट फोन में 4 इंच की टच स्क्रीन है. इसका कर्व डिजाइन इसकी हैंडलिंग को बेहतर बनाता है. 1.0 गीगाहर्ट्ज डुअल कोर प्रोसेसर से लैस यह नया स्मार्ट फोन एंड्रॉयड जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. यह 21.1 एमबीपीएस की तेज 3-जी स्पीड के साथ मोबाइल पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छा फोन है. इसमें 3.2 मेगा पिक्सल का रियर कैमरा है. वी-4.0 ब्लूटूथ एवं वाई-फाई जैसी सुविधाएं भी फोन की खासियत बढ़ाती हैं. इसकी मेमोरी स्टोरेज क्षमता एसडी कार्ड की मदद से 32 जीबी तक बढ़ाई जा सकती है. यह डुअल सिम स्मार्ट फोन सभी आइडिया रिटेल आउटलेट्स पर मिलेगा. आइडिया ने इसे शानदार ऑफर के साथ लॉन्च किया है. 1.6 जीबी का 3-जी डेटा और 3 महीने के लिए मुफ्त आइडिया टीवी जैसे ऑफर कंपनी फोन के साथ दे रही है. यह ऑफर पुराने ग्राहकों के लिए 259 रुपये और नए ग्राहकों के लिए 261 रुपये में उपलब्ध है. आइडिया का यह स्मार्ट फोन सिर्फ़ 4999 रुपये में उपलब्ध है.■

लेनोवो का वॉयस कॉलिंग टैबलेट

लेनोवो ने अपना दमदार ए सीरीज टैबलेट ङ्कए 7-50 भारतीय बाज़ार में पेश किया है, जो कंपनी के डू स्टोर पर मिलेगा. यह टैबलेट सिंगल सिम पर काम करता है. इसमें वॉयस कॉलिंग फीचर भी है. 7 इंच की स्क्रीन के साथ 5 मेगा पिक्सल रियर कैमरा है और 2 मेगा पिक्सल फ्रंट कैमरा. क़ीमत 15,499 रुपये है. इसमें 1280 गुणा 800 पिक्सल का रेजोल्यूशन है. इस टैबलेट में एचडी मल्टी टच आईपीएस डिस्प्ले है. 1 जीबी रैम के साथ एंड्रॉयड 4.2 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे अपग्रेड करके एंड्रॉयड 4.4 (किटकैट) भी किया जा सकता है. टैबलेट में 16 जीबी मेमोरी स्टोरेज क्षमता है, जिसे 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. इसका वजन 320 ग्राम है और बैटरी 3450 एमएएच की है. ■

एक्स-2 नेक्स्ट जेनरेशन एंड्रॉयड फोन

नोकिया ने अपना नया स्मार्ट फोन एक्स-2 बाज़ार में उतार दिया है. यह डुअल सिम फोन है, जिसकी क़ीमत लगभग 8097 रुपये है. यह नेक्स्ट जेनरेशन एंड्रॉयड फोन है और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम नए सिरे से तैयार किया गया है. स्क्रीन 4.3 इंच की है. यह 1.2 जीएचजेड डुअल कोर स्नैप ड्रैगन 200 प्रोसेसर से चलता है. रैम 1 जीबी है और इसमें 4 जीबी इंटरनल स्टोरेज क्षमता है. स्क्रीन के ठीक नीचे एक बटन है, जिससे नेविगेशन हो सकता है. पहले एक्स सीरीज के फोन में यह बटन पीछे होता था. अब आगे होने से यूजर को आसानी होगी. इसका रियर कैमरा 5 एमपी का है और बैटरी 1800 एमएएच की. माइक्रोसॉफ्ट के एप्स जैसे कि स्काइप, आउटलुक डॉट कॉम और वनड्राइव के साथ-साथ वीचैट, पाथ, फेसबुक और फेसबुक मैसेंजर भी मौजूद हैं. इस फोन का डिजाइन पहले जैसा है, लेकिन इसे ऊपर से थोड़ा पतला कर दिया गया है. यह लुमिया की तरह कई रंगों में उपलब्ध है.■

डिजाइनर गैजेट्स

बाज़ार में प्रतिदिन नए गैजेट्स आ रहे हैं, जैसे कि फोन, लैपटॉप, कैमरा. इसके साथ ही आपका काम आसान बनाने वाले गैजेट्स भी बाज़ार में उपलब्ध हैं. पेश है, ऐसे कुछ गैजेट्स के बारे में जानकारी:-

पैनासॉनिक लूमिक्स एफ जेड-1000

इस कैमरे से वीडियो फुटेज के साथ 8 मेगा पिक्सल स्टिल इमेज ली जा सकती है. कन्वेंशनल एचडी वीडियो की तुलना में इसका वीडियो परफॉर्मेंस चार गुना ज़्यादा है. लेंस फिक्स्ड है. पीछे की तरफ़ तीन इंच की एलईडी स्क्रीन है.

एडिन्ज़ गार्डन सेंसर

गार्डिंग को रुचिकर बनाने के लिए यह गैजेट खास तौर पर डिजाइन किया गया है. इससे पौधों के पास की मिट्टी और एयर क्वालिटी मॉनिटर करना आसान है. इसे स्मार्ट फोन से कनेक्ट करने से लगातार मैसेज मिल सकते हैं.

लासिई रग्ड यूएसबी 3.0 थंडरबोल्ट

यह यूएसबी उन फोटोग्राफर्स एवं वीडियोग्राफर्स, जिन्हें ज़्यादा डेटा स्टोर करना होता है, के लिए परफेक्ट है. वजन कम होने के कारण इसे कहीं भी ले जा सकते हैं. इसे ऑरेन्ज रबर कवर दिया गया है. इसे ऑरेन्ज रबर कवर वाला लाइटवेट यूएसबी 3.0 भी कहा जाता है.

छोटे वायरलेस ईयरबड्स

ईयरइन ईयरबड्स में दो छोटे ईयर पीस होते हैं. कान में फिट करने के बाद ये बिल्कुल दिखाई नहीं देते. कोई केबल न होने के कारण इन्हें पहनने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती. जब ईयर पीस न पहनने हों, तो उन्हें कैप्सूल में सुरक्षित रख दें.

बाइक फ्रेंडली ब्लूटूथ स्पीकर

स्कॉशी बूमबॉटल एच2ओ वॉटरप्रूफ ब्लूटूथ स्पीकर हैं. ये बिना रुके 11 घंटों तक लगातार चलते हैं. इन्हें बाइक (साइकिल) पर लगे बॉटल होल्डर में आसानी से फिट कर सकते हैं. ये फ्लैट सरफेस पर भी टिक जाते हैं. इन्हें ट्रैवल फ्रेंडली गैजेट कहा जा सकता है. इनमें वायरलेस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है और बिल्ट-इन रिचार्जेबल बैटरी है. ये तीन रंगों यानी येलो, ग्रे और ब्लू में उपलब्ध हैं. आप अपनी पसंद का रंग चुन सकते हैं. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

बदहाली का शिकार महिला फुटबॉल

भारत में महिला–पुरुष को लेकर होने वाला भेदभाव खेलों में भी दिखाई दे रहा है. भारतीय महिला फुटबॉल टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है. हालिया जारी फीफा रैंकिंग में उसे विश्व में 50वां स्थान हासिल हुआ है. फीफा विश्वकप में महिला टीम के शिरकत कर सकने की संभावनाएं प्रबल नज़र आ रही हैं, लेकिन वह दोहरे मापदंडों का शिकार हो रही है. 2017 में भारत में पुरुषों का अंडर–17 विश्वकप आयोजित होना है, क्या ऐसे में महिला फुटबॉल की तस्वीर बदलेगी?

नवीन चौहान

दुनिया भर में फुटबॉल का बुखार चढ़ा हुआ है, भारत भी इससे अछूता नहीं है. भारत के लोग अपने–अपने हिसाब से विभिन्न टीमों का समर्थन कर रहे हैं. यदि आपसे यह पूछा जाए कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान का नाम क्या है, तो आप झट से कह उठेंगे कि सुनील छेत्री अथवा फिर बाइचुंग भूटिया. लेकिन, महिला फुटबॉल टीम की कप्तान का नाम पूछे जाने पर आपकी ज़ुबान खामोश रह जाएगी. जिस टीम की कप्तान के बारे में आपको जानकारी नहीं है, वही टीम पुरुषों की टीम से कोसों आगे है. हाल में फीफा ने जो रैंकिंग जारी की है, उसके अनुसार, भारतीय महिला फुटबॉल टीम दुनिया में 50वें पायदान पर है, जबकि पुरुष टीम 154वें पायदान पर. साथ ही महिला टीम को एशिया में 11वां स्थान मिला है. महिला फुटबॉल की यह स्थिति तब है, जब भारत में न तो महिला फुटबॉल की कोई लीग है, न उन्हें मैच फीस दी जाती है और न उनकी सुनील छेत्री जैसी फैन फॉलोविंग है. बावजूद इसके, भारतीय महिलाएं पुरुषों से 100 से भी ज़्यादा रैंक आगे हैं. और विडंबना देखिए, भारतीय महिला टीम कभी भी सुर्खियों का हिस्सा नहीं बनती.

सबसे ज़्यादा अचंभित करने वाली बात यह है कि भारतीय टीम की रैंकिंग उत्तरी आयरलैंड, ग्रीस, क्रोएशिया, आईवरी कोस्ट एवं उरुग्वे आदि से ज़्यादा है. पुरुष फुटबॉल में जहां 205 देशों की भागीदारी है, वहीं महिला फुटबॉल में 175 देशों की. भारतीय टीम चीन और जापान जैसी मज़बूत टीमों से पार नहीं पा पाती है, अन्यथा भारतीय महिलाएं भी फीफा विश्वकप में खेलती दिखाई दें. इसका सबसे प्रमुख कारण है कि महिला खिलाड़ियों को नियमित तौर पर अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का मौक़ा नहीं मिलता है. इन हालात में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है. भारतीय महिला टीम ने अपना आख़िरी अंतरराष्ट्रीय मैच मई 2013 में फिलिस्तीन में हुए एशियाई खेलों के क्वालीफायर्स के दौरान खेला था, जहां उसे म्यांमार और ताइवान से हार मिली और फिलिस्तीन के साथ मैच ड्रा हुआ था. इससे पहले अक्टूबर 2007 से 2010 तक तीन साल के अंतराल में भारतीय महिला टीम ने कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला था. एआईएफएफ एक भी दोस्ताना मैच आयोजित नहीं कर पाया और इसे उसका लापरवाह रवैया ही कहा जाएगा. इसके बाद जून 2010 में फीफा ने भारतीय फुटबॉल संघ को चेतावनी दी कि यदि भारतीय महिला फुटबॉल टीम कोई मैच नहीं खेलेगी, तो वह उसे फीफा रैंकिंग से बाहर कर देगा, क्योंकि उसके पास रैंकिंग अंक देने का कोई आधार नहीं है. किसी भी टीम की रैंकिंग पिछले कुछ समय में उसके द्वारा खेले गए मैचों के परिणामों के आधार पर तय होती है. इसके बाद खेल प्रशासकों की नींद खुली और मैच आयोजित किए गए.

भारत में फुटबॉल खेलने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत कम है. भारतीय महिला टीम में सामर्थ्य भले ही कम हो, लेकिन परिस्थितियां धीरे–धीरे बदल रही हैं. भारतीय टीम को इस साल नवंबर में पाकिस्तान में होने वाली सैफ (एसएएफएफ) चैंपियनशिप में भाग लेना है. भारतीय टीम लगातार दो बार यह प्रतियोगिता जीत चुकी है. इस बार वह जीत की हैट्रिक बनाने की कोशिश करेगी. कुछ समय पहले महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं का आयोजन केवल खानापूर्ति के लिए किया जाता था. आयोजकों को 20 दिनों में 50 मैचों की पूरी प्रतियोगिता आयोजित करने की ज़िम्मेदारी सौंप दी जाती थी. आयोजक खराब मैदान और विपरीत परिस्थितियों में कई बार तो कम रोशनी में मैच आयोजित कर देते थे, लेकिन अब परिस्थितियों में थोड़ा बदलाव आ रहा है. आईएएफएफ अब आयोजन के लिए ऑब्जर्वर और एडवाइजरों की नियुक्ति करता है.

भारत सरकार महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कोई योगदान नहीं कर रही है. महिला फुटबॉल को प्रोत्साहित करने के लिए कोई स्पॉन्सर भी सामने नहीं आ रहा है. महिला खिलाड़ियों को सबसे निम्न स्तर की सुविधाएं मिल रही हैं. जहां मैचों का आयोजन होता है, वहां उनके बेहतर लिए चेंजिंग रूम भी उपलब्ध नहीं होते हैं.

सबसे बड़ी परेशानी यह है कि केवल कमजोर तबके की लड़कियां ही फुटबॉल खेलने के लिए आगे आ रही हैं. उनमें से भी अधिकांश को फुटबॉल में करियर बनता नहीं दिखता, तो वे बीच में ही खेलना छोड़ देती हैं. इसके बावजूद कुछ अच्छी ख़बरें सुनने को मिल जाती हैं. हाल में भारत की दो महिला खिलाड़ियों को मालदीव के फुटबॉल क्लब न्यू रेडिएंट ने साइन किया था, जिनमें 34 वर्षीय भारतीय कप्तान बेमबेम देवी और 19 वर्षीय डिफेंडर लेको फुती भूटिया शामिल थीं. भारत की सबसे बड़ी महिला फुटबॉल खिलाड़ी ओइनेम बेमबेम देवी हैं, जो एक मिडफील्डर हैं. वर्तमान में वह टीम की कप्तान हैं. उनके नाम 18 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 11 गोल दर्ज हैं. उन्हें 2013 में एआईएफएफ ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना था. वह इस बार भारत को लगातार तीसरा सैफ चैंपियनशिप खिताब जिताने की कोशिश में हैं. 13 साल की उम्र में मणिपुर के लिए फुटबॉल खेलना शुरू करने वाली बेमबेम देवी की ओर मीडिया की नज़र कभी–कभार पड़ जाती है. बेमबेम के करियर का सबसे अहम पड़ाव 1996 में आया था, जब उन्होंने बैंकॉक में हुए एशियाई खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया था. इसके बाद वह भारतीय महिला फुटबॉल की धुरी बन गईं. उन्हें महिला फुटबॉल के भविष्य को लेकर बहुत आशाएं हैं, खासकर तब, जब भारतीय टीम की रैंकिंग 50वीं है. वेतन के रूप में खिलाड़ियों को कुछ नहीं दिया जाता है. जब खिलाड़ी देश के लिए खेल रहे होते हैं, तब उन्हें भत्ते के रूप में देश में 600 रुपये और विदेश में 30 अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं. ऐसे में, खिलाड़ियों से प्रोफेशनलिज्म की अपेक्षा नहीं की जा सकती. वेतन के बारे में बेमबेम देवी का कहना है कि महिला फुटबॉल में व्यवसायिक लीग आने से ही कोई बदलाव आ सकता है. यदि हमारे लिए आई लीग जैसा कुछ हो जाए, तो हम और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे. सरकार के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है. सरकार एक टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए दो लाख रुपये मुहैया कराती है, जबकि एक टूर्नामेंट आयोजित करने में एक करोड़ रुपये का खर्च आता है. जो धनराशि सरकार द्वारा दी जाती है, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है. महिला और पुरुष वर्ग में हर साल तीन–तीन प्रतियोगिताएं आयोजित करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा पैसे की कमी के चलते नहीं हो पाता. यह स्थिति केवल फुटबॉल की नहीं है, बल्कि क्रिकेट और हॉकी को छोड़कर अधिकांश खेलों की लगभग यही हालत है.

भारत सरकार महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कोई योगदान नहीं कर रही है. महिला फुटबॉल को प्रोत्साहित करने के लिए कोई स्पॉन्सर भी सामने नहीं आ रहा है. महिला खिलाड़ियों को सबसे निम्न स्तर की सुविधाएं मिल रही हैं. जहां मैचों का आयोजन होता है, वहां उनके लिए बेहतर चेंजिंग रूम भी उपलब्ध नहीं होते हैं. इसके बावजूद महिला खिलाड़ी किसी तरह की शिकायत नहीं करती हैं और बेहतरीन कोशिश करती दिखती हैं. महिला खिलाड़ियों के लिए न तो विदेशी कोच उपलब्ध हैं और न ट्रेनर. इन बहादुर महिला खिलाड़ियों को विदेश दौरे पर जाने के भी बहुत कम मौक़े मिलते हैं. अब समय आ गया है कि एआईएफएफ महिला खिलाड़ियों के बारे में गंभीरता से सोचे और महिला फुटबॉल के विकास के लिए कोई ठोस निर्णय ले. अच्छी सुविधाएं और प्रशिक्षण उपलब्ध होने पर भारतीय महिला टीम इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने की ताकत रखती है. हो सकता है कि महिलाएं फीफा विश्वकप में पुरुषों से पहले भारत की नुमाइंदगी करती नज़र आएं. ■

feedback@chauthiduniya.com

सचिन के सम्मान में सिक्का जारी

भारत पर बरसों तक राज करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200वां टेस्ट मैच खेल कर संन्यास लेने वाले सचिन तेंदुलकर के सम्मान में सोने का सिक्का जारी किया है, जिसकी क़ीमत लगभग 12,000 पाउंड है. ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि तेंदुलकर के सम्मान में वैश्विक स्तर पर 200 ग्राम सोने के केवल 210 सिक्के जारी किए गए हैं. केवल कुछ लोग ही सिक्के को देख पाएंगे. यह सिक्का अपने आप में विशिष्ट है. इसे विशेष रूप से तैयार किए गए बॉक्स में रखा गया है. इस सिक्के के साथ सचिन तेंदुलकर द्वारा हस्ताक्षरित बैट भी दिया जाएगा. तेंदुलकर ने सिक्का जारी होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इससे खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं. इस सिक्के में सचिन का हस्ताक्षरित बैट, उनकी टेस्ट जर्सी का नंबर 187 और गेट वे ऑफ इंडिया अंकित है, जो मुंबई में खेले गए आख़िरी टेस्ट मैच को दर्शाता है. ग़ौरतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई में जन्मे व्यवसायी संजीव ने 33 विभिन्न शेयरधारकों से खरीदा था. इसके बाद उन्होंने इसे दुनिया के एक बड़े लक्जरी ब्रांड में तब्दील कर दिया है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

श्रीलंका की ऐतिहासिक जीत

श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ संपन्न हुई दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1–0 से जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया. एंजिलो मैथ्यूज ने कप्तान और खिलाड़ी के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन किया और टीम को जीत दिलाई. सीरीज के दोनों टेस्ट मैचों का अंत बड़े रोमांचक ढंग से हुआ. पहले टेस्ट मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका के सामने मैच बचाने की चुनौती थी, जिसे एंजिलो मैथ्यूज ने कप्तानी पारी खेलते हुए बचा लिया, लेकिन जब ऐसी ही स्थिति इंग्लैंड के सामने खड़ी हो गई, तो जेम्स एंडरसन मैच की सेकेंड लास्ट बॉल पर रंगना हीरथ के हाथों आउट हो गए और श्रीलंका 100 रनों से मैच जीतने में कामयाब हो गया. श्रीलंका ने अपने टेस्ट इतिहास में इंग्लैंड की धरती पर तीसरा टेस्ट जीता है. इससे पहले उसने 1998 में अर्जुन रणतुंगा की कप्तानी में एक टेस्ट मैच की सीरीज में जीत दर्ज की थी. इसके अलावा 2006 में टेंट ब्रिज में भी उसे जीत मिली थी. इंग्लैंड के बल्लेबाज मोईन अली के लिए यह हार बहुत निराशाजनक रही, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को शुरुआती झटकों से उबारते हुए लगभग सात घंटे तक बल्लेबाजी की और अपने करियर का पहला टेस्ट शतक लगाते हुए 108 रनों की पारी खेली, लेकिन वह अपनी टीम को हार से नहीं बचा सके. ■

हॉट सीन देने से ऐतराज नहीं

जन्नत-2 से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री ईशा गुप्ता अपनी आगामी फिल्म हमशक्ल्स को लेकर काफी उत्साहित हैं. बॉलीवुड में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती ईशा कहती हैं कि बॉलीवुड में बिना किसी गॉड फादर के पहचान बनाना काफी मुश्किल है. दिल्ली से मुंबई वह अपने सपने पूरे करने आई थीं और इसमें उनके परिवार ने भी खूब साथ दिया. दिल्ली से यहां आते समय उन्होंने अपनी बहन से कहा था कि वह अपने बलबूते अपनी मंजिल हासिल करेंगी, लेकिन मुंबई आकर उन्होंने महसूस किया कि यह सफर इतना आसान भी नहीं है, जितना वह सोचकर यहां आई थीं. उनके पास तब कार भी नहीं थी. उन्होंने शहर से दूर बीस हज़ार रुपये महीने किराये पर फ्लैट लिया. तब फ्लैट का किराया देना भी उनके लिए मुश्किल होता था. मॉडलिंग और रैंप शो से वह जो पैसे कमाती थीं, उसका बड़ा हिस्सा स्टूडियो और प्रोड्यूसर के पास चला जाता था, लेकिन तब भी वह हिम्मत नहीं हारीं. भट्ट कैंप से शुरुआत करने के बाद उन्हें प्रकाश झा और साजिद खान जैसे नामी

ईशा कहती हैं कि वह काफी बोल्ड हैं और कोई भी सीन करने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई की खातिर उन्हें जिस्म की नुमाइश करने से ऐतराज है. दिल्ली में उन्हें चांदनी चौक और बंगाली मार्केट काफी पसंद हैं.

निर्देशकों के साथ काम करने का मौक़ा मिला. साजिद खान के साथ काम करने को लेकर वह कहती हैं कि शूटिंग के दौरान उन्हें ऐसा लग रहा था, जैसे कहीं पिकनिक इंज्वॉय करने आई हैं. साजिद बहुत ही कूल तरीके से शूटिंग करते हैं, एक दिन पहले ही सीन्स के बारे में बता देते हैं और सेट पर वैसा माहौल तैयार कर देते हैं, जैसा सीन उन्हें शूट करना होता है. ईशा कहती हैं कि वह काफी बोल्ड हैं और कोई भी सीन करने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई की खातिर उन्हें जिस्म की नुमाइश करने से ऐतराज है. दिल्ली में उन्हें चांदनी चौक और बंगाली मार्केट काफी पसंद हैं. यहां उनका परिवार रहता है और यहां उनका पसंदीदा खाना भी मिलता है. दिल्ली में देर रात आप घर से नहीं निकल सकते, लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं है. शूटिंग ख़त्म करने के बाद आधी रात के समय भी घर जाते हुए उन्हें तनिक डर नहीं लगता. ■

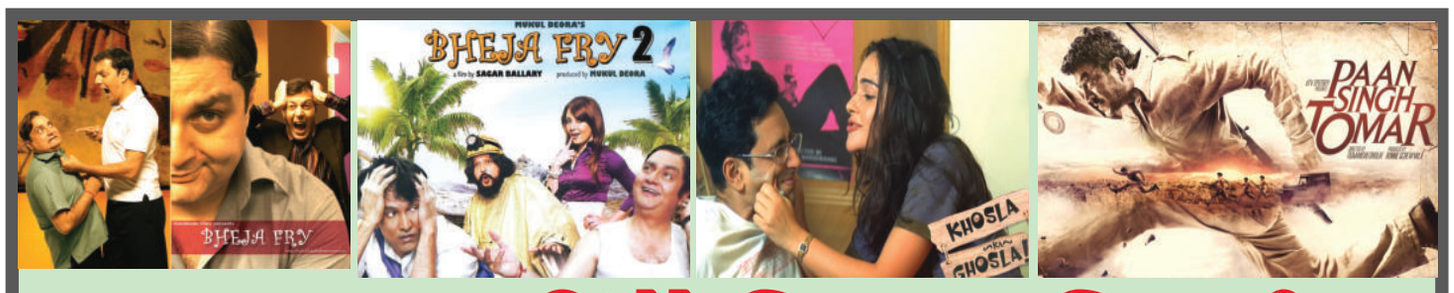

आसान नहीं है फिल्म निर्माण

संजीव कमल जुल्का

फिल्म निर्माण आसान काम नहीं है. यह काफी जोखिम भरा है. विशेषकर, कम बजट की बिना स्टार वाली फिल्में ज़्यादातर बॉक्स ऑफिस पर असफल रहती हैं. इस वर्ष अभी तक कोई कम बजट और बिना स्टार वाली फिल्म नहीं चल सकी है. पिछले कुछ वर्ष इस मामले में अपवाद ज़रूर रहे. कम बजट वाली फिल्मों के हिट और फ्लॉप होने की शुरुआत हुई थी फिल्म भेजा फ्राई से. यह कम बजट एवं बिना स्टार की फिल्म होते हुए भी खूब चली. इसके बाद कुछ और छोटी फिल्में जैसे, खोसला का घोंसला, पान सिंह तोमर, फंस गए ओबामा आदि आईं. इनमें से लेटेस्ट फिल्म थी लंच बॉक्स, जो खूब चली, पर ऐसी फिल्में बहुत कम ही हैं. ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, जो कम बजट या बिना स्टार के बनती हैं. इसके कई कारण हैं. आजकल फिल्में बहुत बनती हैं और उनमें आपस में ही काफी प्रतिस्पर्धा होती है. ये बड़े बजट की फिल्मों के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पातीं. छोटी फिल्में रिलीज के लिए ऐसा हफ्ता ढूंढती हैं, जब कोई बड़ी फिल्म न हो. हालांकि, ऐसे हफ्ते भी बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं. और, जो भी ऐसा हफ्ता मिलता है, उसमें इतनी सारी छोटी फिल्में आ जाती हैं कि उनमें आपस में काफी प्रतिस्पर्धा हो जाती है. यही नहीं, हॉलीवुड की फिल्में भी उन्हें टक्कर देती हैं. छोटे बजट या बिना स्टार वाली फिल्मों को सबसे तगड़ी टक्कर मिल रही है टेलीविजन से. आजकल ज़्यादा बिजनेस वीकएंड यानी हफ्ते के तीन दिन शुक्रवार से लेकर रविवार तक होता है और इन दिनों में टीवी पर बड़ी-बड़ी हस्तियों और बड़े-बड़े स्टारों के कार्यक्रम, जैसे दस का दम, कौन बनेगा करोड़पति आदि छाए रहते हैं. ऐसे में दर्शक फिल्में देखने जाने की बजाय टीवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं. इन छोटे बजट की फिल्मों को हॉलीवुड, टीवी और बड़े बजट की फिल्मों से टक्कर मिल ही रही थी कि आईपीएल भी मैदान में आ गया. आईपीएल के समय ज़्यादातर शाम के शो प्रभावित होते हैं. इसीलिए, बड़ी फिल्में ऐसे समय में आने की हिम्मत नहीं कर पातीं. जो समय बड़ी बजट की फिल्में रिलीज के लिए बेहतर नहीं मानतीं, उसी समय छोटे बजट की फिल्में रिलीज होती हैं.

छोटी फिल्में रिलीज के लिए ऐसा हफ्ता ढूंढती हैं, जब कोई बड़ी फिल्म न हो. हालांकि, ऐसे हफ्ते भी बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं. और, जो भी ऐसा हफ्ता मिलता है, उसमें इतनी सारी छोटी फिल्में आ जाती हैं कि उनमें आपस में काफी प्रतिस्पर्धा हो जाती है.

इनमें कुछ फिल्में खासी अच्छी होती हैं, बावजूद इसके वे बाकी फिल्मों की भीड़ में खो जाती हैं. परीक्षा के दौरान विशेषकर, फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक फिल्म रिलीज के लिए अच्छा वक्त नहीं होता. छोटी फिल्में ही इस समय आती हैं और वे भी फ्लॉप हो जाती हैं. मध्यम या बड़े बजट की फिल्में, जिनमें स्टार या सेमी-स्टार, नए उभरते हुए नायक-नायिकाएं होते हैं, वे अच्छे संगीत, अच्छे अभिनय और अच्छी मार्केटिंग की बदौलत ज़्यादा अच्छी न होते हुए भी चल जाती हैं. दर्शकों की तादाद बहुत बड़ी है. खासकर, मल्टीप्लेक्स के आ जाने से अब लोग फिल्में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं. मल्टीप्लेक्स आने के बाद अच्छे कलाकारों वाली फिल्मों को, जिन्हें हम आर्ट सिनेमा भी कहते हैं, काफी प्रोत्साहन मिला है. इस तरह के सिनेमा के दर्शक अलग होते हैं, जिन्हें हम क्लास ऑडियंस कहते हैं, लेकिन ऐसी फिल्में भी बहुत कम कामयाब होती हैं. कामयाब होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि फिल्में मनोरंजक हों और वे दर्शकों को बांधे रख सकें. कई और बातें हैं, जिनका स्क्रिप्ट एवं कहानी में ख्याल रखना ज़रूरी है, जिससे वह फिल्म दर्शकों को पसंद आए. मल्टीप्लेक्स में हॉलीवुड और छोटे बजट वाली फिल्मों की टिकट दरें बड़ी फिल्मों के लगभग बराबर होती हैं. ज़्यादा पैसे देकर छोटे स्टारों वाली फिल्म देखने भला कोई क्यों जाएगा. एक फिल्म देखने में टिकट, आने-जाने और जलपान आदि मदों में एक बड़ी रकम खर्च हो जाती है. फिल्म इंडस्ट्री में जोखिम बहुत ज़्यादा होता है. जबकि किसी अन्य उद्योग में इतना ज़्यादा जोखिम नहीं होता. अगर आप कोई अन्य उद्योग शुरू करेंगे, तो जमीन, मशीनें एवं फर्नीचर आदि खरीदने में पैसे खर्च होंगे. मान लीजिए, अगर बना हुआ माल न भी बिका, तो जमीन, मशीनें, फर्नीचर वगैरह बेचकर काफी पूंजी वापस मिल जाएगी और नुक़सान कम होगा. जबकि फिल्म निर्माण के धंधे में नुक़सान के बाद कुछ भी नहीं बचता यानी सारा पैसा डूब जाता है. इतने जोखिम के बावजूद लोग फिल्म बनाते हैं. टीवी जहां फिल्मों के लिए चुनौती बनकर सामने आया, वहीं राहत भी लाया है.

आजकल चैनल फिल्में चलाने के लिए अच्छी क़ीमत चुकाते हैं. कुल लागत का 50-60 प्रतिशत हिस्सा निकल आता है. कई बड़े प्रोड्यूसर तो 80 से 100 प्रतिशत तक लागत वसूल कर लेते हैं, लेकिन ऐसी किस्मत सभी फिल्म निर्माताओं की नहीं होती. फिर भी लोगों में फिल्में बनाने का क्रेज है, क्योंकि उनमें अपनी बात और कहानी पर्दे पर कहने का जुनून होता है.■

feedback@chauthiduniya.com

इंज्वॉय कर रहे हैं सुनील

अभिनेता सुनील शेट्टी 90 के दशक में बेहतरीन अभिनेताओं में गिने जाते थे. वह आज भी फिल्मों में काम कर रहे हैं. अपनी अगली फिल्म में वह एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं. हालांकि, पुलिस ऑफिसर के रोल में वह पहले भी दिख चुके हैं. उनकी पिछली फिल्म थी, देसी कट्टे. यह एक रिटायर्ड आर्मी मैन की कहानी है, जो काफी एग्रेसिव है और हमेशा सोचता है कि उसे कुछ हासिल करना है. जब वह खुद कुछ नहीं कर पाता, तब कुछ लड़कों के जरिये अपना लक्ष्य साधने का प्रयास करता है. देसी कट्टे के मुख्य किरदार दो लड़के यानी जय और अखिल हैं. लेकिन, सुनील मानते हैं कि फिल्म में उनकी भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं थी. रोमांटिक अभिनेता के तौर पर पहचान रखने वाले सुनील ने इस फिल्म में कोई लव सीन नहीं दिया. कहते हैं कि अब वह अपनी उम्र के मुताबिक भूमिका कर रहे हैं. वह कहते हैं कि उम्र, अनुभव और समय के हिसाब से सफलता, असफलता सब स्वीकार करनी चाहिए. पहले उनके पास काफी काम होता था, लेकिन अब कम काम है. सुनील ने अपने फिल्मी करियर में हर तरह की भूमिकाएं कीं. अब वह वैसी भूमिकाएं करते हैं, जो उनकी उम्र और व्यक्तित्व के लिहाज से उचित होती हैं. ■

अब अक्षय होंगे तमन्ना के हीरो

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने हिम्मतवाला से बॉलिवुड में एंट्री की. अब उनकी दूसरी फिल्म हमशकल्स रिलीज होने वाली है. अजय और सैफ के साथ काम कर चुकीं तमन्ना अब अक्षय के साथ काम करने को लेकर काफी उत्सुक हैं. वह कहती हैं कि उनके तीनों ही हीरो किसी न किसी मामले में खास हैं. अजय की खास बात उन्हें यह लगी कि वह अपने अगले शॉट के बारे में डायरेक्टर से बात करते हैं. अजय का स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होता है. अक्षय दूसरों की मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं. बॉलीवुड में उनके करियर की शुरुआत की खास बात यह है कि उनकी तीनों ही फिल्में साजिद खान की है. लगातार साजिद की फिल्मों में काम करने की वजह से उनका नाम साजिद से जोडा जाने लगा था, लेकिन तमन्ना इस बारे में कहती हैं कि साजिद और वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. वह कहती हैं कि साजिद उनके भाई हैं और वह साजिद को राखी बांधती हैं ऐसे में साजिद से उनके अफेयर की बात उन्हें हास्यास्पद लगती है. ■

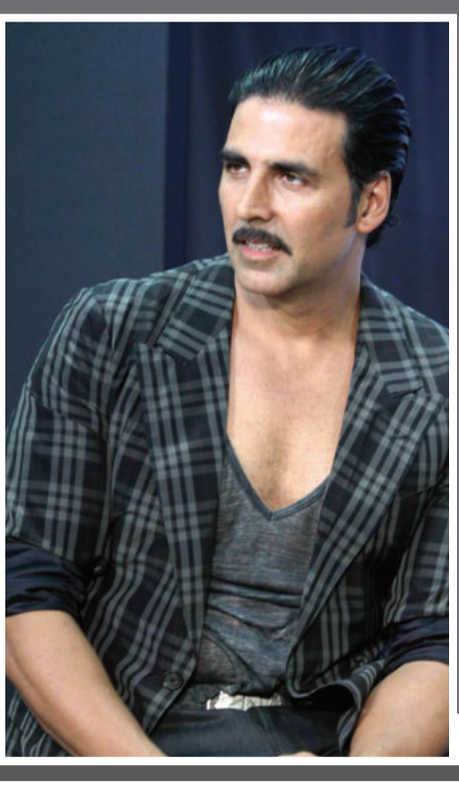

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

07 जुलाई–13 जुलाई 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार झारखंड

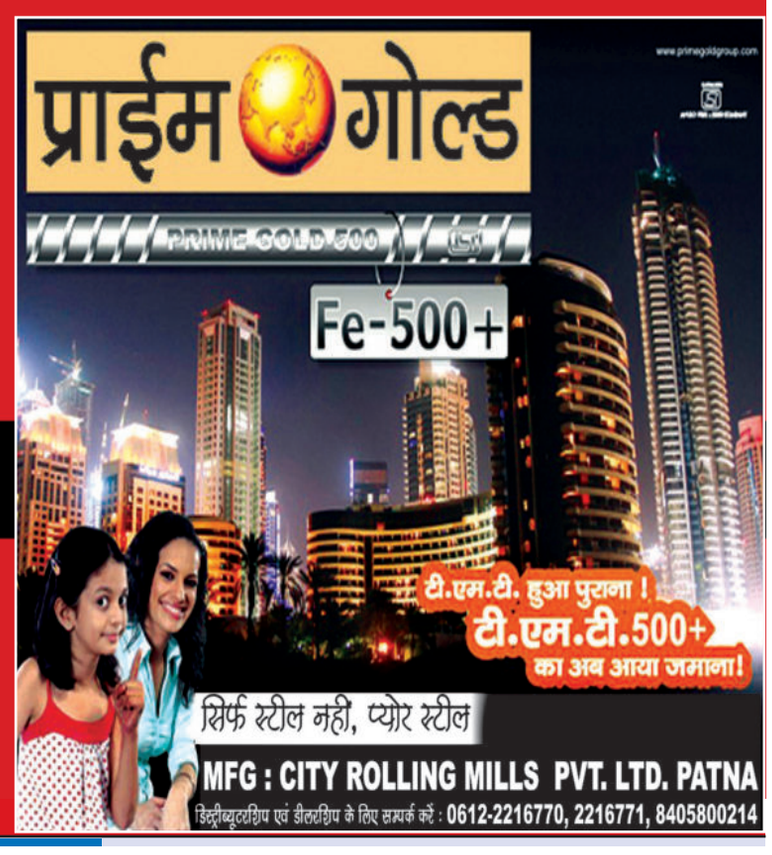

लाभ लेने के बाद

वैश्यों को भुला देते हैं राजनीतिक दल

वैश्यों के जितने छोटे व बड़े नेता हैं उनको लेकर लगभग प्रत्येक राजनीतिक दल ने उपेक्षा का ही भाव रखा है. इन नेताओं के जरिए इस समाज के वोट तो प्रत्येक दल हासिल करता रहा है पर जब उनके खुद की हिस्सेदारी की बात आती है तो हर दल गुम्मी गोली खाकर सो जाते हैं. वैश्यों की इस दुर्गति के लिए खुद वैश्य नेता भी कम जिम्मेदार नहीं हैं. आपसी तालमेल के अभाव में मजबूती से ये नेता समाज के हित की बात सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं.

सरोज सिंह

यह मानी हुई सच्चाई है कि बिहार की राजनीति को जातीय गणित कई मायनों में प्रभावित करता है. चुनावी नतीजों में जातीय भागीदारी के रंग बीते लोकसभा चुनाव में भी दिखे. लेकिन लगता है प्रदेश की मौजूदा सरकार के चुनावी मैनेजर इस रंग से अब तक वाकिफ नहीं हो पाए हैं. सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक ताकत का रुतबा रखने वाले वैश्य समाज को लेकर भी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है. इसका ताजा उदाहरण उस समय मिला जब मांझी मंत्रिमंडल के नए विस्तार में वैश्य समाज के एक भी नेता को जगह नहीं मिल पाई. यही नहीं जदयू के अलावा राजद ने भी इस मोर्चे पर गलतियों से कोई सबक नहीं सीखी और लोकसभा चुनाव में उन्हें तवज्जो नहीं दी. हालत यह है कि वैश्य समाज को मांझी कैबिनेट में एक अदद मंत्री पद भी नसीब नहीं हुआ. इससे यह समाज अंदरूनी तौर पर काफी उद्वेलित है. तीस सदस्यीय मंत्रिपरिषद में एक भी वैश्य नेता को जगह नहीं मिलना हैरतअंगेज है. अभी वैश्य समुदाय से ललन सर्राफ को विधान परिषद में मनोनीत कर इस जख्म को सहलाने की कोशिश की गई है. इतिहास के पन्नों को पलटें तो कांग्रेस शासन में इस समुदाय से पूर्व मंत्री लहटन चौधरी जैसे काफी प्रभावशाली मंत्री हुआ करते थे. वह कई मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में रहे. उनका कद अपने किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं होता था. लालू राज में भी शंकर प्रसाद टेकरीवाल, बृजबिहारी प्रसाद और रमा देवी, रामचन्द्र पूर्वे जैसे दबदबे वाले वैश्य नेता कैबिनेट में थे. टेकरीवाल के जिम्मे वित्त जैसा महत्वपूर्ण विभाग तक था. बृजबिहारी और रमा देवी के जिम्मे पूरा चम्पारण था. लालू–राबड़ी कैबिनेट के सबसे शरीफ मंत्रियों में शुमार किए जाने वाले रामचन्द्र पूर्वे के जिम्मे शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग था. भाजपा व जदयू की सरकार में सुशील कुमार मोदी उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री के पद पर काबिज थे. माना जाता है कि मोदी के वित्त मंत्री रहने के दौरान वैश्य समुदाय के लोगों को अपनी बात वित्त विभाग में कहने में काफी सहुलियत होती थी. वहीं, सुनील कुमार पिंटू राज्य सरकार में पर्यटन मंत्री थे. हालांकि, दोनों भाजपा के कोटे से ही इस पर नियुक्त किए गए थे. वैसे भी वैश्य समुदाय को मूल रूप से भाजपा का ही वोटर माना जाता है.

जनसंघ के जमाने से लेकर जबतक भाजपा का आधार काफी सीमित रहा तो, इसको बनियों की पार्टी कहा जाता था. इसके नेता एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इसी बिरादरी से आते हैं. अभी बिहार से दो वैश्य लोकसभा सदस्य चुनाव जीते हैं. शिवहर लोकसभा क्षेत्र से रमा देवी और पश्चिमी चम्पारण क्षेत्र से संजय जायसवाल. दोनों भाजपा के सांसद हैं. इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दो वैश्य उम्मीदवार इतारे, जदयू ने भी दो वैश्यों को टिकट दिया. मुजफ्फरपुर से विजेन्द्र चौधरी एवं कटिहार से रामप्रकाश महतो. जबकि, राजद ने किसी वैश्य उम्मीदवार को टिकट देना तक मुनासिब नहीं समझा. यह अवश्य है कि राजद में उनके मुख्य सलाहकार प्रेमचन्द्र गुप्त हैं और उनके कहने पर आंख मूंद कर चलने वाले प्रदेश अध्यक्ष रामचन्द्र पूर्वे भी इसी बिरादरी से आते हैं. रामचन्द्र पूर्वे भी लोकसभा टिकट के लिए दा–वेदारी कर रहे थे. लेकिन, उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी गई. उनके बदले लालू प्रसाद ने अपने निजी सहायक विनोद श्रीवास्तव को उम्मीदवारी प्रदान कर दी. राजद के एक नेता नाम उजागर न करने की शर्त पर कहते हैं कि श्रीवास्तव को टिकट देना लालू की मजबूरी थी. वैसे, विनोद श्रीवास्तव अपने स्वजातीय कायस्थ मतदाताओं का मत लेने में सफल रहे. जबकि, कायस्थ को भाजपा का खांटी समर्थक मतदाता माना जाता है. वहीं, अन्य दलों ने जहां भी वैश्य उम्मीदवारों को टिकट दिया, वहां भी वैश्य समुदाय का मत पूरी तरह भाजपा के पीछे लामबंद था. हालांकि, वैश्य समुदाय के नेतागण इसे नकार देते हैं. उनका भी तर्क कमजोर नहीं है. 2009 के लोकसभा

(शेष पृष्ठ 18 पर)

कृष्णा प्रसाद

बिजेन्द्र चौधरी

संजय वर्मा

गंगा प्रसाद

समीर महासेठ

एक नज़र

महाविद्यालय बना राजनीतिक अखाड़ा

चतरा जिला के अन्तर्गत राम नारायण स्मारक महाविद्यालय इन दिनों चतरा विधायक जनार्दन पासवान द्वारा राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है जिसके कारण विगत आठ माह से महाविद्यालय कर्मीगण को मासिक मानदेय नहीं मिल रहा है. बात इस प्रकार है कि राम नारायण स्मारक महाविद्यालय के सचिव पद का चुनाव होना है जिसमें जिला के शिक्षा अधिकारी डी०ई०ओ० द्वारा अनुमण्डल अधिकारी, शिक्षाविद, प्रचार्य, स्थानीय विधायक एवं भू-दाता आदि की एक कमिटी बनाई जाती है. इसी कमिटि के द्वारा एक सचिव का चुनाव होता है और सचिव एवं प्रचार्य के संयुक्त हस्ताक्षर से शिक्षक एवं कॉलेजकर्मी का मानदेय का भुगतान किया जाता है. इस कमिटी को पूरा करने में विधायक अपना राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं. विधायक पासवान अपने चहेते को शिक्षाविद बनाना चाहते है, जबकि विधायक के चहेते को कॉलेज कर्मी सिरे से नकारते रहे है. विधायक जानबूझकर महाविद्यालय को प्रभावित कर रहे हैं और अपनी विधायिका का रौब दिखाकर गलत नियुक्ति करना चाहते है जो प्रचार्य नहीं चाहते हैं. बताते चले कि विधायक पासवान के रौब से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं आरडीडीई०ओ० इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है यही कारण है कि आज तक आठ माह बीतने के बाद भी कॉलेज कर्मी को मानदेय भुगतान नहीं हो पाया और फिलहाल भुगतान के आसार नहीं बन रहे है. जिसे महाविद्यालय के प्रचार्य द्वारा उपायुक्त अमित कुमार को महाविद्यालय कर्मी के मानदेय भुगतान को लेकर एक आवेदन दिया गया है तथा उपायुक्त जल्द से जल्द भुगतान कराने का आश्वासन दिया है. शिक्षा संस्थान में हो रहे राजनीति का असर तीन माह बाद झारखण्ड विधान सभा के चुनाव में विधायक को भुगतना पड़ सकता है.

-अमरेन्द्र प्रताप

राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिला कांग्रेस कार्यालय ललित आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जन्मदिन मनाई. सीतामढी जिलाध्यक्ष विमल शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मौके पर गरीब बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया. इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में देश के अंदर राहुल गांधी जैसे युवा नेता को युवा वर्ग दिल से चाहने लगे है. कार्यक्रम में उपाध्यक्ष सीताराम झा, सत्येंद्र कुमार तिवारी, मो असद, विजेंद्र कुमार यादव, नगर अध्यक्ष सीमा गुप्ता समेत अन्य मौजूद थे.

-ब्रजेश

मांझी की सरकार में बेगूसराय गायब

भाजपा-जद यू गठबंधन टूटने के बाद जदयू को भरोसा था कि नीतीश कुमार जब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो बेगूसराय को मंत्रिमंडल में अवश्य स्थान दिया जाएगा. नीतीश कुमार तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए. जीतन राम मांझी ने तो बेगूसराय के जदयू के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की उम्मीद पर तुषारापात ही कर दिया. जबकि कांग्रेस एवं राजद के शासनकाल में भी बेगूसराय को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त था. हरिहर महतो, भोला सिंह, रामजीवन सिंह, श्रीनारायण यादव मंत्री हुआ करते थे. लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जीतन राम मांझी ने अपने मंत्रिमंडल में बेगूसराय को स्थान न देकर न सिर्फ जदयू बल्कि जिले की जनता का उपहास किया है.

सुरेश चौहान/रघुवीर झा

जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल में बेगूसराय को प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने से जदयू नेता एवं कार्यकर्ता काफी निराश एवं हताश हैं. जो पार्टी के घटते जनाधार के लिए शुभ संकेत नहीं है. पार्टी को इसका खामियाजा आगामी विधान सभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है. यों भी लोकसभा के चुनाव परिणाम से यह खुलासा हो चुका है कि जिले में जदयू का जनाधार खिसक रहा है. जबकि जिले के सात में से दो पर अभी भी जदयू का कब्जा है. साहेबपुर कमाल विधान सभा उपचुनाव में राजद ने जदयू से यह सीट झटक ली है.

नीतीश सरकार में बेगूसराय के एक भाजपा एवं एक जदयू विधायक को मंत्री का पद प्राप्त था. नीतीश कुमार के प्रथम शासनकाल में बलिया के जदयू विधायक जमशेद अशरफ एवं भाजपा के नगर विधायक डॉ. भोला सिंह मंत्री थे. जमशेद अशरफ ने मंत्रीपद से त्यागपत्र दे दिया था और डॉ. भोला सिंह नवादा से सांसद निर्वाचित हुए. जिससे मंत्रिमंडल में बेगूसराय का प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया. लेकिन नीतीश कुमार ने दूसरे चरण के शासनकाल में साहेबपुरकमाल की जदयू विधायिका परवीन अमानुल्लाह को मंत्रिमंडल में शामिल कर बेगूसराय को पुनः महत्व दिया. लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले परवीन अमानुल्लाह ने जदयू की सदस्यता एवं मंत्रिपद से त्यागपत्र देकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गईं. तभी से मंत्रिमंडल में बेगूसराय का प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया. वर्तमान में जिले के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जदयू विधायक नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह कर रहे हैं जबकि चेरियाबरियारपुर विधानसभा का मंजू वर्मा. इसके साथ ही बेगूसराय के रूठत राय विधायक हैं.

गठबंधन टूटने के बाद जदयू को भरोसा था कि नीतीश कुमार जब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो बेगूसराय को मंत्रीमंडल में अवश्य स्थान दिया जाएगा. नीतीश कुमार तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए. जीतन राम मांझी ने तो बेगूसराय के जदयू के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की उम्मीद पर तुषारापात ही कर दिया. पहली बार हुआ है कि जीतन राम मांझी ने अपने मंत्रिमंडल में बेगूसराय को स्थान न देकर न सिर्फ जदयू बल्कि जिले की जनता का उपहास किया है. अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव है. जदयू के घटते जनाधार पर इस उपहास का दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है.

यों भी जिले में जदयू का खस्ताहाल है जिसका पर्दाफाश लोकसभा चुनाव में हो चुका है. लोकसभा चुनाव में जदयू-भाकपा का गठबंधन था और बेगूसराय में इस गठबंधन को माकपा का भी समर्थन प्राप्त था. फिर भी गठबंधन के भाकपा प्रत्याशी राजेन्द्र प्रसाद सिंह को जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में से एक में भी बढ़त नहीं मिल पाई. जबकि नीतीश कुमार ने खुद जिले के कई विधान सभा क्षेत्रों में सघन चुनाव प्रचार अभियान चलाया और कई जनसभाओं को संबोधित किया. चौंकानेवाली बात तो यह है कि जिले के चर्चित मटिहानी विधायक नरेन्द्र कुमार सिंहउर्फ बोगो सिंह को चुनावी गठबंधन का संयोजक बनाया गया था फिर भी बोगो अपने विधान सभा क्षेत्र में भी प्रत्याशी को लीड नहीं दिला पाए और मात्र 29893 मत ही दिला पाए. जो जदयू के गिरते जनाधार का द्योतक है. गत विस चुनाव में बोगो सिंह भाजपा-जदयू गठबंधन के प्रत्याशी थे. आगामी चुनाव में क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी?

बेगूसराय

लोकसभा चुनाव के साथ ही जिले के साहेबपुरकमाल विधान सभा का उप चुनाव हुआ. यह सीट जदयू की मंत्री परवीन अमानुल्लाह के त्यागपत्र देने से रिक्त हुई थी. जदयू ने इस सीट से निवर्तमान सांसद मोनाजिर हसन की पत्नी शबनम परवीन को प्रत्याशी बनाया था. यहां भी नीतीश कुमार का अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कार्ड काम नहीं आया और परवीन मात्र 21869 मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहीं. चेरियाबरियारपुर की जदयू विधायक मंजू वर्मा भी अपने क्षेत्र में गठबंधन प्रत्याशी को 23232 मत ही दिला पाईं. जिले के सात में से एक भी विधान सभा में जदयू-भाकपा को लीड नहीं मिली, जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए निराशा का संकेत है. ■

बेगूसराय को औद्योगिक राजधानी बनाने की चुनौती

सांसद भोला सिंह के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सर्वाधिक अहम मुद्दा है सिमरिया का राजेन्द्र पुल. राजेन्द्र पुल का डीपीआर बनाते समय रेल मंत्रालय के अभियंताओं में दूरदर्शिता का अभाव रहा जिस ओर आजतक रेलवे एवं प्रतिरक्षा मंत्रालय का ध्यान नहीं गया. पुल के दोनों ओर पटना-मोकामा-कोलकता तथा सोनपुर-बरौनी-कटिहार रेलमार्ग का दोहरीकरण हो चुका है. लेकिन राजेन्द्र पुल पर एकल रेल ट्रैक है. परिणाम यह होता है कि मोकामा-हथिदह एवं बरौनी-सिमरिया स्टेशनों पर ट्रेनों को रोककर बारी-बारी से गुजारना पड़ता है. राष्ट्रीय आपदा के समय क्या हाल होगा, कल्पना की जा सकती है.

सुरेश चौहान/पंकज झा

सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह के बाद बेगूसराय का विकास न सिर्फ ठप है बल्कि उत्तरोतर छीजन की ओर अग्रसर है. सांसद भोला सिंह इसके पीछे बाहरी व्यक्तियों के सांसद होने को एकमात्र कारण मानते रहे हैं. अब वे खुद सांसद निर्वाचित हुए हैं. इसलिए जिले की जनता उनकी ओर हसरत भरी निगाहों से देख रही है कि अब बेगूसराय का विकास ट्रैक पर आएगा. भोला सिंह भाजपा के सांसद हैं और केन्द्र में भाजपा की सरकार बनी है. इसलिए बेगूसराय को बिहार की औद्योगिक राजधानी बनने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा मानना है जिलेवासियों का. बेगूसराय को समृद्ध औद्योगिक क्षेत्र बनाने के श्रीबाबू के सपनों को मूर्त रूप देने का भार आ गया है सांसद भोला सिंह के कंधों पर. वक्त गवाह बनेगा कि सांसद भोला सिंह को व्यापक जनहित के इस पुनीत कार्य में कितनी सफलताएं मिल पाती हैं.

सांसद भोला सिंह के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सर्वाधिक अहम मुद्दा है सिमरिया का राजेन्द्र पुल. राजेन्द्र पुल का डीपीआर बनाते समय रेल मंत्रालय के अभियंताओं में दूरदर्शिता का अभाव रहा जिस ओर आजतक रेलवे एवं प्रतिरक्षा मंत्रालय का ध्यान नहीं गया. पुल के दोनों ओर पटना-मोकामा-कोलकता तथा सोनपुर-बरौनी-कटिहार रेलमार्ग का दोहरीकरण हो चुका है. लेकिन राजेन्द्र पुल पर एकल रेल ट्रैक है. परिणाम यह होता है कि मोकामा-हथिदह एवं बरौनी-सिमरिया स्टेशनों पर ट्रेनों को रोककर बारी-बारी से गुजारना पड़ता है. राष्ट्रीय आपदा के समय क्या हाल होगा, कल्पना की जा सकती है. सांसद भोला सिंह की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी इस समस्या के समाधान के लिए राजेन्द्र पुल पर रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण कराने की दिशा में पहल करें. गरहरा रेलवे यार्ड की 2200 एकड़ परती जमीन अपने उद्धार की बाट जोह रही है. बिहार के कई रेलमंत्री हुए लेकिन क्षेत्रवाद से ग्रसित लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार एवं राम विलास पासवान रेलवे से संबंधित सभी बड़ी विकास योजनाओं को अपने-अपने क्षेत्र ले गए और गरहरा उपेक्षित रहा. गन्ना किसानों के हित में अंग्रेजी हुकूमत ने बरौनी से हसनपुर चीनी मील तक रेल ट्रैक निर्माण कराने हेतु सर्वे कराया था. बाद में रेलमंत्री ललित नारायण मिश्र ने इसे आगे बढ़ाया. लेकिन बाद में इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई. बरौनी जंक्शन एवं बेगूसराय रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन का दर्जा देने की घोषणा फाइलों में सिमट कर रह गई. उम्मीद जगी है कि भोला सिंह इस दिशा में ठोस पहल करेंगे.

भोला सिंह के लिए दूसरी अहम चुनौती है बंद पड़े बरौनी खाद कारखाना को फिर से चालू कराना. यद्यपि यह आसान नहीं है लेकिन सांसद भोला सिंह पर चुनावी वादे को पूरा कराने के लिए जिलेवासियों का दबाव बना रहेगा. इसी प्रकार सांसद के चुनावी वादों में शुमार है बरौनी रिफाइनरी की शोधन क्षमता को बढ़ाकर 12 एमएमटीपीए कराना. इसके साथ ही बरौनी रिफाइनरी के स्थापना काल से ही लम्बित पेट्रो-रसायन कारखाना की स्थापना कराना जिले का प्रमुख मुद्दा है. अन्य ज्वलन्त मुद्दा है- काबर झील, पक्षी बिहार नमक सत्याग्रह स्थल एवं बौद्ध स्तूप का विकास. पक्षी एवं पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. सलीम ने काबर झील को एशिया का सबसे अच्छा ताजा जलस्त्रोत का झील बताते हुए पक्षी बिहार के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया था. लेकिन डॉ. सलीम के सपनों का काबर झील एवं पक्षी बिहार का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है. झील की जमीन का अतिक्रमण एवं बौद्ध स्तूप पर अवैध कब्जा होता जा रहा है. स्थानीय किसानों की मांग है कि झील को विकसित कर पक्षी बिहार बनाया जाए. शेष जमीन पर मालिकाना हक दिया जाए तथा बौद्ध स्तूप को बौद्ध सर्किट से जोड़कर इसका विकास किया जाए. मुद्दे और भी हैं. बरौनी औद्योगिक क्षेत्र वीरान होता जा रहा है. बरौनी डेयरी में दुग्ध उत्पादक किसानों का शोषण जारी है. एक अन्य अहम मुद्दा है, उलाव हवाई हड्डे का विकास. अंग्रेज शासकों द्वारा अस्तित्व में लाया गया उलाव हवाई अड्डा जानवरों का चारागाह बनकर रह गया है.

हवाई अड्डे की जमीन का अतिक्रमण जारी है नियमों की अवहेलना करते हुए इसके पास पेट्रोल पम्प एवं मकान का निर्माण हो चुका है. बरौनी रिफाइनरी के कारण यहां मिनी भारत निवास करता है और बरौनी-बेगूसराय महत्वपूर्ण व्यवसायिक केन्द्र है. यदि हवाई अड्डे को विकसित कर इसे वायुमार्ग से जोड़ दिया जाता है तो नागरिकों को सुविधाओं के साथ ही सरकार को राजस्व प्राप्त होगा. समय बताएगा कि सांसद भोला सिंह को उपयुक्त चुनौतियों से निपटने में कितनी सफलताएं मिल पाती हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

सीएम का पुतला फूंका

बिजली की समस्या को लेकर प्रदेश भाजपा के आह्वान पर ठाकुरगंज में कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री व बिजली मंत्री जीतन राम मांझी का पुतला फूंका. कार्यक्रम का नेतृत्व करने में जुटे भाजपा ठाकुरगंज नगर अध्यक्ष नरेश शाह एवं जिला महामंत्री अमित सिन्हा ने अपने सम्बोधन में कहा कि किशनगंज जिला एवं पूरे प्रदेश में विद्युत की अनियमितता, मीटर रीडिंग में हेरा-फेरी, समय पर बिल नहीं मिलना जैसी समस्याओं से उपभोक्ता परेशान हैं. पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक माह के अंदर विद्युत समस्याओं में सुधार नहीं आए तो पूरे प्रदेश में भाजपा चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए विवश होगी. पुतला फूंको अभियान में शामिल भाजपा समर्थकों में मुखिया मोहन सिंह नगर मंत्री संतोष पासवान महिला मोर्चा नेत्री द्रौपदी देवी के साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रीतेश यादव, नीरज झा, संजीव झा, रोशन साह, मनीष ऋषिदेव, समेत दर्जनों भाजपा एवं विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता मौजूद थे.

-कुलभूषण सिंह

घर-घर परमात्मा अवतरण संदेश का आयोजन

प्रजापित ब्रम्ह कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय की प्रथम मुख्य केन्द्रीय शासिका यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती के 49 वीं पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत घर-घर परमात्मा अवतरण संदेश' का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम के तहत पतौरा में संचालित संस्था के ईश्वरीय गीता पाठशाला द्वारा नगर के कई मोहल्लों एवं पश्चिमी भाग के दर्जनों गांव में घर-घर जाकर परमात्मा के अवतरण की जानकारी दी गई. पर्चे एवं संवादों के तहत अनेक जानकारियां लोगों को दी गईं. टीम में शामिल पन्द्रह ओम शांति के भाई-बहनों ने परमात्मा के दिव्य गुणों एवं उनके संदेश में व्यसनमुक्त होना तामसी भोजन त्यागना तथा पांच विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार को छोड़ना आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया. मौके पर बीके सीता बहन, बीके शम्भू, बीके अन्नू, बीके विभा, बीके गायत्री, उर्मिला, राधिका, हिमांशू, त्रियांश, नीलम, शिवपूजन, कृष्णा, रंजन, रौशनी, सुमन एवं मोहन उपस्थित थे. शहर के मिस्कॉट, बेलीसराय, रघुनाथपुर, तुरकौलिया के बालगंगा, तुरकौलिया, जयसिंहपुर, शंकर सरैया, बैरिया, गायघाट, मठलोहियार, गोविन्दापुर, अरेराज, चण्डी स्थान, लौरिया, भेलवा, गोवर्धना एवं सिकटिया के सभी गांवों में परमात्मा के संदेश पहुंचाए गए.

-इन्तेजारुल हक

सीएम व डीएम का पुतला जलाया

मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय के छात्रों ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी व पूर्वी चम्पारण के जिलाधिकारी अभय कुमार सिंह का पूतला जलाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की. छात्रों का आरोप था कि उनकी समस्याएं नही सुनी जाती है. मौके पर संजीव कुमार, छोटन कुमार जायसवाल, संजय कुमार, किशोर कुमार, पारस नाथ प्रसाद, मुकेश कुमार, मयंक आनन्द, सुनिल कुमार, राजन कुमार, राहूल कुमार, वरूण कुमार, राकेश कुमार, रजनीश कुमार समेत बड़ी संख्या में छात्रों ने आज पुतला जलाया और शासन व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी की. छात्रों ने बताया कि शिक्षकों की यहां भारी कमी है जिस कारण कक्षायें संचालित नही होती. दस जुलाई से थर्ड ईयर व आठ जुलाई से सेकेण्ड इयर की परीक्षा है और लाइब्रेरी में किताबे नही है. यहां कॉलेज प्रशासन की लापरवाही भी चरम पर है और कोई ठोस कार्रवाई नही उठायी जाती हैं.

-इन्तेजारूल हक

सड़क-बिजली को लेकर हंगामा

चतरा से गया (बिहार) को जाने का एकमात्र सड़क है. जिससे होकर इन दोनों राज्यों के हजारो वाहन का आवागमन पिछले दो वर्षों से बाधित है. वर्ष 2012 में इस सड़क का निविदा हुआ और संवदेका रामजनम सिह को सड़क का काम मिला विगत तीन वर्षो से इस पर रहने वाले लोगों का जीना एवं चलना इस सड़क पर दुभर हो गया है. बताते चले कि वगित तीन वर्षो से सड़क के किनारे वाले ग्रामीणों को धूल , कीचड़, और गड्ढ़ों से होकर गुजरना पड़ा रहा है. सड़क किनारे कि जनता अब तक दर्जनों बार संवेदक के प्रति विरोध जता चुकी है तथा सड़क जाम किया गया है. इस सड़क के किनारे वाले शहर जोरी, हंटरगंज, गोसाईडीह, आदि है दर्जनों बार सड़क जाम करने के बाद तथा जिला प्रशासन के पहल के बाबजूद तीन किलोमीटर सड़क तीन वर्षों में बन पाया. संवेदक के प्रशासन द्वारा कहे जाने के बाद भी इसपर कोई असर नही हुआ हाल में जोरी बाजार के लोगों द्वारा बारह धंटा सड़क जाम किया गया . जिसमें एनएच 99 के सहायक अभियंता के साथ ग्रामीणों ने धक्का -मुक्की किया चतरा अनुमण्डल पदाधिकारी सतीश चन्द्रा के पहल के बाद जाम को हटाया गया तथा तत्काल सड़क के रूके हुए काम को पूरा करने के आश्वासन के बाद सड़क से जाम हटा दिया गया . इस मौके पर चतरा सिविल सर्जन सत्येन्द्र कुमार सिंह, हंटरगंज प्रखण्ड विकास पदाधिकारी केवलकृष्ण अग्रवाल, भैरो सिंह, मिस्टर मिंया, राजेन्द्र सिंह, विनोद चौरसिया आदि दर्जनों गणमन्य के बीच वार्ता किया गया .

-अमरेन्द्र प्रताप

रिफाइनरी में ब्वॉयलर का उद्घाटन

रिफाइनरीज के निदेशक राजा कुमार घोष ने बरौनी रिफाइनरी में ब्वॉयलर-6 एवं टीजी-4 का उद्घाटन किया. उद्घाटन के साथ ही बरौनी रिफाइनरी को निर्बाधित रूप से बिजली की आपूर्ति सुश्चित हो गई. निदेशक ने श्रमिक विकास परिषद एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बरौनी रिफाइनरी के विस्तारीकरण एवं गोल्डेन जुबली वर्ष में सामाजिक दायित्वों के निर्वहन पर चर्चा की. घोष ने विश्व पर्यावरण दिवस पर उद्घाटन वृक्षारोपण भी किया. जीएम आर. एस. यादव ने बरौनी कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई. इस अवसर पर बरौनी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक एस.के.झा, जीएम एनकेदास, एडी प्रसाद, संजय सेन, सीसीओ आर.के. सिंह, आर. के. झा, एल.एस. खरगोंकर, यूनियन के परवेन्द्र कुमार एवं नवल किशोर सिंह, ऑफिसर्स एसोसियेशन के आशीष आनन्द सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे.

-सुरेश चौहान

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

गया नगर निगम

हटाओ, फंसाओ और बचाओ में बीता दो साल

सुनील सौरभ

अपनी धार्मिक गरिमा के लिए पूरी दुनिया में विख्यात गया में नागरिकों को बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले गया नगर निगम का दो वर्ष मेयर, डिप्टी मेयर तथा वार्ड पार्षदों के आपसी झगड़े में ही बीत गया. मेयर विभा देवी तथा डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव के गुट के बीच बंटे वार्ड पार्षद एक दूसरे को हटाने, फंसाने और बचाने की ही मुहिम में लगे रहे. इसका खामियाजा गया शहर को भुगतना पड़ा. इन दो वर्षों में विकास के सारे पहलू गौण रहे. एक समय तो ऐसा भी आया कि गया नगर निगम के तीनों शीर्ष पद खाली पड़े रहे. एक आपराधिक मामले में मेयर विभा देवी फरार रहीं. इसी बीच 31 दिसम्बर 2013 को नगर आयुक्त रिटायर हो गए और इसके बाद 6 जनवरी 2014 को डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव पटना के एक होटल में नाबालिग लड़कियों से सामूहिक बलात्कार के मामले में रंगे हाथ पकड़े गए और बेउर जेल चले गए. नतीजा हुआ कि तीनों शीर्ष पद करीब दो-ढाई महीनों तक खाली रहे. बाद में नगर विकास विभाग ने गया जिला प्रशासन में पदस्थापित एडीएम रामविलास पासवान को नगर आयुक्त का अतिरिक्त पदभार ग्रहण कराया. इसके बाद मेयर विभा देवी को भी जमानत मिल गई. तब जा कर गया नगर निगम कुछ रास्ते पर आया.

लेकिन नाबालिग लड़कियों से सामूहिक बलात्कार में डिप्टी मेयर के पकड़े जाने के बाद गया नगर की बदनामी पर विरोधी गुट मोहन श्रीवास्तव को डिप्टी मेयर से हटाने की मुहीम में लग गया. मोहन श्रीवास्तव गुट भी सक्रिय होकर अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में खड़े हो गया, लेकिन असफलता हाथ लगी. अन्तत: काफी मशक्कत के बाद गया नगर निगम के चर्चित डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव को बहुमत से हटा दिया गया. नाबालिग लड़की से पटना के होटल में सामूहिक बलात्कार के मामले में पिछले 6 महीने से दो वार्ड पार्षद और एक पार्षद पति के साथ बेउर जेल में बंद गया नगर निगम के डिप्ट मेयर मोहन श्रीवास्तव को पद से हटाने की मांग वार्ड पार्षदों और राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा की जा रही थी. लेकिन जब जिला पदाधिकारी ने इस मांग की अनदेखी कर दी तो डिप्टी मेयर विरोधी पार्षदों ने गया नगर निगम के चुनाव के दो वर्ष पूरे होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 22 के मुकाबले 27 मत लाकर मोहन श्रीवास्तव को पदच्युत कर दिया. डिप्टी मेयर के हटाए जाने को गया की आम जनता सही ठहरा रही है. लेकिन इसमें बड़ी बात यह रही कि गंभीर मामले में बेउर जेल में बंद रहने के बाद भी गया नगर निगम के 22 वार्ड पार्षदों ने मोहन का साथ दिया. शहरवासी इससे भौंचक हैं. यह बात बताते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता अखौरी निरंजन प्रसाद कहते हैं कि ऐसे वार्ड पार्षदों को भाजपा महिला मोर्चा की ओर से बेनकाब करने का अभियान चलाया जाएगा. हालांकि मोहन श्रीवास्तव समर्थक वार्ड पार्षद मेयर विभा देवी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं. लेकिन अभी तक इसपर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है. डिप्टी मेयर को हटाने की मुहीम में लगे वार्ड 36 के पार्षद चितरंजन प्रसाद वर्मा डिप्ट मेयर पद के प्रमुख दावेदार हैं. उनका कहना है कि गया नगर निगम के रावण को बहुत मुश्किल से मारा गया है. अब नगर निगम में विकास की बातें ही होंगी. उन्होंने कहा कि सारा शहर जानता है कि मोहन श्रीवास्तव वार्ड पार्षदों को या किसी भी मतलब के व्यक्ति को अपने कब्जे में कैसे लेता है. इसी का परिणाम है कि वह जेल में है. वार्ड पार्षद लालजी प्रसाद कहते हैं कि डिप्ट मेयर मोहन श्रीवास्तव के हटते ही गया नगर निगम से कलंक का टीका हटा है. अब शहर में विकास की बातें होंगी. गलत आदमी का साथ देने वाले वार्ड पार्षदों का चेहरा शहरवासियों के द्वारा बेनकाब किया जाएगा. लेकिन सवाल यह है कि शहर के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण दो वर्ष खो देने के बाद अब नगर निगम शहर के विकास में कितना योगदान कर पाएगा, इसका जवाब कोई वार्ड पार्षद नहीं दे पा रहा है. आखिर सवाल है वार्ड पार्षद के गुटबाजी का खामियाजा शहर क्यों भुगते ?

गया

दूरस्थ शिक्षा ने बदली मगध विश्वविद्यालय की तस्वीर

जब तक मगध विश्वविद्यालय तथा इसके अंगीभूत कॉलेजों में विद्वान-कड़े प्रशासनिक क्षमता वाले शिक्षक-प्राचार्य, कुलपति रहे तब तक मगध विश्वविद्यालय की गरिमा चरम पर रही. धीरे-धीरे वैसे शिक्षक-प्राचार्य रिटायर होते चले गए और बिहार की बदली राजनीतिक व्यवस्था ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर प्रभाव डाला, जिससे मगध विष्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास फर्जी डिग्री तथा अन्य तरह के अनियमितताओं के कारण धूल धुसरित हो गई. लेकिन इन सब से इतर 2008 में मगध विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा विभाग की शुरुआत हुई. मनोविज्ञान विभाग के भवन में दूरस्थ शिक्षा विभाग शुरू होकर आज अपने अलग विशाल भवन में मगध विश्वविद्यालय की खोई हुई गरिमा को वापस लाने में लगा है. मगध विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों की बात तो छोड़ दीजिए, परिसर में जो भी चीजें आपको अच्छी नजर आएंगी उसमें दूरस्थ शिक्षा का योगदान दिखाई देगा. मगध विश्वविद्यालय के विशाल परिसर में दूरस्थ शिक्षा विभाग 2010 में अपने अलग भवन में आ गया. इस परिसर में घुसते ही यहां की शैक्षणिक व्यवस्था तथा अन्य गुणवर्त्तापूर्ण कार्य देखने से ही पता चल जाता है कि यह एक महत्त्वपूर्ण विभाग है. दूरस्थ शिक्षा परिसर में बने वातानुकूलित डॉ. राधाकृष्णन सभागार में दो अन्तरराष्ट्रीय तथा 7 राष्ट्रीय सेमिनार हो चुके हैं. जिनमें देश-विदेश के जाने-माने विद्वानों का व्याख्यान हो चुका है. यहां म्यांमार के प्रधानमंत्री, भारतीय सेना के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकाडमी के चीफ तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों की कई प्रमुख हस्तियों का आगमन हो चुका है. बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी मगध विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा विभाग में पहुंच कर यहां के कार्यों तथा पठन-पाठन की व्यवस्था की सराहना कर चुके हैं. फिलहाल यहाँ 5 विषयों में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था है. जिनमें बी.एड, लाइब्रेरी साइंस में स्नातक तथा स्नातकोत्तर के साथ एम.ए. इन एजुकेशन की भी पढ़ाई होती है. इन सब के अलावा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं को यूजीसी प्रोग्राम के तहत कोचिंग की नि:शुल्क व्यवस्था है. दूरस्थ शिक्षा के निदेषक डॉ. इजराइल खां बताते हैं कि वर्तमान कुलपति डॉ. इश्तियाक के दिशा निर्देश में अन्य विषयों की पढ़ाई भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था हो रही है. इसके लिए कुलपति की ओर से सार्थक पहल की गई है. मगध विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा से मगध के छात्र छात्राओं के अलावा राज्य तथा राज्य के बाहर के लोगों को भी लाभ मिल रहा है. आने वाले समय में मगध विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा विभाग पूरे राज्य में मील का पत्थर साबित होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है.

– सुनील सौरभ

लाभ लेने के बाद वैश्यों को भुला देते हैं राजनीतिक दल

पृष्ठ 17 का शेष

चुनाव में वैश्य समुदाय के कांग्रेस उम्मीदवार समीर महासेठ को सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में जबरदस्त वोट मिला था. वह राजद उम्मीदवार एवं तत्कालीन निवर्तमान सांसद सीताराम यादव को तीसरे स्थान पर ढकेल, मुख्य मुकाबले में रहे थे. जबकि, उस चुनाव में कांग्रेस अलग और राजद-लोजपा ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा था. लिहाजा, सीताराम के वोट में लोजपा का भी मत शामिल था. वहीं, कांग्रेस के आधार मत एवं वैश्यों के वोट लेकर समीर सब पर भारी पड़े थे. उनका इस बार लालू प्रसाद ने अपने स्वजातीय उम्मीदवार सीताराम यादव को उम्मीदवार बनाने की नियत से पत्ता साफ कर दिया. यह सीट गठबंधन के तहत कांग्रेस को लेने ही नहीं दी. नतीजा सब जानते हैं कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री उपेन्द्र कुषवाहा की पार्टी रालोसपा के टिकट पर चुनावी अखाड़े में उतरे उम्मीदवार रामकुमार शर्मा उर्फ रामकुमार कुशवाहा ने भारी मतों के अंतर लालू के प्रत्याशी को पटखनी दे दी. सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से चर्चित व्यवसायी कृष्णा प्रसाद टिकट के ख्वाहिशमंद थे. काफी जद्दोजहद के बाद यह सीट उपेन्द्र कुशवाहा ने रामकुमार कुशवाहा को सौंप दी.

आकंडे बताते हैं कि प्रदेश में वैश्यों की आबादी 23 फीसदी है. लगभग 56 उपजातियों में बंटा यह समाज बिहार की कारोबारी दुनिया में अपना दबदबा बनाए हुए है. अपनी लगन व मेहनत से इस समाज ने यह साबित किया कि संसाधन व सरकारी सुविधा के अभाव में भी कैसे व्यापार का ग्राफ बढ़ाया जा सकता है और राज्य सरकार को राजस्व देकर उसे आर्थिक तौर पर मजबूत किया जा सकता है. अपने पेशे के प्रति बेहद ईमानदार यह समाज सालों से अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी की गुहार लगाता रहा है पर किसी भी सरकार ने आबादी के हिसाब से इसकी हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया. हां, इतना जरूर हुआ कि उनके वोट ने प्रदेश और देश में कई सरकारों के गठन में अहम भूमिका निभाई. लेकिन जब काम निकल गया तो सभी दलों ने उन्हें भूला दिया. समीर महासेठ 2009 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे पर इस बार इनको टिकट तक नहीं दिया गया.

गंगा बाबू ने भाजपा के लिए क्या नहीं किया और क्या नहीं कर रहे हैं पर जब लोकसभा चुनाव में टिकट देने की बारी आई तो भाजपा के बड़े नेता बगलें झांकते हुए नजर आए. कृष्णा प्रसाद ने बिना मांगे न जाने कितने दलों व नेताओं को सहयोग किया होगा. लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है तो फिर कृष्णा बाबू का चेहरा ही किसी को याद नहीं रहता है. विजेंद्र चौधरी पहले लोजपा और फिर राजद में ठुकराए गए और आखिरकार किसी तरह जदयू का टिकट पाने में सफल रहे. इसी तरह उमाशंकर भगत उर्फ टुनटुन भगत से हर किसी ने मदद ली लेकिन जब चुनावी हिस्से की बात सामने आई तो सभी ने हाथ झटक दिया. वैश्यों के हक की बात हर मंच पर उठाने वाले संजय वर्मा को अभी तक ठिकाना नहीं मिल पाया है. नीतीश कुमार के आश्वासनों के सहारे वैश्यों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं पर देखना है कि इसका असर खत्म होने के बाद वह कौन सी लाइन अख्तियार करते हैं. इसी तरह रणविजय साहू भी हाशिए पर डाल दिए गए हैं. कहने का अर्थ यह है कि वैश्यों के जितने छोटे व बड़े नेता हैं उनको लेकर लगभग हर दलों ने उपेक्षा का ही भाव रखा है. इन नेताओं के मारफत इस समाज के वोट तो हर दल हासिल करते रहे हैं पर जब उनकी खुद की हिस्सेदारी की बात आती है तो हर दल गुम्मी गोली खाकर सो जाते हैं. जानकार बताते हैं कि वैश्यों की इस दुर्गति के लिए खुद वैश्य नेता भी कम जिम्मेदार नहीं हैं. आपसी तालमेल के अभाव में मजबूती से ये नेता समाज के हित की बात सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं. पटना में ऐसा कोई संगठन नहीं है जो पूरे वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करता हो. वैश्य नेता राजनीतिक दलों को रैलियों व चुनावों में तो दिल खोल कर चंदा देते हैं लेकिन अपने लिए एक मजबूत संगठन खड़ा करने और अपना कार्यालय खोलने में हाथ खड़े कर देते हैं. राजनीतिक दल व सियासी नेता वैश्यों की इसी कमजोरी का लाभ उठा रहे हैं. बड़े नेता यह जान गए है कि वैश्य समाज आपसी झगड़े में ही इतना मशगूल है कि इसे अगर कुछ न भी दिया जाए तो कुछ असर नहीं पड़ेगा. इसलिए अगर वैश्यों को सत्ता में अपनी हिस्सेदारी लेनी है तो इसे पहले अपना घर ठीक करना होगा. जब तक एक संयुक्त ताकत के तौर पर यह समाज सरकार पर दबाव नहीं डालेगा तब तक वह वोट बैंक की हैसियत से आगे नहीं बढ़ पाएगा. जिस दिन नेताओं को यह लगेगा कि अब वैश्य एकजुट होकर एकस्वर में अपनी बात रख रहा है तो उसी दिन से सत्ता में उनकी हिस्सेदारी का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE MOULDED FURNITURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY शर्तें लागू।
Contact : 9386595926, 9334115955

नकसीर बचाव और निवारण
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
डॉ विवेक मधुकर एमएस (ईएनटी) देवघर
नकसीर अर्थात नाक से खून आना : ज्यादातर रक्त नाक के सामने से आता है, कभी-कभी नाक के पीछे से भी आता है. सामान्यतः रक्त नाक के एक छिद्र से ही आता है. ताजा खून और खून के थक्के पेट में चले जाने से उल्टियां भी हो सकती हैं. हालांकि ढेर सारा खून देख कर लोग भयभीत हो जाया करते हैं, किन्तु ज्यादातर यह जानलेवा नहीं होता. सही समय पर उपचार होने से सब ठीक हो जाता है. कारण : • बाहरी चोट, मसलन चेहरे पर घूंसे से या दुर्घटना से चोट • बार-बार आदतन उंगली से नाक साफ करना • अत्यधिक ठण्ड या गर्मी से नाक का सूख जाना • धूल या धुएँ से नाक में जलन होना • उच्च रक्तचाप • संक्रमण श्वास नाली का, साइनस का, या जोरदार सर्दी होना • नाक की हड्डी का टेढ़ा होना या हड्डी बढ़ जाना• नाक का ट्यूमर या पॉलिप निवारण : •नाक से खून आने पर सर्वप्रथम शान्ति से बैठ जाएँ और नाक के नरम हिस्से को उँगलियों से दबाएँ. ऐसा 5 से 10 मिनट तक करने से सामान्यतः खून आना बंद हो जाता है. • यदि बर्फ उपलब्ध हो तो नाक के ऊपर बर्फ रखने से खून जल्दी जमेगा और बहना बंद हो जाएगा. •इस दौरान लेटें नहीं, अपितु बैठे रहें। जिससे खून गले और पेट में नहीं जाएगा. •पानी पीने से भी खुश्की में कमी आएगी. •इसके बावजूद यदि खून आना बंद न हो तो तत्काल अपने चिकित्सक से या कान-नाक-गला रोग विशेषज्ञ से सलाह लें. बचाव : •नाक जब ज्यादा सूखी लगे तो वेसलीन या पैराफिन के इस्तेमाल से नकसीर से बचा जा सकता है. • अधिक पानी पीने से त्वचा और नाक, मुंह, गला सूखने से बचा जा सकता है. •गर्म वातावरण में ज्यादा देर न रहें.•ठंडी शुष्क हवाएँ चल रही हों तो चेहरा और नाक अच्छी तरह से ढँक कर रखें. धूल, धुएँ से बचें. •यदि आप उच्च रक्तचाप के मरीज हैं तो नियमित जाँच और सम्यक इलाज करवाएं.
URSLIV Tab. Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Rabinok-DSR Entenic Coated Rabeprazole & Domeridone Sustained Release Cap.
Nokcef-O Tab. Cefixime 200 mg + Ofloxacin 200 mg
Liv-guard Syp. Herbal Scientic formula to manage Liver Disorder
Asrfen Tab. Diclofeanc Sodium 50 mg. serratiopeptidase 10 mg
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd. A Division of AriskonPharma
प्रस्तुति : चित्रा भारती

Mob. : 9386745004, 9204791696
www.iiher.org, Email : anilsulabh6@gmail.com
INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH
Health Institute Rd, Beur (Near Central Jail), Patna -2.
(Recongnised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)
AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

POST GRADUATE COURSES :

Name of Courses		Eligibility	Duration
MPT	Master of Physiotherapy	BPT	2yrs.
MOT	Master of Occupational Therapy	BOT	2yrs.
DEGREE COURSES			
BPT	Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BOT	Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BPO	Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc	4yrs.+6 Months of Internship
BASLP	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc	3yrs.+1 year of Internship
BMLT	Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc	3yr.+6 Months of Internship
BMRIT	Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc	3yrs.+6 Months of Internship
B.Ophth.	Bachelor of Ophthalmology	I.Sc	4yr.+6 Months of Internship
B.Ed.	(Special Education)	Graduate	1yr.
1 YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT			
DIPLOMA COURSES :			
DPT	Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)	3yrs.+6 Month of Internship
D-X-Ray	Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DMLT	Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DECG	Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)	2yr.
DOTA	Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DHM	Diploma In Hospital Management	Graduate	1yr.
CMD	Certificate in Medical Derssing	Matirc with Science & English	1yr.

ADMISSION OPEN
Form & Prospectus - Can be obtained from the office against a payment of Rs. 500/-. only by cash. Send a DD of Rs. 550/- only in the favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna, for postal delivery.
डा. अनिल सुलभ निदेशक प्रमुख

ऑरकेस्ट्रा पार्टियों पर मेहरबान क्यों है प्रशासन

इन्तेजारुल हक

संगीत कार्यक्रमों या मनोरंजन के लिए ऑरकेस्ट्रा पार्टियों के आयोजन की बात तक तो ठीक है लेकिन इनकी आड़ में देह-व्यापार कराने वाले ऑरकेस्ट्रा संचालकों पर प्रशासन मेहरबान क्यों है, यह बात समझ से परे है. आखिर इनके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई क्यों नहीं होती और इनके चंगुल में फंसी लड़कियों को छुड़ाने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? हाल के दिनों में पूर्वी चम्पारण जिले के छौड़ादानो थाना क्षेत्र के बहुअरवा गांव स्थित रेलवे ढाला के समीप एक झोपड़ी में ऑरकेस्ट्रा नर्तकी की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद पूरे चम्पारण व इसके आस-पास के क्षेत्रों में अनेक तरह की चर्चाएं होने लगी हैं और प्रशासन की खामोशी पर सवाल उठने लगा है तथा जानकार उनकी भूमिका संदिग्ध बताने लगे हैं. आखिर देह-व्यापर का धंधा भी मानव तस्करी में आता है और इस को सह देने वालों पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है. जानकार बताते है कि पूरे चम्पारण में आरकेस्ट्रा के नाम पर एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो नेपाल से लेकर भारतीय महानगरों कोलकाता, मुम्बई व अन्य इलाकों से कम उम्र की लड़कियों को हिरोइन बनाने, उनसे शादी करने व उन्हें बड़ा कलाकार बनाने के साथ-साथ अच्छी कमाई कराने प्रलोभन देकर उन्हें यहां लाता है और पहले उनका शारीरिक शोषण करता है और फिर ऑरकेस्ट्रा संचालकों को उन्हें सौंप देता है. जहां इसके एवज में इसे मोटी राशि मिलती है. ऑरकेस्ट्रा में उक्त लड़कियों से नाच-गाने के अलावा लेकर देह-व्यापार तक के काम लिए जाते हैं जो मानव संस्कृति के खिलाफ तो हैं ही साथ ही सभ्य समाज के माथे पर एक काला धब्बा भी है. जिससे मानवता भी शर्मसार हो जाती है. एक आंकड़े के मुताबिक अभी पूर्वी व पश्चिमी चम्पारण के विभिन्न इलाकों में संचालित ऑरकेस्ट्रा पार्टियों में बंगाल की दस दर्जन से अधिक लड़कियां काम कर रही हैं और अनेक गंभीर चुनौतियों से जूझ रही हैं. इसका विरोध करने वाली लड़कियों के साथ मारपीट भी की जाती है और तरह-तरह की यातनाएं भी दी जाती है.

जानकार बताते हैं कि पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी, तुरकौलिया, छौड़ादानो, सगौली, बनकटवा, घोड़ासहन, पिपराकोठी, रक्सौल, रामगढ़वा, हरसिद्धि, चिरैया, बनकटवा, चकिया, पिपराकोठी आदि क्षेत्रों में ऑरकेस्ट्रा संचालकों का सब से अधिक जाल बिछा हुआ है और इसकी आड़ में खुले-आम देह-व्यापार का धंधा चल रहा है. बीते दिनों पूर्वी चम्पारण जिले के छौड़ादानो थाना क्षेत्र के बहुअरवा गांव स्थित रेलवे ढाला के समीप एक झोपड़ी से ऑरकेस्ट्रा नर्तकी की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत इसकी गवाह है. इसे लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में बंगाल व बिहार की पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में बरामद लड़कियों द्वारा दिए गए बयान इसका ज्वलन्त प्रमाण हैं. पुलिस को दिए बयान में एक लड़की ने रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं का खुलासा करते हुए बताया था कि उन्हें कई पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था. यहां बतातें चलें कि हाल के महीनों में भी पूर्वी चम्पारण जिले के छौड़ादानो, आदापुर, तुरकौलिया आदि क्षेत्रों में प्रयास नामक संस्था के सहयोग हुई छापेमारी में बरामद हुई लड़कियों से पूछ-ताछ के बाद अनेक जानकारियां हासिल हुई हैं और ऑरकेस्ट्रा संचालकों की काली करतूत का खुलासा हुआ है. वहीं दूसरी तरफ जानकार बताते हैं कि यहां सब से अधिक लड़कियां बंगाल से लाई जाती हैं और उन्हें गुप्त तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में रखा जाता है तथा जरूरत के अनुसार उनका इस्तेमाल किया जाता है. इन्हें चंद पैसे के लिए जिस्म के सौदागरों के हाथों इन्हें सौंप दिया जाता है. इसके अलावा मोतिहारी शहर के ज्ञान बाबू चौक, छतौनी कॉलोनी, बेली सराय आदि मोहल्लों में भी ऑरकेस्ट्रा की आड़ में युवतियों से देह-व्यापार कराने की खबरें समय-समय पर मिलती रही हैं और स्थानीय अखबारों में खबरें छपती रही हैं. इसी तरह के हालात पश्चिमी चम्पारण जिले के भी बताए जाते हैं.

पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी, तुरकौलिया, छौड़ादानो, सगौली, बनकटवा, घोड़ासहन, पिपराकोठी, रक्सौल, रामगढ़वा, हरसिद्धि, चिरैया, बनकटवा, चकिया, पिपराकोठी आदि क्षेत्रों में ऑरकेस्ट्रा संचालकों का सब से अधिक जाल बिछा हुआ है और इसकी आड़ में खुले-आम देह-व्यापार का धंधा चल रहा है. बीते दिनों पूर्वी चम्पारण जिले के छौड़ादानो थाना क्षेत्र के बहुअरवा गांव स्थित रेलवे ढाला के समीप एक झोपड़ी से ऑरकेस्ट्रा नर्तकी की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत इसकी गवाह है.

शहर से लेकर गांव तक ऑरकेस्ट्रा पार्टियों का जाल बिछा हुआ है और इसकी आड़ में देह-व्यापार का धंधा चलता खूब चलता है. कई बार स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया गया और पुलिस से शिकायतें भी दर्ज की गईं किन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस खेल में यहां की पुलिस की भी भूमिका जानकार संदिग्ध बताते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक ऑरकेस्ट्रा संचालकों से पुलिस पैसे लेती है और यही कारण है कि इन पर कार्रवाई करना मुनासीब नहीं समझती है. जानकार यह भी बताते हैं कि इस कारोबार को आगे बढ़ाने में कई सफेदपोश भी शामिल हैं और अपनी जरूरत के अनुसार समय-समय पर इसका इस्तेमाल करते हैं. अगर समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में यहां स्थिति काफी भयवाह हो जाएगी. इन दिनों सबों की नजर पूर्वी चम्पारण के जिलाधिकारी अभय कुमार सिंह व पुलिस कप्तान विनय कुमार पर टिकी हुई है.■

feedback@chauthiduniya.com

चम्पारण

पंचायतों में हुआ करोड़ों का घोटाला

शिकायत करने वाले पर कराया जाता है झुठा मुकदमा

महज आठ हजार की आबादी वाले इस पंचायत के मुखिया राहुल कुमार सिंह ने अपने आठ वर्शों के कार्यकाल में डेढ़ करोड़ से ज्यादा की विकास राशी में अनियमितता की है.

पूर्वी चम्पारण जिले के पंचायतों में इन दिनों भ्रश्टाचार की जड़ काफी मजबूत हो गयी है और सभी विभागीय नियमों व आदेशों की धज्जिया उड़ाते हुए करोड़ो का घोटाला किया जा रहा है. यहां भ्रष्टाचार की जड़े इतनी मजबुत हो गई हैं कि खुलेआम सरकारी आदेशों की कैसे धज्जियां उड़ायी जा रही है और इसका विरोध करने वाले लोगों को झुठे मुकमों में फंसाया जा रहा है. इसका ज्वलन्त नमुना अरेराज अनुमण्डल के हरसिद्धी प्रखण्ड का कनछेदवा व बंजरिया प्रखण्ड का रोहिनिया पंचायत है. हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन पंचायतों में गड़बड़ी करने वाले मुखियों पर तो कार्रवाई नही होती, लेकिन शिकायत करने वाले को झुठे मुकदमों में इस कदर फंसा दिया जाता है कि दूसरा कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ किसी अधिकारी के यहां शिकायत करने की हिम्मत न जुटा सके. कनछेदवा पंचायत के उपमुखिया व खाद व्यवसायी ब्रजकिशोर सिंह ने जब सूचना के अधिकार के तहत योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली और एक बड़े घोटाला का खुलासा किया तो उन्हें आधा दर्जन से अधिक झुठे मुकदमों में वहां के मुखिया राहुल कुमार सिंह ने फंसा दिया.

महज आठ हजार की आबादी वाले इस पंचायत के मुखिया राहुल कुमार सिंह ने अपने आठ वर्षों के कार्यकाल में डेढ़ करोड़ से ज्यादा की विकास राशि में अनियमितता की है. खाद व्यवासायी व उपमुखिया बृजकिशोर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, वित्तीय वर्ष 2006 से 2011 तक यानी पांच वर्षों के विकास योजनाओं मनरेगा, बीआरजीएफ, हरियाली, सोलर आदि योजनाओं के मद में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और बगैर काम कराये लाखों रूपये का उठाव कर लिया गया है. इस गड़बड़ी की शिकायत डीएम से लेकर विजिलेंस तक उपमुखिया ने की तो मुखिया ने अपने समर्थकों की बदौलत दलित एक्ट के झुठे मुकदमा में फंसा

दिया. हालाकि पुलिस ने जांच में मामले को गलत करार दिया. इसकी शिकायत वर्ष 2013 में पूर्वी चम्पारण पूर्व जिलाधिकारी विनय कुमार को मिली तो उन्होंने गंभीरता से लेते हुए अक्टूबर में अरेराज के अनुमण्डल पदाधिकारी को जांच का आदेश दिया. एसडीओ के आदेश पर नियुक्त विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी रईसुद्दीन खां ने जब इस पंचायत में हुए घोटाले की जांच की तो सभी आरोप सही पाया और अनेक गड़बड़ घोटालों का खुलासा किया.

जांच प्रतिवेदन में कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री खां ने 35 लाख रुपये की विकास राशि वाले बीआरजीएफ व मनरेगा के नौ योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने व लाखों रुपये का बंदरबाट होने का उल्लेख किया और 20 अक्टूबर 2013 को एसडीओ को अपनी रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट में मुखिया, रोजगार सेवक, कनीय अभियंता व संवेदक की मिली भगत से आधे-अधुरे काम कराकर अस्सी प्रतिशत राशि की निकासी कर ली गयी है. इतना सबकुछ होने के बावजूद मुखिया पर तो कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इस घोटाले का खुलासा कराने में सहयोग करने वाले उपमुखिया को गोली मारकर घायल कर दिया गया. इस बाबत अरेराज के एसडीओ शंभुशरण पांडेय से पुछे जाने पर कुछ बताने से परहेज किया. इस बीच उपमुखिया श्री सिंह ने बताया कि पंचायत के सभी योजनाओं में बड़े पैमाने पर खानापूर्ति की गयी है और राशि का दुरूपयोग किया गया है. वे बताते हैं कि इस लड़ाई में इनका व्यवसाय पुरी तरह से चौपट हो गया है. अब यही स्थिति बंजरिया प्रखण्ड के रोहिनिया पंचायत की है जहां केवल मनरेगा में लाखों का घोटाला हुआ है और अधिकारी सब कुछ जान कर भी अंजान बने हुए हैं. जानकार बताते हैं कि दर्जनों ऐसे पंचायत यहां है जहां मुखियों ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है और राशि का बंदरबाट किया है. आखिर जांच प्रतिवेदन आने व शिकायतें मिलने के बावजूद इन मुखियों पर कार्रवाई क्यों नही होती और अधिकारियों की मंशा इसके पीछे क्या है? जनता अनेक तरह की चर्चाएं कर रही है और अधिकारियों के इस तरह की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है. अब नए जिलाधिकारी अभय कुमार सिंह पर सबों की उम्मीदें टीकी हुई है. श्री सिंह इस मामले में कितनी दिलचस्पी लेते हैं और घोटालेबाज मुखियों पर कार्रवाई कैसे करते हैं यह अभी समय के गर्भ में है.■

इन्तेजारुल हक

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

07 जुलाई–13 जुलाई 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

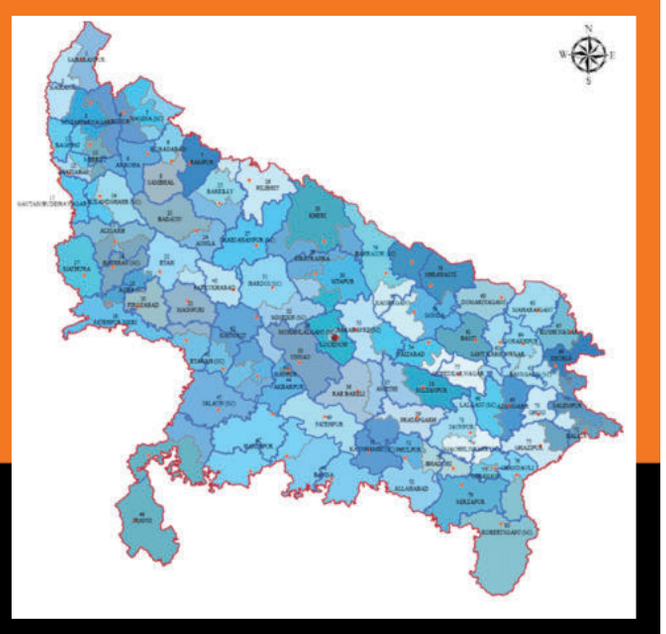

उत्तर प्रदेश– उत्तराखंड

उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र

विधानसभा में विपक्ष अब बौना नहीं दिखता

दर्शन शर्मा

उत्तर प्रदेश विधानसभा के पिछले सत्रों में विपक्ष का कोई ख़ास असर नहीं दिखा था. लेकिन इस बार विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने का भरपूर प्रयास किया. सदन में सरकार के मंत्री पूरी तैयारी के साथ सवालों का जवाब देने के लिए पहुंचे थे. अखिलेश के मंत्रियों ने अपने शासनकाल में हुए अपराधों का ब्यौरा तो दिया ही, बल्कि पूर्ववर्ती मायावती सरकार, राजनाथ सिंह सरकार तथा कल्याण सिंह सरकार तक में हुए अपराधों के आंकड़े भी पेश किए गए. इतना ही नहीं अन्य राज्यों में हुए अपराधों का बखान करते हुए यह जताने की कोशिश की गई कि उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा अपराध कम हुए हैं. इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर वाकयुद्ध चला.

विधानसभा में मुट्ठी भर सदस्यों के साथ उपस्थित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मोदी की तरह 56 इंची सीने की अवधारण के साथ पहुंचे थे. उन्होंने सपा सरकार पर शब्द बाण चलाते हुए कहा सरकार के रवैये से राज्य में 2015 में विधानसभा चुनाव निश्चित हैं. हम 2017 का इंतजार नहीं कर सकते. चूंकि सरकार के मंत्रियों और खुद विधानसभा अध्यक्ष को भी जनता ने लोकसभा चुनाव के दौरान नकार दिया है. इसलिए, सरकार सदन में नैतिक अधिकार खो चुकी है. सरकार के लोग बीजेपी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं. सरकार ने बजट में पूर्वांचल और बुंदेलखंड को कुछ नहीं दिया है. जिस आम चुनाव में वोट लेने के लिए लोकलुभावन योजनाओं के नाम पर युवाओं को गुमराह किया गया है. उन्हीं योजनाओं पर बेतहाशा पैसा खर्च करने के बाद अब 26 महीने बाद उन्हें बंद किया जा रहा है. जवाब में सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी का कहना रहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण और कार्यपालिका पर अंकुश की दृष्टि से विधायिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. उसकी गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की होती है, उतनी ही विपक्ष की भी होती है. विपक्ष के रचनात्मक सुझावों का हमेशा स्वागत होता है, लेकिन खेद है कि राज्य विधान मण्डल के बजट सत्र में पहले दिन से ही विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही है. विपक्ष को सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सत्ता पक्ष का सहयोग करना चाहिए, ताकि प्रदेश में विकास का रथ अबाध गति से आगे बढ़ता रहे. भाजपा और बसपा सदस्यों ने बजट सत्र के पहले दिन 19 जून को हंगामा कर विधानमण्डल में प्रश्नकाल नहीं होने दिया.

सदन में नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री अखिलेश के लिए ऐसा बेतुका शब्द बोल गए जिसे कार्यवाही से विधानसभा को हटाना पड़ गया. स्वामी प्रसाद की जुबान तब फिसल गयी जब उन्होंने कहा,'मुख्यमंत्री में नेताजी (मुलायम सिंह यादव) के गुण आ रहे हैं, साम दाम दंड भेद तो आ गए हैं, लेकिन उन्हें आंख दिखाना भी आना चाहिए. सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आया कि मुख्यमंत्री सब जानते हैं. अंबिका चौधरी ने कटाक्ष करते हुए कहा, दरअसल मौर्या जी का यह 'शब्द' नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री जी की 'बुआ' का दिया हुआ है. चौधरी का इशारा मायावती की ओर था. शोरशराबे के बीच मुख्यमंत्री भी खड़े होकर बोले, 'अभी तो 'बुआ' तक ही हुआ है, आप चाहो तो आगे कुछ और बढ़ा दें.

विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दलों बसपा, भाजपा और कांग्रेस ने कानून व्यवस्था के मुद्दे जोर–शोर से उठाया था. रालोद ने गन्ना किसानों के मुद्दे को उठाकर गन्ना बकाये की भुगतान की मांग की. किसानों का पेराई सत्र 2013–14 का साढ़े आठ हजार करोड़ रुपए चीनी मिलों पर बकाया है. 2012–13 का भी पूरा गन्ना मूल्य नहीं मिला. 17 चीनी मिलों की आरसी जरूर काटी गई, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई. रालोद नेता ने कहा इसी सदन में चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उनकी आवाज कानून होती थी, अखिलेश यादव क्यों कमजोर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं. सरकार की ओर से अंबिका चौधरी ने जवाब दिया कि बकाया भुगतान दिलाने के लिए सीएम ने बजट

बसपा और भाजपा नेता बिजली संकट को लेकर सरकार पर वार करते रहे. बिजली के प्रश्न पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और स्वामी प्रसाद मौर्य एक हो गए. उनका कहना था कि बिजली की समस्या सुलझाने में राज्य की अखिलेश यादव सरकार पूरी तरह असफल रही है. भाजपा के सतीश महान ने कहा कि प्रदेश में ब्लैक आउट जैसी स्थिति की नौबत आ गयी है. उन्होंने किसानों को 10 घंटे और महानगरों को 24 घंटे की बिजली आपूर्ति की मांग की.

में चार सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था की है.

सदन में नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से बोलने का प्रयास किया कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है. गुंडे और माफिया कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं. हत्या, लूट डकैती, अपहरण बलात्कार छिनैती और रोड होल्ड अप की घटनाएं बेतहाशा बढ़ी हैं. अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और महिलाएं एवं साधारण जनता असुरक्षित हैं. राजनीतिक कार्यकर्ता चुन चुनकर मारे जा रहे हैं तथा नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या की जा रही है. ऐसे में सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है. नैतिकता के नाते उसे तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए. ढाई साल के शासनकाल में जनता इस सरकार से इतनी ऊब चुकी है. लोग बहनजी के शासन काल को याद कर रहे हैं.

संसदीय कार्यमंत्री मोहम्मद आजम खान ने सवालों के जवाब में कहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा शासित मध्य प्रदेश और राजस्थान अपराधों के मामलों में तीसरे और चौथे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 25वें स्थान पर है. संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि सुनहरे सपने दिखाने वालों के शासन में अपराध अधिक बढ़े हैं. केन्द्र के एक मंत्री पर बलात्कार के गंभीर आरोप हैं. उन्होंने भाजपा और बसपा को घेरते हुए कहा कि सपा सरकार में 15 मार्च 2012 से गत 14 जून तक राज्य में डकैती की 667 घटनाएं हुई हैं, जबकि इसी अवधि में बसपा शासनकाल में 785 ,राजनाथ सिंह के समय में 825, कल्याण सिंह के समय 1667 घटनाएं घटी थीं. उन्होंने सदन को बताया सपा शासनकाल में 10673 हत्याएं हुई हैं, जबकि बसपा शासनकाल में 20891 ,राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में9369 घटनाएं घटी थीं.

मुजफ्फरनगर दंगे को अपने राजनीतिक जीवन का काला धब्बा बताने वाले आजम खान ने विधानसभा में सफाई दी कि उन्होंने मुजफ्फरनगर के किसी थाने में कोई फोन नहीं किया था. जिस चैनल ने स्टिंग आपरेशन के जरिए उन पर आरोप लगाए थे, वही लोग अब विधानसभाध्यक्ष के पीछे भागते फिर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता.प्रश्नकाल के दौरान जब शाहजहांपुर से भाजपा विधायक सुरेश खन्ना ने रामपुर की तर्ज पर विकास करवाने के लिए आजम खान से अनुरोध किया, तो आजम खां भावक होकर कहने लगे कि रामपुर नवाबों का शहर है, जहां एक जमाने में वहीं सड़क होती थी, जिस पर नवाब की ही गाड़ी निकलती थी. अनारकली को दीवार में चुनवाने की तो काल्पनिक फिल्म बनी है. रामपुर में आज भी एक तवायफ की मजार मौजूद है, जिसे वहां के नवाबों ने जिंदा दफन करवा दिया था. अगर मैंने दो चार सड़कें बनवा दीं तो आप लोगों को दर्द क्यों है. वह शहर (रामपुर) राम के नाम पर है, मुझसे जो हो सका वह किया. आपका शहर तो शाहजहां के नाम पर है. मैं सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं सह पाता हूँ. मैं आज भी मानता हूँ कि सरकारी खजाने से हुआ ताजमहल का निर्माण गलत था.

बसपा और भाजपा नेता बिजली संकट को लेकर सरकार पर वार करते रहे. बिजली के प्रश्न पर लक्ष्मी कांत वाजपेयी और स्वामी प्रसाद मौर्य एक हो गए. उनका कहना था कि बिजली की समस्या सुलझाने में राज्य की अखिलेश यादव सरकार पूरी तरह असफल रही है. भाजपा के सतीश महान ने कहा कि प्रदेश में ब्लैक आउट जैसी स्थिति की नौबत आ गयी है. किसानों को 10 घंटे और महानगरों को 24 घंटे की बिजली आपूर्ति की मांग की. स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बसपा सरकार में गांवों को 10 से 12 घंटे तथा सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली दी जा रही थी. लेकिन जैसी ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बोला, मुख्यमंत्री ने पूछ लिया कि रोजा बिजलीघर से सपा सरकार ने कम दरों पर समझौता किया था, पर बसपा सरकार ने उसकी दरें बढ़ा दी थीं. बसपा नेता झूठ बोल रहे हैं. वे अपने शासनकाल के एक भी बिजली कारखाने का नाम बताएं, जिसे चालू करवाया हो. बिजली परियोजनाएं मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में शुरू हुई थीं, लेकिन बसपा एक भी लाइन नहीं बिछा पाई थी. भाजपा नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बसपा का समर्थन करते हुए कहा कि बिजली की समस्या सुलझाने में सपा सरकार पूरी तरह असफल रही है. लोग हलकान है. बिजली कटौती के कारण उद्योगधंधे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. स्वामी प्रसाद मौर्य ने सदन में कहा कि बेसिक शिक्षा का हाल बुरा है. माध्यमिक शिक्षा में बजट काफी कम प्रस्तावित है.

बहरहाल विपक्ष अब प्रचंड बहुमत वाली सरकार से पूरी तरह लोहा लेने में सक्षम है. भाजपा की बांछें खिली हुई हैं. सदन में मुट्ठी भर सदस्यों के बावजूद वह तीखे तीर चलाने में पीछे नहीं है. भाजपाई सदस्य सदन में बढ़चढ़कर बोल रहे हैं. विपक्षी खेमा प्रबल दिख रहा है. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन सहित 73 सीटों पर कब्जा जमाने से भाजपा के भाव बहुत ऊंचे हैं. 11 विधायकों के लोकसभा में चले जाने से उसकी संख्या भले ही कम हो गयी हो, लेकिन सदन के भीतर वे सपा सरकार के छक्के छुड़ाने में पीछे नहीं हैं. यूपी विधानसभा का नजारा इस बार खासा बदला हुआ था. दशकों तक विधानसभा की गौरवशाली परंपरा को मजबूती देते आ रहे कई चेहरे नदारद दिखें. भाजपा की उमा भारती, निरंजन ज्योति, सावित्री बाई फुले और अनुप्रिया पटेल सांसद बन जाने से उत्तर प्रदेश विधानसभा से दूर हो गईं. हुकुम सिंह, कलराज मिश्र लोकसभा चले गए. लोकसभा चुनाव में मात्र पांत्र सीटें जीतने वाली सपा के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्र चलने से पहले ही अपने सभी मंत्रियों को सचेत कर दिया था कि मंत्री विपक्ष के जवाबों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तैयारी के साथ सदन में उपस्थित रहें. जो मंत्री सदन में नहीं बोल सकते वे अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे को सौंप दें. किसी प्रकार की किरकरी सरकार की नहीं होनी चाहिए.

हालांकि, विपक्षी दलों ने पहले से ही सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी थी. उनके तरकश इस बार अच्छे तीर थे. लोकसभा चुनाव में भाजपा से मात खाई पार्टियों के धुरंधर जैसे–जैसे बसपा के प्रमुख विपक्षी दल के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रदीप माथुर और रालोद के विधानमंडल दल के नेता दलवीर सिंह भी पूरी तैयारी के साथ विपक्षी लॉबी में मौजूद थे. भले ही वह अलग–अलग दलों के थे, लेकिन सरकार को घेरने वाले मुद्दे लगभग सभी के पास एक जैसे थे. विपक्ष के तूणीर में सबसे बड़ा तीर कानून व्यवस्था, महिला अपराध, बिजली, गन्ना किसान ही थे. अपनादल के विधायक आरके वर्मा भी भाजपा के रथ पर सवार होकर सत्ता पक्ष के छक्के छुड़ाने के लिए बेताब देखे गए. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

कांग्रेस में गुटबंदी चरम पर

राजकुमार शर्मा

संसदीय आम चुनाव में राज्य की पांच की पांचों सीट गंवाने के बाद भी कांग्रेस के दिग्गज नेता अपनी अंदरूनी कलह से बाहर नहीं निकल पाई है. कांग्रेस के दिग्गज सूबे की राजनीति में एक दूसरे को नीचा दिखाने, कांग्रेस को क्षति पहुंचाने का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहते हैं. विजय बहुगुणा और हरीश रावत दो गुटों में बंटी कांग्रेस में किसी को 'नेहरू–गांधी' के कांग्रेस की चिन्ता नहीं है. राज्य में आई दैवी आपदा के बाद जिस तरह मुख्यमंत्री बहुगुणा ने आपदा ग्रस्त हिमालयी जनता के हित को नकार कर अपने परिवार, चहेतों का हित साधा उसका परिणाम रहा कि उनके सभी अपने लखपति से रातों रात करोड़पति हो गए. जिस तंग हाल जनता की मदद के लिए दुनिया से सभी ने मदद का हाथ बढ़ाया था, वह मदद सही लोगों तक पहुंच नहीं सकी. नेताओं के साथ भ्रष्ट अफसरशाही ने आर्थिक मदद का बंदरबांट किया. इसकी जानकारी कांग्रेस के हरीश गुट ने कांग्रेस हाई कमान के समक्ष रख कर बहुगुणा का असली चेहरा रख दिया.

चुनाव से पहले यह समझाने का प्रयास किया कि पानी अब नाक के ऊपर बह रहा है. अब भी एक मौका है कि बहुगुणा की विदाई करके उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा जाए, तो कांग्रेस की लुटिया डूबने से बचा सकते हैं. कांग्रेस हाईकमान भी हरीश रावत के दिखाए सच को सच मान कर उनके झांसा में आ गई. चुनाव से पहले आनन–फानन में बहुगुणा की विदाई करके हरीश रावत की ताजपोशी कर दी गई. सूबे की राजनीति में हरीश रावत का एक भी पैंतरा मोदी लहर के सामने काम नहीं आया. वे अपनी हरिद्वार सीट पर पत्नी रेणुका रावत को भी नहीं जीता सके. मुख्यमंत्री के रूप में बहुगुणा ने कांग्रेस का जो बेड़ा गर्क किया था, उसे रावत लाख कोशिशों के बावजूद सही नहीं कर पाए. इन्हीं में से एक है चारधाम यात्रा. चारधाम यात्रा को लेकर पहले ही सवाल उठ रहे हैं. कोई ठोस बंदोबस्त नहीं किया गया और वहां से नरकंकाल बरामद हो रहे हैं. इन सब के बावजूद रावत

बहुगुणा की अपेक्षा अपने नेता राहुल, सोनिया का विश्वास जीतने में पूरी तरह से सफल रहे. साथ ही, उन्हीं की मर्ज़ी से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर किशोर उपाध्याय को अध्यक्ष की कुर्सी पर ताजपोशी करा ली. उपाध्याय की नियुक्ति के बाद एक बार फिर असंतुष्ट खेमा खुलकर सामने आ गया है. काबीना मंत्री हरक सिंह रावत के नेतृत्व में जो विरोधी खेमा पूर्व में सोनिया गांधी से नहीं मिल सका था, उसने पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा के नेतृत्व में दस जनपथ पर दस्तक दी है. बहुगुणा के साथ मिलने वालों में पूर्व काबीना मंत्री अमृता रावत व नरेंद्रनगर के विधायक सुबोध उनियाल शामिल थे. फरवरी 2014 से पीसीसी अध्यक्ष की नियुक्ति तक घटित राजनीतिक घटनाक्रम से बहुगुणा, अमृता रावत व सुबोध उनियाल तीनों को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान हुआ है और वे सरकार व संगठन में सीधी दखल चाहते हैं. सोनिया गांधी से हुई भेंट को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है. विधायक सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार व संगठन दोनों स्तरों पर पार्टी अध्यक्ष से विस्तार से चर्चा हुई. उनियाल के अनुसार पार्टी अध्यक्ष को राज्य में मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद सरकार व संगठन में घटित तमाम राजनीतिक घटनाओं से अवगत करा दिया गया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी पूर्व विधायक किशोर उपाध्याय की नियुक्ति के बाद विरोधी खेमे में हलचल के साथ असंतोष भी पैदा हुआ. यही वजह है कि काबीना मंत्री हरक सिंह रावत के नेतृत्व में आठ विधायक सोनिया व राहुल गांधी से मिलने दिल्ली में जुटे. यह अलग बात है कि उनकी पार्टी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष (राहुल) दोनों में से किसी से भी भेंट नहीं हो सकी. दस जनपथ में 'बहुगुणा', 'अमृता' व उनियाल की सोनिया गांधी से हुई भेंट औपचारिक भेंट नहीं कही जा सकती. तीनों ही नेता अलग–अलग कारणों से मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ–साथ पार्टी हाईकमान से नाराज बताए जाते हैं. बहुगुणा इसलिए कि फरवरी में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से अचानक हटाया गया. अमृता इसलिए कि हरीश रावत ने सतपाल महाराज के बीजेपी में जाने के तुरंत बात उन्हें मंत्री पद से हटा दिया. सुबोध उनियाल इसलिए कि वह कैबिनेट मंत्री व पीसीसी अध्यक्ष पद की दौड़ में पिछड़ गए और अध्यक्ष की कुर्सी उनके धुर विरोधी किशोर उपाध्याय को सौंप दी. ये सारे राजनीतिक घटनाक्रम इस ओर इशारा करते हैं कि तीनों नेताओं की सोनिया गांधी से भेंट शायद ही सामान्य रही हो.

जल्द ही राज्य में तीन सीटों पर उप चुनाव होने जा रहा है. राज्य के दोनों गुट एकमत होकर चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो कांग्रेस के लिए रास्ता आसान हो सकता है. हरीश की जीत के साथ ही उनकी सरकार को पूर्ण बहुमत मिल सकता है. अगर कांग्रेस की कलह नहीं थमी, तो मुमकिन है रावत के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं रहने वाला है. रावत ने प्रदेश अध्यक्ष पद पर उपाध्याय की नियुक्ति करवा कर ब्राह्मण मतदाताओं को यह संकेत देने की कोशिश की है कि रावत (राजपूत)–उपाध्याय (ब्राह्मण)दो बैलों की जोड़ी कांग्रेस का भला करने को तैयार है. ■

कांग्रेस ने की प्रत्याशियों की घोषणा

कांग्रेस ने प्रदेश में खाली तीन विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं. इनमें धारचूला विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री हरीश रावत, डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट एवं सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र से रेखा आर्य को कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया गया है. प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने भी इसकी पुष्टि कर दी है. प्रत्याशी चयन में कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी की मुहर लगने के बाद दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने तीनों प्रत्याशियों की घोषणा की. इसके साथ ही मुख्यमंत्री हरीश रावत के दो विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर भी विराम लग गया. सूबे में भारतीय जनता पार्टी की भयंकर कलह के चलते ही अब तक तीनों सीट पर अपने प्रत्याशियों की घाषणा करने में भी पिछड़ गयी है. भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो डोईवाला और सोमेश्वर की सीटें अपनी झोली में करना है. दोनों ही सीटें भाजपा के खाते में रही हैं. यदि भाजपा इन दोनों सीटों को नहीं बचा पाती है तो प्रदेश में यह स्पष्ट संदेश चला जायेगा कि अब उत्तराखंड में मोदी की लहर की हवा निकल चुकी है, जो भी लहर थी वह लोकसभा चुनाव के दौरान ही रही है. ■

बाबा रामदेव ने योग शिविर के दौरान मंच पर एक बच्चे को लाकर संभवतः अपने उत्तराधिकारी की घोषणा का संकेत दिया.

सपा सदस्य बनाओ अभियान पर निकली

रवि प्रकाश यादव

चुनावी झंझावत से निपटने के बाद समाजवादी पार्टी का ध्यान अब संख्या बल बढ़ाने की ओर गया है. सपा अपना जनाधार बढ़ाने के लिए एक जुलाई से तीस सितंबर तक (तीन माह) सदस्यता अभियान चलाने जा रही है. सपा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी पदाधिकारियों/जनप्रतिनिधियों से सदस्यता अभियान में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है. सपा उत्तर प्रदेश के साथ–साथ पूरे देश में युद्ध स्तर पर सदस्यता अभियान चलाएगी. कितने सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, इसे लेकर कोई भी साफ–साफ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन आलाकमान कम से कम दो लाख नए सदस्य बनाना चाहती है. वहीं विधान सभावार सदस्य बनाने की बात की जाए तो प्रत्येक विधानसभा से न्यूनतम तीन सौ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिस हिसाब से करीब एक लाख बीस हज़ार नए सदस्य बन जाएंगे.

गौरतलब हो, समाजवादी पार्टी के संविधान की धारा 5 (ग) के अनुसार तीन साल खत्म होने के बाद फिर सदस्यता अभियान चलाया जाता है. 2011 में 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2011 तक समाजवादी पार्टी के एक लाख दस हजार सक्रिय सदस्य बने थे. समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को गांवो और मोहल्लों में संपर्क कर प्रारम्भिक सदस्य बनाने के लिए कहा है. सदस्यता अभियान को क्षेत्रीय विधायक, पूर्व विधायक, विधान सभा के प्रत्याशी तथा विधानसभा अध्यक्ष साथ में उत्तर दायित्व के साथ चलाएंगे. बड़े–बड़े गांवो और मोहल्लों में शिविर लगाकर सदस्य बनाने का कार्य होगा. ब्लॉकवार कार्यक्रम बनाकर हैण्ड बिल छपवाकर बंटवाए जाएंगे, ताकि इस सदस्यता अभियान का अच्छा प्रचार हो सके. सदस्यता अभियान पर पार्टी के

तमाम बड़े नेताओं के अलावा सपा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव की पैनी नजर रहेगी. समाजवादी पार्टी के संविधान के अनुसार 50 प्रारम्भिक सदस्य बनाने वाले को सक्रिय सदस्य माना जाता है. प्रारम्भिक सदस्यता शुल्क 10 रुपए है. सक्रिय सदस्यता के लिए 500 रुपए का शुल्क जमा करना होगा. प्रत्येक पोलिंग बूथ से कम से कम एक सक्रिय सदस्य अवश्य बनाया जाएगा. इस तरह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 300 सक्रिय सदस्य बनाने का न्यूनतम लक्ष्य रखा गया है. पार्टी नीति के अनुसार संगठन तथा विभिन्न चुनावो में सक्रिय सदस्य ही प्रत्याशी हो सकते हैं. राज्य कमेटी, जिला/महानगर कमेटी, प्रकोष्ठो की जिला/महानगर कमेटी, विधानसभा प्रकोष्ठो की कमेटी के सभी पदाधिकारियों तथा सदस्यों, सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों, जिला पंचायत सदस्यों को पार्टी का सक्रिय सदस्य बनना अनिवार्य है. समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी कहते हैं कि सदस्यता अभियान के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि सभी जाति–बिरादरी के लोग सपा की सदस्यता ग्रहण करें, ताकि सामाजिक तानेबाने को मजबूत किया जा सके. ■

बलिया: बाढ़ से कैसे राहत मिलेगी

नवचंद्र तिवारी

मानसून दस्तक देने ही वाला है. वर्षा के साथ ही नदियों में जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती लोगों को प्रति वर्ष बाढ़ विभीषिका झेलनी पड़ती है. सरकारी कवायदों के प्रयास दावे के साथ चलते हैं. लेकिन, वस्तुस्थिति यथावत ही बनी रहती है. बलिया में दोआब (द्वाबा) के क्षेत्र प्रति वर्ष ऐसे उपजे हालातों से रूबरू होते हैं. गंगा, घाघरा, टोंस, मगई आदि नदियां उफान पर होकर भीषण तबाही मचाती हैं. सैकड़ों परिवारों का मकान, खेत आदि जल में समाहित हो जाता है और फिर वे खानाबदोश होकर असहाय सी जिन्दगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं.

जनपद का लगभग तीन हिस्सा नदियों से घिरा हुआ है. सोहांव विकास खंड के अन्तर्गत कोटवा नारायणपुर से लेकर जयप्रकाश नगर और चांद दियर तक गंगा के किनारे बसे सैकड़ों गांव बाढ़ में समा जाते हैं. गंगा के अलावा घाघरा नदी के तटवर्ती क्षेत्र बिल्थरा रोड, मनियर से लेकर रेवती विकास खंड और मांझी पुल तक टीएस बांध के किनारे बसी हजारों की आबादी अपनी तबाही का मंजर देखती है. टोंस व मगई नदी का कहर भी कम नहीं होता. राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को बचाने के लिए मझौंवा के पास बने स्परों को न तो दुरूस्त कराया गया है और न ही नोज का निर्माण हुआ है. साथ ही टीएस बांध, दूबेछपरा रिंग बांध सहित अन्य बांधे भी मरम्मत से दूर हैं. हल्दी, बैरिया, नरहीं क्षेत्र के जुलाई से लेकर सितम्बर तक बाढ़ का कहर बरपता है. लाखों की आबादी दो वक्त के निवाले, तन ढकने के लिए कपड़े और सिर छुपाने के लिए छत की तलाश में भटकती है. प्रशासनिक मदद भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान होता है. पशुओं के लिए चारे की तो बात ही जुदा है. एक आकलन व सर्वेक्षण के अनुसार चैनपुर (बिल्थरारोड) में तकरीबन 400 एकड़, गुलौरा में 150 एकड़, मठिया में 50 एकड़, विशनपुरा में 25 एकड़, महुआतर में 100 एकड़ तथा टंगुनिया दाला नाला में 10 एकड़ जमीन घाघरा में समा चुकी है. उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि 4 दशक में 80 गांव समाप्त हो चुके हैं. 40,000 एकड़ से ज्यादा भूमि नदियों में विलीन हो चुकी हैं. बिल्थरारोड (सीवर) तहसील के आखिरी छोर पर मऊ की सरहद से सटा हाहानाला, तुर्तीपार बांध के अन्तर्गत 6 गांवों में सैकड़ों किसान इस बार अपना सबकुछ खो चुके हैं. रेवती विकास खंड में उत्तरी दियरांचल के छतिग्रस्त रामबालक बाबा सेतु का निर्माण अधर में है. बाढ़ के दिनों में पुल ही एकमात्र 60 हजार से अधिक की आबादी के आवागमन का सहारा होता है. पिछले वर्ष राम बालक बाबा सेतु का एप्रोच टूटकर बह गया था. पुल को सेतु निगम ने भी रिजेक्ट कर दिया है. जिला प्रशासन ने इसे बाढ़ आने से पूर्व निर्माण कराने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है.

बैरिया तहसील के अंतर्गत इब्राहिमाबाद, नौबरार पंचायत में गांव की आबादी 18 हजार है. इसी के बगल में बिहार सीमा को स्पर्श करता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का पैतृक गांव सिताबदियारा है. यहां के ग्राम प्रधान बच्चा यादव व पूर्व प्रधान हरेन्द्र सिंह कहते हैं पिछले वर्ष भी यहां मंडलायुक्त, जिलाधिकारी सहित बाढ़ प्रखंड से जुड़े तमाम अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन समस्या जस की तस है.

बैरिया तहसील के अंतर्गत इब्राहिमाबाद, नौबरार पंचायत में गांव की आबादी 18 हजार है. इसी के बगल में बिहार सीमा को स्पर्श करता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का पैतृक गांव सिताबदियारा है. यहां के ग्राम प्रधान बच्चा यादव व पूर्व प्रधान हरेन्द्र सिंह कहते हैं पिछले वर्ष भी यहां मंडलायुक्त, जिलाधिकारी सहित बाढ़ प्रखंड से जुड़े तमाम अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन समस्या जस की तस है.

बैरिया तहसील के अंतर्गत इब्राहिमाबाद, नौबरार पंचायत में गांव की आबादी 18 हजार है. इसी के बगल में बिहार सीमा को स्पर्श करता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का पैतृक गांव सिताबदियारा है. यहां के ग्राम प्रधान बच्चा यादव व पूर्व प्रधान हरेन्द्र सिंह कहते हैं पिछले वर्ष भी यहां मंडलायुक्त, जिलाधिकारी सहित बाढ़ प्रखंड से जुड़े तमाम अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन समस्या जस की तस है.

उपजिलाधिकारी (बैरिया) शीतला प्रसाद ने बताया कि बाढ़ में राहत व बचाव के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गयी है. बाढ़ खण्ड के अधीक्षण अभियन्ता अवधराज यादव ने बताया कि गांव के लिए 17 करोड़ के परियोजना का नाम प्रस्तावित है. अधिशासी अभियन्ता पीसी यादव का कहना है कि धन का कोई अभाव नहीं है. उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष शासन से अवमुक्त 8.28 करोड़ रुपए का मरम्मत कार्य अन्तिम चरण में है. इस साल बाढ़ व कटान से बचाव के लिए 10.95 करोड़ की धनराशि भी मिल चुकी है. यादव ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर 25 दिनों में बांध को सुरक्षित करने की दिशा में चल रहें कार्यो को पूर्ण कर लिया जाएगा. विधायक जयप्रकाश अंचल ने भी यही बताया कि धन का कोई अभाव नहीं है. हालांकि नवनिर्वाचित सांसद भरत सिंह भी इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं व यथा सम्भव आश्वासन भी दिया है. उपरोक्त तथ्यों में नेता व अधिकारियों के अपने अपने बयान तथा बाढ़ व कटान पीड़ितों को सपना दिखाने के दावे हैं, लेकिन यह मौखिक ही सिद्ध होता है. प्रतिवर्ष ऐसी घोषणाओं व कथित उपाय पर प्रभावित लोगों की निगाहें टिकी होती हैं, लेकिन कई दशकों के बाद भी ये बेचारे अपने किस्मत का रोना रो रहे हैं. बाढ़ से लोगों का विकास, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक कारोबार बेपटरी हो जाता है. कटान के कारण हजारों परिवार आशियाना खुद उजाड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं और यही सिलसिला बदस्तूर जारी है. देखना होगा प्रशासन का प्रयास क्या रंग लाता है? ■

सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा उपचुनाव की रणनीति बनाने में जुटे

कांग्रेस ने रालोद-महान दल से बनाई दूरी

संदीप कश्यप

लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद सपा–बसपा और कांग्रेस सहित तमाम राजनैतिक दलों की नजरें उपचुनाव पर लगी हैं. सभी दल एकला चलो की बात कर रहे हैं. भाजपा जरूर वाराणसी की रोहनिया विधानसभा सीट अपना दल के लिए समझौते के तहत छोड़ सकती है. इस सीट पर 2012 के विधानसभा चुनाव में अपना दल की अनुप्रिया पटेल जीती थीं. बाद में मिर्जापुर से सांसद चुने जाने के बाद यह सीट उन्हें छोड़ना पड़ गई थी. भाजपा को छोड़ यूपी में वेंटिलेटर पर पड़े अन्य दल और उनके शीर्ष नेताओं को इस बात का अहसास अच्छी तरह से है कि उपचुनाव में यदि बाजी उनके हाथ लग जाती है तो आम चुनाव में मिली करारी हार का कलंक काफी हद तक धुल जायेगा. हार का कलंक धोने के लिए समाजवादी पार्टी अपनी सरकार का सहारा ले रही है. उसने अपनी चुनावी रणनीति में परिवर्तन कर लिया है. संगठन के पुनर्गठन का काम तेजी से चल रहा है. कई जिलों में नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं. वहीं अब सपा तुष्टिकरण को छोड़कर सबको साथ लेकर चलने की बात करने लगी है. आम चुनाव भले ही कांग्रेस ने संगठनात्मक अव्यवस्था के साथ लड़ा, लेकिन उपचुनाव कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर अपने आप को मजबूत करके लड़ना चाहती है. हार के बाद कांग्रेस में राहुल गांधी बैकफुट पर चले गए हैं. यूपी के उपचुनाव कांग्रेस एक बार फिर सोनिया गांधी के सहारे लड़ सकती है. वहीं यूपी के चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री की भी वापसी हो गई है. कांग्रेस अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी. यह संकेत खुद कांग्रेस के यूपी प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने दिए. उन्होंने कहा कि फिलहाल उम्मीद यही है कि हम सभी सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगे. अपने दो दिनों के दौरे पर लखनऊ पहुंचे प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की नब्ज भी टटोली. गौतलब हो, लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकदल व महान दल के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन उसे इसका कोई फायदा नहीं हुआ. इसी वजह से उसका महान दल और रालोद से मोहभंग हो गया. मिस्त्री ने

सभी विधायकों और नेताओं/कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि विधायक सदन के अंदर सरकार को घेरने की, तो कार्यकर्ता सड़क पर प्रदेश की सपा और केन्द्र की भाजपा सरकार को घेरने में कोई कोर कसर न छोड़े. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि जिला कमेटियों का गठन 25 जुलाई तक हो जाएगा. जहां पर सर्वसम्मति से जिला कमेटियों का चयन हो जाएगा, वहां चुनाव नहीं कराए जाएंगे. विवाद वाली स्थिति में ही चुनाव कराए जाएंगे. मिस्त्री ने माना कि जिला व शहर कांग्रेस कमेटियों में कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उन्हें बैठाने से नुकसान ज्यादा हुआ है. इससे गुटबाजी और बढ़ गई. हालांकि जिलों की गुटबाजी जिले के कांग्रेस नेतृत्व को ही खत्म करनी होगी. उसमें प्रदेश का नेतृत्व कोई दखल नहीं देगा.

यूपी का उपचुनाव कांग्रेस एक बार फिर सोनिया गांधी के सहारे लड़ सकती है. वहीं यूपी के चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री की भी वापसी हो गई है. कांग्रेस अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी. यह संकेत खुद कांग्रेस के यूपी प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने दिए. उन्होंने कहा कि फिलहाल उम्मीद यही है कि हम सभी सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगे.

उधर, बसपा समाजवादी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर कठघरे में खड़ा कर रही है. वहीं, कांग्रेस को कोस–काट कर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उनका कांग्रेस से कोई लेना–देना नहीं रह गया है. बात राष्ट्रीय लोकदल की बात कि जाये तो इसके नेता तो दो कदम आगे बढ़कर विधानसभा तक में यह कहते फिर रहे हैं कि तुष्टिकरण की नीति के कारण ही समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का आम चुनाव में बुरा हाल हुआ है. रालोद इसलिए उपचुनाव को लेकर तेजी दिखा रहा है, क्योंकि जिन 12 विधान सभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें से चार सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं जिसे रालोद अपना गढ़ मानती है. वैसे मैनपुरी की एक लोकसभा सीट पर भी उप–चुनाव होने हैं, लेकिन सभी दल दबी जुबान से यह मान कर चल रहे हैं कि मुलायम के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई यह सीट समाजवादी पार्टी के ही खाते में जाएगी. दो जगह से चुनाव लड़ने वाले मुलायम ने मैनपुरी संसदीय सीट से इस्तीफा देकर आजमगढ़ संसदीय सीट अपने पास रखी थी. वहां जिन विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, उसमें लखनऊ पूर्व, कैराना, बिजनौर, ठाकुरद्वारा, नोएडा, सहारनपुर, चरखारी, हमीरपुर, निघासन, बलहा, सिराथू और रोहनिया सीट शामिल हैं. ■

नर कंकाल ने रावत सरकार की कलई खोली

रेवू शर्मा

केदारनाथ क्षेत्र में लगातार मिल रहे नर कंकाल ने सूबे की हरीश सरकार की कलई खोल दी है. नर कंकालों के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी में है. आपदा के एक साल बाद भी मिल रहे नर कंकाल को लेकर सियासत कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों की ओर से युद्धस्तर पर जारी है. किसी की भी नज़र अब तक इस बात पर नहीं गयी है कि जिन लोगों के नर कंकाल मिल रहे हैं वे कहां के रहने वाले हैं और कौन है.

केदारनाथ घाटी में मिल रहे नर कंकालों की सूचना फैलते ही देश–विदेश, अन्य प्रांतों से इन पर्यटकों के परिजन प्रदेश पहुंचने लगे हैं, जो एक साल पहले आयी त्रासदी में लापता हो गये थे. अपनों को खेजने के लिए आने वाले परिजनों को किसी तरह की कोई मदद राज्य सरकार द्वारा मुहैया नहीं करायी जा रही है, जिससे परिजनों में बेहद नाराजगी है. इस हादसे में जापान का एक अप्रवासी दंपती एक वर्ष से लापता है. केंद्र या उत्तराखंड सरकार अभी तक दंपती के परिजनों को मुआवजा तो दूर 'मृतक प्रमाणपत्र' तक नहीं दे सके हैं. अमेरिका और जापान से दंपती के पुत्र व पुत्री (एनआरआई) तीन बार यहां के चक्कर लगा चुके हैं. उधर जापान में अपने माता–पिता के मृतक होने का प्रमाणपत्र पाने में विफल परिजनों को सिटिजन–टैक्स, हेल्थ–टैक्स व अन्य कर देने पड़ रहे हैं. उत्तराखंड त्रासदी की पहली बरसी पर जापान से आए अजीत ने 'मीडिया' को बताया कि एक वर्ष पूर्व इनके अप्रवासी भारतीय पिता भगवान सिंह (68वर्ष) और माता नारायणी देवी (65वर्ष) भारत आए थे और दिल्ली से टैक्सी लेकर 14 जून को उत्तराखंड (केदारनाथ) तीर्थाटन गए थे. त्रासदी के बाद जब उनका कोई अता–पता नहीं लगा और जापान दूतावास से संपर्क करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली तो अजीत अपने परिवार के साथ भारत आए. दिल्ली व उत्तराखंड सरकार में प्रार्थनापत्र देकर अपने माता–पिता के त्रासदी में मारे जाने की संभावना जताई. दिल्ली सरकार के कापसहेड़ा जिलाधीश कार्यालय में उन्हें बताया गया कि वे जापान चले जाएं और कुछ समय बाद

यहां से मृतक प्रमाणपत्र व मुआवजा आदि लेने की प्रक्रिया शुरू करें. अजय ने बताया कि उनका टोकियो में होटल एवं रेस्टोरेंट का कारोबार होने के कारण वह चले गए और अमेरिका में रहने वाली उनकी अप्रवासी बहन नीतू अपने परिवार के साथ भारत आई. वह भी एक महीने तक भटकने के बाद निराश होकर चली गईं. भारत या उत्तराखंड सरकार कुछ भी बताने में विफल रही. इतना ही नहीं, अजय ने बताया कि मम्मी–पापा की जुदाई में मेरी बहन मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई है, जिसका उपचार अमेरिका में चल रहा है. अजय का कहना है कि उन्हें अब कोई मुआवजा नहीं चाहिए और न ही वे मुआवजा के लिए पत्र व्यवहार कर रहे है या यहां बार–बार आते हैं. उनके आने का मुख्य मकसद है मृत्यु प्रमाणपत्र हासिल करना. क्योंकि जापान का अनिवार्य नियम है कि किसी के मृतक होने की सूचना देना उसके परिजनों का संवैधानिक दायित्व है. इसी तरह बीते दिनों फैजाबाद से आये मनमोहन शुक्ल ने बताया कि उनके परिवार के दो लोग आपदा के दौरान फंस गए थे, जिनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया. इस समय भी लापता लोगों को खोजने की कोशिश की गयी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पायी. अब तो नर कंकाल निकल रहे हैं, जिससे यह पता चल पाना काफी मुश्किल है कि मिल रहे नर कंकाल किसके हैं. शुक्ल के मुताबिक इस बारे में शासन के अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है. शुक्ल का कहना है कि एक साल पहले यदि शवों की खोज की गयी होती तो शव नर कंकालों में तब्दील नहीं हुए होते.

नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश एंव फटकार के बाद सूबे की सरकार की आंखें खुली हैं. सरकार का अब कहना है कि मिलने वाले नरकंकाल की फोटो के साथ डीएनए सैंपलिंग की जा रही है. फिर उनका संस्कार किया जा रहा है. इस बारे में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट का कहना है कि नर कंकालों के मिलने के बाद भी कांग्रेस की सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है. भट्ट का कहना है कि नर कंकालों को लेकर भाजपा कोई राजनीति नहीं कर रही है. भाजपा तो चाहती है कि नर कंकालों को खोजने के काम में एक बार फिर से सेना को लगाया जाए, ताकि शेष बचे नर कंकालों को निकाला जा सके और कम–से–कम सफाई की प्रक्रिया भी पूरी की जा सके. भट्ट का कहना है कि अब बरसात भी शुरू होने को है और ऐसे में नर कंकालों को खोजना भी कठिन कार्य होगा. सरकार कोई सुध नहीं ले रही है. उधर प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि सरकार नर कंकालों को लेकर बेहद गंभीर है. भाजपा जबरन 'नर कंकाल' की राजनीति कर रही है. दरअसल मौसम और केदारनाथ की भौगोलिक हालात ही इस तरह के हैं जिससे नर कंकालों को खोजने में कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही है. आपदा के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी ने आपदा पीड़ितों को मदद का हाथ बढ़ाया था. अब प्रधानमंत्री बन कर मोदी केदारनाथ की आपदा को लेकर खासे चिंतित हैं. प्रधानमत्री मोदी का केदारनाथ पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है.

हिमालय में आई दैवी आपदा के एक साल बाद भी प्रदेश सरकार चार–धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों के मन से आपदा का खौफ हटाने में नाकाम रही है. इसका अंदाजा इस साल जून तक चार–धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़े से लगाया जा सकता है. पिछले वर्ष आपदा से पहले 16 जून तक जहां चार धाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या तेरह लाख के करीब थी. वहीं इस वर्ष अभी तक यात्रियों का आंकड़ा बमुश्किल दो लाख तक पहुंच रहा है. इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि चार धाम यात्रा को सुचारू करने के प्रदेश सरकार के दावों में कितनी हकीकत है. उत्तराखण्ड प्रदेश में पर्यटन को जीविका का मुख्य आधार माना जाता है. मुख्यतः पांचधाम (हेमकुण्ड सहित) यात्रा पर ही यहां का पर्यटन टिका हुआ है. यहां हर वर्ष लाखों देशी–विदेशी श्रद्धालु व पर्यटक आते थे, पिछले वर्ष उत्तराखंड में आई भयंकर आपदा ने यात्रियों के पैर थाम लिए और उनकी संख्या पर कम होने लगी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

अजय कुमार , लखनऊ ब्यूरो प्रमुख कार्यालय का पता : जे–3/2 डॉलीबाग़, हजरतगंज, लखनऊ–226001, फोन –(0522) 2204678/09415005111